In view of these deevlopments, the Minister for Health should make a statement on these issues.

(v) FLOODS IN KERALA.

SHRI A. A. RAHIM (Chirayinkil): Mr. Speaker, Sir, I would like to bring to the notice of this House, the Prime Minister and the Finance Minister the havoc caused by the unprecedented floods in Kerala in the last fortnight. It has already claimed 42 human lives. Over 14,000 houses have been destroyed and over 22,000 damaged. Crop loss has been extensive. Eight of the eleven Districts of the State have been badly affected. The State Government have made a preliminary estimate of the loss at over Rs. 20 crores. They have already ordered some relief measures. Government of India should urgently consider extending interim Central assistance pending a final assessment by a Central Study team who may be sent to the State immediately.

12.26 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 1980-81—*contd.*

MINISTRY OF HOME AFFAIRS—*Contd.*

MR. SPEAKER: Now we start with the discussion on the demands of the Ministry of Home Affairs. Shri Sukhadia.

श्री मोहन लाल सुखाड़िया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जिस मांग पर हम यहां विचार कर रहे हैं वह देश के लिए बहुत महत्व रखती है । मैं समझता हूं सभी इस बात को जानते हैं कि चाहे विकास का काम हो चाहे देश की रक्षा का सवाल हो, चाहे मनुष्य के शांति के साथ जीवन-यापन करने का प्रश्न हो यह अत्यन्त आवश्यक है कि देश के अन्दर कानून और व्यवस्था ठीक तौर से चले । आज सुबह के अखबारों में यह समाचार पढ़ने को मिले कि आसाम में जो आन्दोलन चल रहा था उसकी हैड लाइन्स थीं कि वह सस्पेंड किया गया । जब उसको विस्तार से देखा तो ऐसा मालूम होता है कि एक तरह से यह पार्शियल सस्पेंसन है क्योंकि पूरे तौर से तो सस्पेंशन किया नहीं है । वहां से कूड नहीं आने दिया जाएगा, ब्लाकेड जारी रहेगा, बैम्बू और टिम्बर वहां से नहीं आने दिया जाएगा, यह उन्होंने साथ ही में कहा है । इसका मतलब यही होता है कि पूर्ण रूप से नार्मलाइज करने की बात नहीं है । लेकिन मैं समझता हूं फिर भी यह एक ठीक दिशा के अन्दर कदम उठाया गया है और इसके डीटेल्स में आशा करता हूं कि प्रधान मंत्री जी और जो आसाम के आन्दोलन से सम्बन्धित व्यक्ति हैं वे मिल कर के निकालेंगे जिससे कि इस समस्या का हल निकाला जा सके । लेकिन आज के अखबार के अन्दर ही यह पढ़ करके भी आश्चर्य हुआ कि हमारे इसी सदन के माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नांडीज ने कहा कि इस आन्दोलन को चालू रखने के अन्दर श्रीमती इंदिरा गांधी की दिलचस्पी है और उनका वेस्टेड इन्टेरेस्ट इस बात के अन्दर है कि यह आन्दोलन चालू रहे, किसी तरह से इसको समाप्त न किया जाय । यह पढ़ कर के आश्चर्य होता है कि आखिर आज देश के अन्दर जो हुकूमत चलाने वाली प्रधान मंत्री है उनकी क्या दिलचस्पी हो सकती है देश के एक सीमावर्ती प्रदेश के अन्दर इस प्रकार के आन्दोलन के चलने देने में जिसमें इन बातों के समाचार मिल रहे हैं कि कुछ विदेशी ताकतें भी इस आन्दोलन का लाभ उठाना चाहती हैं, कुछ साम्प्रदायिक ताकतें इस आन्दोलन को और दिशा के अन्दर ले जाने की कोशिश में लगी हुई हैं । मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बात करने और बार बार वहां जाकर लोगों से मिल जुल कर अपनी बात कहने से ऐसा संकेत होता है कि उनकी दिलचस्पी वास्तव में इसमें नहीं है कि यह आन्दोलन समाप्त हो बल्कि वह दोषारोपण करके चाहते हैं कि इसका राजनैतिक लाभ ज्यादा से ज्यादा उठायें। आज मैं समझता हूं कि सारा देश इस बात को पसन्द करेगा कि इस आन्दोलन का शांतिपूर्ण हल निकले । मैं ऐसा मानकर के चलता हूं कि अगर इस आन्दोलन से सम्बन्धित व्यक्ति साम्प्रदायिकता की भावनाओं को दूर रख करके और देश की एकता को सामने रखते हुए बातचीत करेंगे तो इसका हल निकलना कोई मुश्किल बात नहीं है । निश्चित तौर से इसका हल निकल सकता है । लेकिन बातचीत के अन्दर अगर साम्प्रदायिकता का पुट रहेगा या बातचीत के अन्दर पीछे से कुछ विदेशी ताकतें यह काम करती रहेंगी कि बातचीत सफल नहीं हो पाएं तो आज कह नहीं सकते कि इसका क्या परिणाम होगा । मेरा कहना है कि अगर उनको खुद को राष्ट्र के हित में देखने और राष्ट्र की प्रगति की दृष्टि से सोचने और फैसला करने के लिये छोड़ा जाएगा तो इसका हल निकले, सभी इस बात को पसंद करेंगे । कुछ दिनों पहले मैं राजस्थान गया तो जयपुर के अन्दर जो रामनिवास बाग है उसके अन्दर लिखा हुआ था आसाम बचाओ, विदेशियों को देश से निकालो, उदयपुर के चारों तरफ दीवारें जैसे चुनाव चल रहा हो

[श्री मोहन लाल सुखाड़िया]

और चुनाव में वोट मांगने के लिए अलग अलग लिखा जाता हो, उस तरह विद्यार्थी परिषद् की तरफ से सब जगह लिखा गया कि आसाम बचाओ, देश बचाओ । कोई इसमें ऐतराज नही हो सकता, हर एक चाहता है कि आसाम बचाया जाना चाहिये, आसाम देश में रहना चाहिये और उसके साथ साथ वहां पर जिनको विदेशी समझा जाय उनको वहां से निकाला जाना चाहिये, इसके बारे में देश की प्रधान मंत्री इंदिरा जी ने भी इस बात की इच्छा बराबर व्यक्त की यह सबको मालूम है कि उन्होंने विरोधी पार्टी के सदस्यों और नेताओं से मिल कर पहले 1971 वाली बात कही । जब 1971 वाली बात कही गई उसके बाद प्रश्न उठने लगा कि गांधी पीस फाउन्डेशन की तरफ से जो प्रस्ताव आये हैं उसके आधार पर बातचीत की जाय । तब भी प्रधान मंत्री जी ने कहा कोई आधार न रखा जाय, 1971 को भी हम इंसिस्ट नही करते, न किसी और बात को रखा जाय, बिना प्री-कडीशन के बातचीत शुरू की जाय । मैं समझता हू उनकी तरफ से तो हमेशा दरवाजा खुला रखा गया है । अगर इसका हल ठीक तौर से निकल सकता है तो उसको निकालने के लिए प्रयत्न किया जाय । मेरे ख्याल से ठीक शुरुआत हुई है और आशा है इसका ठीक परिणाम सामने आयेगा ।

इस सदन में चिन्ता व्यक्त करना स्वाभाविक ही है अगर हरिजनों पर एट्रामिटीज की बात हो, महिलाओं पर एट्रासिटीज की बात हो या ट्राइबल्स पर एट्रासिटीज की बात हो । लेकिन इन चीजों के सम्बन्ध में मैं चाहता हूं यह सदन जो कि सारे देश का प्रतिनिधित्व करता है, निश्चित तौर से इस बात पर विचार करेगा, गहराई के साथ विचार करेगा यह सारे कारण क्यों पैदा हुए, कबसे स्थिति बिगड़ने लगी, विशेष तौर से कहा ज्यादा बिगड़ने लगी ? मैं समझता हू इस पर अगर गहराई से विचार किया जायेगा तो इस बात को मानना होगा कि जून, 1977, जब जनता पार्टी के हुकूमत आई उसके बाद विविध कमीशन का मुकर्रर किया जाना, सरकारी कर्मचारियों को लपेटा जाना, और उनमे डि-मार्लाइजेशन की स्थिति का पैदा किया जाना, सरकारी अफसरों ने अगर कोई काम किया, फेमिली प्लानिंग के सम्बन्ध में या ला ऐंड आर्डर अथवा किसी दूसरे क्षेत्र में तो उनके ऊपर लगातार इस बात के प्रयत्न किए गए जिसकी वजह से उसी जमाने में कई प्रदेशो में ला एंड आर्डर की स्थिति ज्यादा खराब होने लगी। मुझे क्षमा करें अगर मैं यह कहू कि आज अगर सदन मे ला ऐंड आर्डर खराब होने की चर्चा चलती है तो वह किन स्थानों के बारे में ज्यादा चलती है ? क्या इस बात से इन्कार किया जा सकता है कि उन्ही प्रदेशों के बारे में ज्यादा चर्चा की जाती है जहा या तो लोकदल के प्रभुत्व वाली सरकारें थी या जनसंघ के प्रभुत्व वाली सरकारें थी ? उन्ही राज्यों के सम्बन्ध में ज्यादा से ज्यादा चर्चाएं इस सदन में होती हैं – वह चाहे बिहार हो, यू०पी० हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो या दिल्ली हो। खास तौर से इन्हीं प्रदेशों के बारे में ज्यादातर बातें यहां पर क्यों आती हैं ? इसका कारण यह है कि वहा पर जातीयता का विष घोला गया, सर्विसेज का डिमार्लेजाइजेशन किया गया, जानबूझ कर धर्म की बातें सामने लाई गई । सर्विसेज के बारे में मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि पुलिस और दूसरे विभागों के कर्मचारियों के हजारों ट्रासफर्स इस आधार पर किए गए कि अमुक धर्म का, अमुक साम्प्रदायिक तत्वों का साथ देगा या नही देगा – इन बातों को लक्ष्य में रखकर ट्रांसफर्स करके सर्विसेज का डिमार्लेइजेशन किया गया । जातीयता के आधार पर अनेक लोगों को इधर से उधर किया गया । उसी जातीयता के परिणामस्वरूप आज बहुत से क्षेत्रों में यह बाते देखने को मिलती है और आज तत्काल इन चीजों में परिवर्तन लाना आसान नही है ।

यहा पर बहुत से ऐसे मामले उठाये जाते हैं जो कि स्टेट सब्जेक्ट से सम्बन्ध रखते है । प्रदेशों में उनको उठाया जाना चाहिये, प्रदेशों में जो नयी सरकारे बनी है उन्हें ही इसे ठीक करना होगा, सारे हालात जो बिगड़े हैं उनको ठीक रास्ते पर लाना होगा । लेकिन कई माननीय सदस्य कहेंगे कि फलानी जगह हरिजनो पर अत्याचार हुआ है, होम मिनिस्टर साहब क्यो इस्तीफा नही दे देते है लेकिन क्या यह किसी से छिपा है कि जब यू०पी० मे लोक दल की सरकार थी और वहा पर नारायणपुर में दुःखद और शर्मनाक घटना घटी थी तब वहा पर प्रधान मंत्री के जाने की बात के ऊपर विरोध पक्ष की ओर से कितनी आवाज उठाई गई थी । क्या वहा पर अत्याचार नही हुआ था । आज एक एक घटना को लेकर आवाज उठाई जाती है । लेकिन उस वक्त कोई आवाज नही उठाई गई थी । अब कही पर दो हत्याये होती है तो आवाज उठाई जाती है लेकिन त्रिपुरा में, यदि कहा जाये तो, जो नरसंहार हुआ उसको लेकर क्या उस पक्ष की ओर से यह आवाज उठाई गई कि वहां की सरकार को बरखास्त किया जाना चाहिये ? असाम के एजिटेशन के सम्बन्ध मे, विरोध पक्ष, की एक राय नहीं है । एक तरफ कहेंगे कि अल्प संख्यकों का प्रोटेक्शन होनी चाहिये माइनोरिटीज का, लिंग्विस्टिक माइनोरिटीज का, रीलीजियस माइनोरिटीज का, ठीक कहा जाता है कि उनका प्राटेक्शन होना चाहिये । साथ-साथ जब मजबूती के साथ काम करने की बात आती है, तो यह भी कहा जाता है कि मूवमेंट को क्रश करने के लिए मजबूती के साथ काम नहीं किया जाना चाहिये । प्रश्न यह है कि इसका क्या रास्ता हो सकता है ? एक कहता है कि गांधी पीस फाउन्डेशन पर चलो, कोई कहता है कि 1971 के कटाव के प्वाइंट के ऊपर चलो और दूसरे कहते हैं कि कन्डीशन्स को सामने रख कर चलो, सारी

जिम्मेदारी सरकार पर है विरोधी पक्ष के लोग केवल इन चीजों का लाभ उठाना चाहते हैं ।

अध्यक्ष जी, सच बात तो यह है कि लॉ एंड आर्डर काफी खराब हुआ था और उसके कई कारण थे, जिसकी वजह से आज इस पक्ष में बैठने वालों को बड़ा भारी बहुमत प्राप्त हुआ । मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस सदन की शुरूआत से लेकर आजतक जो विषय, जो कि स्टेट्स के अन्दर डिसकस किये जाने चाहिएं, रोज यहां पर उठाये जाते हैं, बिना मकसद के नहीं, बल्कि उसके पीछे निश्चित तौर से यह भावना है कि किसी तरह से लोगों में अशान्ति पैदा की जाय, सर्विसेज के अन्दर डिमोरलाइजेशन पैदा किया जाए और इस तरह के हालात पैदा किये जायें कि जिनसे लाभ उठाकर अन्ततोगत्वा देश के अन्दर आक्रोष और अराजकता पैदा हो । इसलिए मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा, जैसा हमारे दिल्ली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि आज देश इस बात का इन्तजार करता है, देश इस बात की आशा करके चलता है और सोच-समझकर लोगों ने वोट दिया है, कि देश में शान्ति स्थापित होगी । यह बात भी इंदिरा जी के लिए कही गई कि वे देश के अन्दर मजबूत शासक हैं और कानून और व्यवस्था कायम की जाएगी । इसलिए मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो संशोधन आवश्यक हो, वर्तमान कानून में या नया कानून लाने की आवश्यकता हो, तो वह भी लाइये और देश के अन्दर कानून और व्यवस्था को मजबूती के साथ स्थापित कीजिए, देश उसका स्वागत करेगा । लेकिन केवल कानूनी बहस और चर्चाओं का देश स्वागत नहीं करेगा । क्योंकि लोगों ने दिल खोलकर हमें वोट दिया है और वोट देकर हमें संसद् में भेजा है ।

आज उनसे चर्चा कीजिए, तो वे कह सकते हैं कि क्यों नहीं देश के अन्दर सारी चीजें ठीक हुईं ? पहले से बहुत अन्तर हुआ है, कम्यूनल टैनशन के इन्सीडेंट्स कम हुए है, स्टूडेंट अनरेस्ट आज पहले के मुकाबले में कम हैं, लेकिन मैं यह मानकर नहीं चलता कि आज सारी स्थितियां ठीक हो गई है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है । अभी बहुत कुछ करना शेष है और उनके कारणों के अन्दर जाने की सख्त आवश्यकता है और मेरा आपसे निवेदन है कि उन कारणों के अन्दर जाकर सारी चीजों को दूर करें । उन कारणों में सोशियल कारण हैं, इकोनामिक कारण हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कारण हैं, इन सबको एक-एक करके देखने की आवश्यकता है ।

माननीय अध्यक्ष जी, देश के एक भाग में असम आन्दोलन चलता है, कभी त्रिपुरा में बात उठती है, कभी मिजोरम की बात उठती है, कभी नागालैण्ड की बात उठती है, कभी झारखंड की बात उठती है, और कभी उत्तराखण्ड की बात उठती है और कभी तमिलनाडु के अन्दर वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा यह आवाज उठाई जाती है कि तिरुपति तमिलनाडु का हिस्सा होना चाहिये । ये अलग अलग मांगें देश के अन्दर उठाई जा रही हैं, इन सबके पीछे अपनी राजनीतिक स्थिति को ज्यादा मजबूत करने की भावना है जिसके कारण कमजोरियां आ रही हैं । इन सवालों को उठाकर देश के अन्दर तनाव का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं । इस वातावरण को पैदा करने की कोशिश के बारे में मैं समझता हूं कि गृह मंत्री जी के पास अलग-अलग जगहों से सूचनायें आती होंगी, इसलिए उन पर तत्काल जल्दी से जल्दी कार्यवाही करने की आवश्यकता होगी ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में कई आन्दोलन हुए है, लेकिन आसाम के आन्दोलन के बारे में मैं यह नहीं कहता कि वहां के विकास के सम्बन्ध में, और बहुत सी चीजों के लिए कुछ न करें । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो स्थिति पैदा हुई है, उनके एजीटेशन को ससपेंड करने वाली बातों को लेकर, वह तो प्रधान मंत्री जी के और उनके बीच की बात है, उसके विस्तार में मैं नहीं पड़ना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि जिस आन्दोलन के अन्दर साम्प्रदायिक पुट मौजूद है, वहां पृथकतावादी स्लोगन लग रहे हों, क्या सरकारी सर्विसेज भी उसकी पार्टी हो सकती है या कोई भी उसका हिस्सेदार हो सकता है, जो उन चीजों को उठाकर चलते हैं कि पुलिस वहां पर काम न करे, वहां के कर्मचारी काम न करें, यह कैसे चल सकता है । जो वाजिब बात है, उसके बारे में फैसला कीजिए । वहां समझौता हो, तो उचित बात है, न हो, तब भी मैं समझता हूं कि प्रशासन तो चलना ही चाहिये, राज तो वहां पर चलना ही चाहिये, यह चीज सामने नहीं होनी चाहिए कि शासन नहीं चल पा रहा है । आन्दोलनकारी यदि अपनी बातों को रखना चाहें, तो वे शान्ति से रख सकते हैं, आन्दोलन के रहते हुए, अपनी मांगों को रख सकते हैं । लेकिन पृथकतावादी ताकतों को किसी भी प्रकार से बढ़ावा मिलता है तो यह छूत की बीमारी की तरह से काम करने वाली चीज होती है, जिसको मैं समझता हूं तत्परता के साथ रोका जाना देश के हित के लिए अत्यन्त आवश्यक है ।

अभी मैंने बतलाया था कि कुछ स्टेट्स में कमीशन या दूसरी आर्गेनाइजेशन के जरिए डीमोरलाइजेशन का वातावरण पैदा किया गया है । कुछ माननीय सदस्यों को मेरी यह बात पसन्द नहीं आयी, लेकिन मैं निवेदन करूं कि यह सच्चाई है कि उनके कारण पुलिस को आन्दोलन करना पड़ा, हड़तालें हुईं, वे सड़कों पर नारे लगाते हुए निकले, एक जगह नहीं, अलग-अलग स्टेट्स के अन्दर ऐसा हुआ है । कई जगह यह चीज नहीं हुई है, लेकिन यह चीज भी सच है कि पुलिस के विरुद्ध गोलियां चलानी पड़ी । आज जिस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है, इसकी जिम्मेदारी किस पर है, वह किसका जमाना था जिसके कारण सरकार का शासनतन्त्र कमजोर हुआ ?

[श्री मोहन लाल सुखाड़िया]

एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि ट्राइबल्स के लिए सब जगहों पर इन्टीग्रेटेड ब्लाक्स बनाये गये हैं । यह ठीक है, लेकिन होम मिनिस्ट्री ध्यान दे कि राजस्थान में 30-35 लाख ट्राइबल्स हैं, इसी तरह से मध्य प्रदेश उनके साथ जुडा हुआ, गुजरात जुड़ा हुआ और यह सारा एक ट्राइबल बैल्ट बनता है, जो बहुत पिछड़ा हुआ है । मैंने आपकी रिपोर्ट पढ़ी, उससे मालूम हुआ कि जहां पर कम आबादी है, वहां तो इन्टीग्रेटेड ब्लाक्स ज्यादा हैं, लेकिन राजस्थान में जहां आबादी बहुत ज्यादा है, वहां इन ब्लाक्स की संख्या कम है । इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नही है, मैं चाहता हूं कि मंत्रालय इस पर गम्भीरता से विचार करे ।

एक चीज मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश के अन्दर बहुत सी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जैसे, बी० एस० एफ०, सी० आर० पी०, आसाम राइफल्स, सी० आई० एस० एफ०, आदि । क्या यह गम्भीरता से विचार करने का विषय नहीं है कि इतनी संख्या मे अलग-अलग डिफरेंट पैटर्न्स पर उनको कायम करके काम लिया जाय । हो सकता है--आप यह कहें कि इनके अलग-अलग काम हैं या इनके विशेष काम हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि इनके लिए अलग-अलग ट्रेनिंग सेन्टर्स बने हुए हैं, और उन पर काफी व्यय हो रहा है । पिछली दफा जब हम डिफेन्स की मांगों पर विचार कर रहे थे तो सभी सदस्यों ने यह राय जाहिर की थी कि आर्मी के लोग 35-36 साल की आयु के बाद रिटायर हो जाते हैं और यह समस्या पैदा हो जाती है कि रिटायर होने के बाद उनको कहां काम दिलाया जाय । क्या यह उपयुक्त नही होगा कि जैसे बी० एम० एफ० है, जो आप के बोर्डर्स की सिक्योरिटी का काम करता है और जिसमें हम नये रिक्रूट्स को भरती करके ट्रेनिंग देते हैं और जो 58 वर्ष की आयु तक नौकरी में रह सकते हैं, उसमें आर्मी के रिटायर हुए लोगों को नौकरी में लिया जाय । मैं राजस्थान के बारे में जानता हू, जब 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई तो उसका पहला अन्ट वहां चौकियों पर बैठे हुये आर० ए० सी० के जवानों पर पड़ा और उसके बाद यह फैसला हुआ कि स्टेट्स में बार्डर आर्म्ड-कांस्टेबुलरी एक होनी चाहिये जो केन्द्र के अधीन हो । जब आप केन्द्र के अधीन इस व्यवस्था को रखना चाहते हैं तो जो 35 और 36 साल में रिटायर हो कर आते हैं, जिनको पहले से ही ट्रेनिंग मिली हुई होती है, जिनकी अच्छी बैक ग्राउन्ड होती है, उन को बी० एस० एफ० में भरती किया जाय । इस तरह से नये रिक्रूट्स की ट्रेनिंग पर जो खर्चा करना पड़ता है, वह कम हो जाएगा और उन का रिटायरमेंट जल्दी न हो कर 58 वर्ष में होगा और इस तरह से उनके लिए रोजगार ढूंढने की समस्या भी हल हो जायगी । एक लाभ यह भी होगा कि इस तरह की इन्टीग्रेड सर्विस बनाने से डिफेन्स और पैरा-मिलिट्री फोर्स के बीच लायजा ठीक तरह से स्थापित हो सकेगा । इस तरह की व्यवस्था से आर्मी में जो लोग हैं उनके अन्दर असन्तोष कम होगा । आप चाहे जितने एक्स-सोल्जर्स बोर्ड बना लें, डिस्ट्रिक्ट बोर्डस बना लें, जहां तक एम्प्लाईमेंट की पासिबिलिटी का सम्बन्ध है, जो लोग रिटायर हो कर आते हैं उनको जमीन देने की एक सीमा समाप्त हो चुकी है, यह चीज सैचुरेशन प्वाइन्ट पर पहुंच गई है, अब उनको ज्यादा जमीन देना सम्भव नही हैं, नौकरियों के मामले में दिक्कत होती ही है, ये सब चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं । जहां तक मैं समझता हूं--डिफेन्स के प्वाइन्ट अन्फ व्यू से भी इस तरह की व्यवस्था करने से लायजा ज्यादार ठीक होगा और सब लोग आसानी से काम कर सकेंगे, एक-दूसरे की बातों को समझ सकेंगे और एक अच्छी आर्मी के रूप में काम कर सकेंगे ।

मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्री जी इन सारी चीजों पर गम्भीरता से विचार करेंगे ।

SHRI RAM JETHMALANI (Bombay North West): Mr. Speaker, Sir, we are debating the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs.

One test of determining the adequacy of the performance of the Ministry, perhaps, is to be furnished by the main role which the Ministry of Home Affairs has to discharge and which the Ministry of Home Affairs must provide which is the feeling of security and wellbeing of the citizens of this country. One has only to ask oneself a question honestly—do the people of this country, during the regime of Sardar Zail Singh, feel safe and secure either in their homes or outside their homes whenever they go about in the streets? This requires to be studied.

If one were to ask the question honestly, there is only one answer. That is, every section of the people of this country has an uneasy feeling of fear, more than a feeling of current fear of foreboding of impending disaster. I do not want to be unfair to the Home Minister; I do not deny that there is a class of people who do feel safe and secure in this country. But, Sir, the snag is that those who only feel safe and secure in this country are the dacoits, the rapists,

the murderers, the corrupt brokers and, above all, the tricksters, the corrupt foreign bankers, who hold funds under camouflaged names, the money stolen from the poor people of this country. These are the classes of people who feel safe and the Home Minister's satisfaction can only arise from the circumstance that these classes are themselves so widespread and so colossal that they could claim that a large number of people of this country are happy and will be happy in spite of his misrule. Even Mr. Zail Singh would not deny that it is the legitimate role of the Opposition to draw the attention of the Government and the people of this country, to the tragic realities, to the tragic situation, that prevails at the moment and to the causes of that tragic situation and to the possible remedies which ought to be applied. I find that this role of the Opposition itself is being denigrated. I have carefully listened to and, at least, I have tried to read, the speeches that were delivered on Saturday in this House by the very distinguished colleagues from the Treasury Benches. I find that every attempt by the Opposition to draw the attention of the Government to its failures to its incompetence and to its own corruption, is being viewed with suspicion. It is being decried as it is being tried to be suppressed.

Sir, I have one word of caution to utter that, at the end of this debate, Sardar Saheb will get up and entertain us to a few couplets of Urdu and will indulge in a few jokes. (~~Interruptions~~) Sir, the faithful people around him will duly clap and applaud and there would be some hilarity in the House. And the hon. Home Minister will go back home to his Home Ministry and everybody will say that he was a jolly good fellow. But, Sir, it is not the kind of attitude with which we have to deal. But, we have to deal with such a tragic situation that confronts the country today. This requires no evidence. But, since my distinguished friend, Mr. Frank Anthony, happens to be here, it compels me to cite the evidence. But, the evidence which I will be able to cite could not even be more remotely characterised as partisan. But, it is my duty to produce before the House witnesses of unimpeachable credibility and integrity. My witness Number one is a gentleman, recently nominated by the distinguished President of this country, to the House of Elder ~~Statement~~, who happens to be running his own newspaper at the same time.

Sir, in his newspaper of yesterday under an editorial under the heading of 'Crimes in the Capital' he recalls the advice of Johnson to the citizens of London that before you leave your house and venture into the streets of London please make your will. And, Sir, he does recite that the performance of the Delhi police and the performance of the Home Ministry leave a good bit to be desired and he has told us that unless these murders and rapes and things like that—some of them committed in the broad day light and under the very nose of the Delhi police—are put a stop to, the city of Delhi and this country will soon hold a palm to cities like Chicago and other notorious cities of the world which are known for their crimes.

Sir, another sober newspaper almost wholly sold out to the furtherance of the Congress (I) cause equally reports that the crimes committed in every part of this country—particularly the city of Delhi—are a standing disgrace to not only so far as the police are concerned but also to those who appoint the police; those who guide the police and those who are ultimately responsible for maintenance of discipline in the police force. With this kind of evidence one does not have to go in looking for any other evidence.

But let me point out what happens in this august House and how the

(Shri Ram Jethmalani)

members of the treasury benches look upon this serious and tragic problem with the levity and that sense of irresponsibility which undoubtedly ought to be avoided if we are to seek any solution of the probelm.

On Saturday my distinguished friend, Mr. Baleshwar Ram from Bihar, speaking of this problem made an astounding suggestion to the Home Minister. The suggestion which he made was that the only way to stop crime in this country is to punish those who punished Mrs. Gandhi and some of her associates. If this is the kind of solution which comes from the mouths of sensible and responsible Members of Treasury Benches then I am afraid, Government will never improve and crime will not stop and the law and order situation will not improve in this country because you cannot devise correct prescriptions unless you have correct diagnosis of the problem and the diagnosis is provided to a Minister ultimately by his colleagues in Parliament and these are the kinds of diagnosis which are being pointed out to him that all this crime which is going on in the country—rapes, murders and dacoities—is due to the fact that some people who tried to punish Mrs. Gandhi have not been punished by Sardar Zail Singh.

Sir, as I said, unless you know the cause of the crime you will not arrive at the remedy. Another cause which is invariably thrown in our face—and this again shows what sort of troubled imagination my friends on the Treasury Benches have—is that the RSS and the Lok Dal people have infiltrated into the police and it is, therefore, that crime has increased in the country. Thank God, they admit that crime has increased. Also thank God, nobody had the courage to say that those police officers who raped the innocent women and those police officers who continue to be a disgrace on all the police force throughout the country were RSS volunteers who have infiltrated into the police force. But, Sir, all this speaks volumes of the irresponsibility—the intensity of irresponsibility—that they exercise in making speeches on the floor of the House All that we hear from them is that crime will stop if somehow you manage to get out from the police force the RSS people and the Lok Dal people who have gone into the police force. And, Sir, another distinguished friend of mine, Shri Harish Chandra Rawat, from the beautiful city of Almora said this. I wish he had made a speech which fairly represents the aesthetic sense of his city. But, Sir, what he told us is something very strange. He talked of that famous incident, the notorious incident, of Baghpat but he asked the House and he advised the House to forget it because he thinks it is not so serious when you compare it with another incident. That incident was that some unnamed United Front Minister had tried to flirt with some women in Singapore. He says this is a more serious incident which has taken place, why do you think of Baghpat. And I want the people of Almora at least to know through you Mr. Speaker, and through what we say in this House that their very distinguished representative in this House considers that Baghpat is less serious.**. If this is the kind of thinking of which the treasury members are capable of, I do not know how far you are going to solve the problem, Sir, we do not wish to go into people's private lives. I don't know who this unnamed United Front minister was. Presumably my distinguished friend who talked of this was not present in Singapore and he did not see this incident. Therefore, he must have relied upon some newspaper report. But, Sir, when you rely on newspaper report, there is a huge issue of the newspaper, called 'Current' by no means a paper favourable either to the Janata Party or the Bharatiya Janata Party.

**Expunged as ordered by the Chair.

** ** ** **

And, Sir, all I hope is that there will be some sense of responsibility exercised in this matter. (*Interruptions*)** Then, Sir, I wish to say this....

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): It was not united; it was disunited.

12.59 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

SHRI RAM JETHMALANI: Sir, I heard my distinguished friend Mr. Bhagat saying this in common with Mr. Baleshwar Ram talking to us the same thing. The first gentleman talked about this: Why don't you go about punishing those who have tried to harass Mrs. Indira Gandhi? Sir, Mrs. Indira Gandhi is the Prime Minister of this country. She has been elected by an overwhelming verdict of the people of this country. We respect it because we are running the democratic apparatus and however much we dislike this phenomenon yet we respect the people's choice. She is the Prime Minister of the country and I will, therefore, not say anything which denigrates the office of the Prime Minister by referring to the antecedents and the character of the occupant of that august office. But, Sir, since we are being constantly provoked, since we are being constantly prodded that Mrs. Gandhi was harassed, the harassers of Mrs. Gandhi must now be punished, Sir, I am only in self-defence entitled to retaliate very briefly and say this that Mrs. Gandhi was sent to prison by the verdict of this Parliament. If the plea now is that this Parliament should be punished, the gentlemen are welcomed to this plea, but after Mers. Gandhi was punishd by the Parliament on the same facts a prosecution was launched against Mrs. Gandhi in the Court because it also amounted to crimes in the ordinary Penal Code and Mrs. Gandhi who was given by a somewhat innocent and foolish Janata Government a chance to go to the judges and establish her innocence on the very facts of which she has been found guilty by Parliament, did not have the courage to go and fight the case on merits but she pleaded the bar of the limitation and got the case dismissed. (*Interruptions*).

SHRI JAGDISH TYTLER (Delhi Sadar): I personally know what he was doing.... (*Interruptions*).

SHRI RAM JETHMALANI: I always find that whenever I got up to speak they know that I am speaking the truth and it acts like chilly powder on them.

SHRI M. SATYANARAYAN RAO (Karunnagar):**

(*Interruptions*)

SHRI JAGDISH TYTLER: Let him deny this ... (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Jethmalani, you should stick to your subject-proper.

(*Interruptions*)

SHRI RAM JETHMALANI: Sir, I cannot fight with the ignorants who do not know the records, who do not know the judgment.

(*Interruptions*)

SHRI JAGDISH TYTLER: Let him deny that he was not instrumental in getting those witnesses to tell a lie. I was a witness to the harassment of Mrs. Gandhi and Mr. Sanjay Gandhi.*

This is the kind of justice they were trying to do to Mrs. Gandhi and this way they were using the police and now they say it is legitimate. (*Interruptions*).

SHRI RAM JETHMALANI: Sir, let me point out that the Supreme Court found them guilty of trying to influence.... (*Interruptions*).

SHRI M. SATYANARAYAN RAO.** .... (*Interruptions*).

SHRI JAGDISH TYTLER:** .... (*Interruptions*).

**Expunged as ordered by the Chair.

SHRI RAM JETHMALANI: I stand on the judgment of the Supreme Court which found them guilty of suborning the witness and sent him to jail.

MR. DEPUTY-SPEAKER:: The whole difficulty is that Mr. Jethmalani never forgets that he is an advocate. You please come to the subject-proper. Your time is over. You will have to complete now.

SHRI JAGDISH TYTLER: Sir, he is making false statement.

(*Interruptions*)

SHRI M. SATYANARAYAN RAO.**

(*Interruptions*)

SHRI JAGDISH TYTLER: I can say that for six months I was with him, after him, and I was trying to find what he was doing.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down....

SHRI M. SATYANARAYAN RAO: We cannot tolerate it when our leader is being attacked like this. What is he talking?

MR. DEPUTY-SPEAKER: He has not used any unparliamentary language. Now, please come to the subject proper and finish your speech within two-three minutes, Mr. Jethmalani.

SHRI RAM JETHMALANI: They are stinking.... (*Interruptions*) I do wish through you to invite the attention of the Minister for Home Affairs and any representative of his who is here to the incidents which have taken place in the city of Delhi. Let me recall that** a por employee, suddenly fell out of a moving Fiat car on the streets of Delhi. A gentleman was found inside the car with two glasses and a bottle of Whisky and a bottle of Gin. Has the Home Minister discovered the identity of that gentleman....

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not mention any person who is not a member of this House. Do not receord it; that will be expunged.... Please sit down. Mr. Jethmalani has mentioned the name of a person who is not a member of this House.....

SHRI RAM JETHMALANI: I have not mentioned any name.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Then, it is all right. I thought you have mentioned the name.

SHRI RAM JETHMALANI: I am on the contrary asking the Home Minister to determine the name.... (*Interruptions*). Truth is very unpleasant. Let me give them some more truth. The same gentleman sitting in the car....

MR DEPUTY-SPEAKER: Please come to the subject proper and complete. You have already exhausted your time.

SHRI RAM JETHMALANI: We are talking of the law and order.... (*Interrptions*). A girl, called Purnima, fell from the fifth floor of a Delhi building. She fell on the road and a person on seeing this woman fall, with an exclamation 'O God, help me' ran from the scene of offence. He was noticed by the Chowkidhar; he was identified by him. Why has the Home Minister and his police not yet identified that man?** (*Interruptions*). If this kind of thing goes on. I am sure, the crime in this country will never come to a stop. Political patronage and membership of a political party have come to mean an instrument of immunity from prosecution.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

**Expunged as ordered by the Chair.

SHRI RAM JETHMALANI: I wish to talk about another serious problem which confronts the nation today and which has been confronting the nation ever since Mrs. Gandhi's Government came to power. I am talking of the turmoil in the North-East of this country. Once again, the diagnosis is wrong and, therefore, the prescriptions are bound to be fallacious. Once again, I hear Mrs. Gandhi occasionally insinuating though her followers insinuating a little more overtly, that it is some kind of RSS mischief that is taking place in Assam. Sometimes Sardar Zail Singh says that some foreign imperialists are involved, sometimes our Communist friends talk of some kind of a body involved there. These are all wrong solutions. These are all.... (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Jethmalani, please complete your speech.

SHRI RAM JETHMALANI: I wish to repeat for the benefit of the Home Minister, certain things in a few words. I wish to Point out to him that to-day, it is mainly because of the reasonableness of the Opposition parties, it is mainly because of the soothing touch of my leader Shri Atal Bihari Vajpayee and some distinguished leaders of the Janata Party that there is comparative peace in that region; and the students to-day have given a demonstration of their goodwill to the Government, by calling off their agitation. I hope the temporary suspension of the agitation will now be taken full advantage of by Mrs. Gandhi, and she and her Ministers will see to it that this is not construed either as a weakening of the agitation, or as the lessening of the confidence of the students in the cause for which they are fighting. It behoves the Government to deal with these people with understanding—these people who understand the Constitution and the country better than either Mrs. Gandhi or Mr. Zail Singh or any other person in the Congress (I) Party who is dealing with this problem. The students have repeatedly said that they wished to solve this problem within the four corners of the Constitution. They have said that no legitimate citizen of this country shall be allowed to be harassed by anybody, and the constitutional rights of every legitimate citizen shall be respected fully, and shall be enforced fully. But it does not behove Sardar Zail Singh—and it is an indictment of his Ministry—that he should have thought, in the first instance, of using brutal force, supplemented only by ignorance of the cause of the agitation. Use of brutal force was threatened against these people—these people who have law and Constitution on their side. I hope sense will prevail, and wiser counsels will prevail and due attention will be paid to the needs of the area, and to the legitimate demands of these young men who have been carrying on this agitation for the last 9 months.

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय की मांगों के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। इस में कोई शक नहीं कि देश के लिये गृह मंत्रालय का अच्छा संचालन और गृह मंत्रालय की उपलब्धियां देश की सुरक्षा और आन्तरिक शांति के लिहाज से बहुत जरुरी है। देश की एकता बनी रहे इस की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय पर है। देश में कानून की व्यवस्था ठीक ढंग से चले इस की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय पर है। इस सरकार ने पिछले छः महीनो से जिम्मेदारी अपने कन्धों पर ली है। राज्यों के अन्दर अभी नौ राज्यों में सरकारो को बने डेढ़ महीने से ज्यादा नहीं हुआ। आज हम गृह मंत्रालय का मूल्यांकन करते वक्त इस बात को नहीं भूल सकते कि पिछले तीन सालों की राज्य की स्थिति क्या थी? इस देश में जनता पार्टी का राज था और फिर जनता पार्टी से ही अलग हुई एक लोक दल और कांग्रेस (यू) की मिली जुली सरकार थी। आज के हालात पर गौर करने के साथ साथ आप को इन तीन सालों के हालात को मदद नजर रखना होगा। कोई भी स्थिति आइसोलेशन में नही पैदा हुआ करती है। जनता पार्टी और लोकदल सरकार के जमाने में इस देश के अंदर जो गिरावट आई कानून और व्यवस्था में और आर्थिक स्थिति में जो बिगाड़ पैदा हुआ, जो सर्विसेज में डिमारलाइजेशन पैदा किया गया, उसका परिणाम यह है कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद यह सही है कि सुधार हुआ है कानून और व्यवस्था में लेकिन यह बात भी मैं मानने के लिये तैयार हूं कि जितना वांछित सुधार होना चाहिये था वह स्थिति भी नहीं बनी पाई है। इसका दोष मेरे मित्र जेटमलानी साहब हमारे गृह मंत्री, श्री जैल सिंह पर

[श्री नवल किशोर शर्मा]

आरोपित करने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि यह सरकार कुछ नहीं कर सकी। एक दो आइसोलेटेड किस्से बताकर उन्होंने यह जताने की कोशिश की कि कानून और व्यवस्था की स्थिति ऐसी हो गई है जिसमें लोगों का जीवन मुश्किल है। मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि जिन हालात में कांग्रेस पार्टी को सरकार मिली, उस समय जो सोशल और राजनीतिक परिस्थितियां तीन सालों में पैदा हुई, उन हालात में कोई जादू के डंडे के तौर पर सरकारी तन्त्र को ठीक नहीं किया जा सकता, आर्थिक स्थिति में बदलाव नहीं लाया जा सकता और सामाजिक टेंशन को खत्म नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि आज भी कानून और व्यवस्था की स्थिति में वांछित सुधार नहीं हुआ लेकिन किसी भी सरकार की उपलब्धि केवल मात्र आंकड़ों के आधार पर नहीं, उसके द्वारा किये गये प्रयत्नों को देखने से ही आंका जा सकता है।

श्री जेठमलानी जी कह रहे थे कि इस हाउस के सरकारी बेंचेज के लोग कितने गैर-जिम्मेदार है कि वे हल्ला-गुल्ला करके ऐसी समस्यायें जो देश में पैदा होती हैं उन पर विचार करने से रोकते हैं। मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं --वे चले गये हैं क्या विरोधी दल के लोगों ने देश की एकता को कायम रखने की अपनी जिम्मेदारी का सबूत दिया है? उन्होंने असम समस्या के बारे में कहा है कि ज्यादती नहीं होनी चाहिये, विद्यार्थियों पर जुल्म नहीं होने चाहिये, रूल आफ ला होना चाहिये, डण्डा नहीं चलना चाहिये, मैं नहीं मानता और मैं नहीं कहता कि हमारी सरकार की ओर से असम में कोई ज्यादती करने की कोशिश की जानी चाहिये पर एक बात भी साफ है कि असम के मामले में इस सरकार ने बहुत छूट दी है। पिछले 6 महीने से जबसे श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार केन्द्र में बनी है, बराबर यह कोशिश की गई है लेकिन उसके बावजूद असम की सर्विसेज कोआपरेट नहीं कर रही हैं। चाहे कोई बड़े से बड़ा पदाधिकारी हो, कमिश्नर हो, चाहे छोटे से छोटा सिपाही हो, और मैं तो यहां तक कह सकता हूं मुझे कभी कभी सन्देह होता है जुडीशियरी के बारे में—उन्होंने ऐसा रुख अख्तियार कर रखा है कि एजिटेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाये। आज जब असम में ऐसी स्थिति हो, देश को भयंकर नुकसान हो रहा हो, एकता के लिये खतरा पैदा हो गया हो, असम की प्रतिक्रियां के फलस्वरूप देश के अन्य भागों में कुछ लोग पृथकतावादी नीति पर चलने की बात सोच रहे हो, तब मेरा ऐसा मानना है कि सरकार ने बहुत इन्तजार कर लिया, बहुत दिन रास्ता खोला कि किसी तरह से समझौता हो लेकिन किसी चीज की एक हद होती है। आज वहां पर अल्पसंख्यक लोग परेशान हैं, देश बिखराव की ओर जा रहा है, ऐसे मौके पर अगर सरकार सख्ती के साथ कदम नहीं उठाती है तो शायद वह गल्ती करती है। हमारे विरोधी मित्र सम्भवतः इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। एक्रास दि टेबल बात करने से वे कतराते हैं, अलग अलग तरीके से सुझाव देकर वे इस समस्या को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि सारे लोग, कुछ पैट्रियाट भी हैं, लेकिन कुछ लोगों की पॉलिटिकल एम्बिशन्स भी हैं, उनके कुछ इरादे भी हैं, उनके इरादे पूरे करने के जाल में सरकार को नहीं फसना चाहिये बल्कि अपने काम को मजबूती से करना चाहिये। मैं तो बधाई देना चाहता हूं कि सरकार ने जो कुछ सख्त कदम उठाने की कोशिश की है, जो शुरुआत की है, उसके नतीजे निकलने लगे हैं। हम चाहते हैं कि वार्ता के जरिये समझौता हो, लेकिन उस वार्ता के नाम पर बहुत दिनों तक असम की समस्या को, चाहे वह त्रिपुरा की समस्या हो, चाहे पृथकतावाद का कोई और सवाल हो, उनको टाला नहीं जा सकता है- यह मेरा आपसे विनम्रता के साथ निवेदन है।

हरिजनों के अत्याचार की बात भी इस सदन में अक्सर हमारे विरोधी दल के लोग उठाकर देश में एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हरिजनों पर इस सरकार के आने के बाद एक कहर सा ढाने लग गया है, रोज का यह कायदा है हमारे जिम्मेदार लोग इस तरह की बात करते है। मैं श्री जेठमलानी व उनके दल के लोगों से और विरोधी दल के लोगों से कहना चाहता हूं कि सदन में गृह मंत्रालय की मांगे चल रही हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय रोज कहते हैं कि जो कुछ आपको कहना है वह आप गृह मंत्रालय की मांगों पर कहिये, लेकिन रोज का यह धन्धा हो गया है। एडजार्नमेंट मोशन के नाम पर, इस सदन का 15-20-25 मिनट और कभी कभी एक घन्टा या आधा घण्टा समय खराब किया जाता है और कोई भी इन्सीडेंट हो, अखबारों में जो रिपोर्ट आती है, मैं उसके आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं, पर सदाकत यह है कि चाहे रेप के सवालात हों, चाहे हरिजनों पर अत्याचार के सवालात हों, उनके बारे में जो रिपोर्टे आई है, उनमें यह कहा गया है कि ये सारे के सारे तो नहीं, लेकिन इनमें से बहुत इन्सीडेंट्स झूठे हैं। यह रात दिन इस सरकार को बदनाम करने की कोशिशें हैं। जहां राष्ट्रीय सवाल हो, वहां तो जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी के साथ आचरण करना चाहिये। जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, मेरा उनसे विनम्रता के साथ निवेदन है कि पहले वे अपने आचरण को देखें।

मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि हरिजनों के साथ जो घटनायें घटती हैं, उनका सख्ती के साथ मुकाबला किया जाना चाहिये। लेकिन मैं गृह मंत्री जी से एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि केवल मात्र कानून से, कानून को सख्त बनाने से, इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। कानून तो हमने बहुत सख्त बना लिये हैं, हमने अनटचेबिलिटी कानून को भी काफी कड़ा करने की कोशिश

की है । असम में समस्या का समाधान अगर हमको ढूंढना है, तो हमें ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा, हमें ऐसी परिस्थितियों का देश में निर्माण करना पड़ेगा ताकि उन समस्याओं का समाधान हो सके ।

एक जो सबसे बड़ा इरिटेंट है, हरिजनों के झगड़े का सबसे बड़ा कारण है, वह है जमीन का सवाल । हरिजनों के कब्जे की जमीन, चाहे वह शेड्यूल्ड कास्ट की हो और चाहे वह शैड्यूल्ड ट्राइब्ज की हो, उन की जमीनों के कब्जे की रक्षा की जानी चाहिये और कोई भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिये कि जहां पर हरिजनों की जमीन किसी स्वर्ण के हाथों में जा सके । मेरा आपसे निवेदन है कि कानून की जो प्रक्रिया है, उसके जरिये ही नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के जरिये हरिजनों को उनकी जमीनों से बेदखल करने से रोकना चाहिये और जहां उनको बेदखल कर दिया गया है, उनको वह जमीन वापिस दिलाई जानी चाहिये ।

इसी तरह से मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, जो हरिजनों की समस्या के समाधान के लिये है । आज जो देश के अंदर कास्ट सिस्टम है, यह जोर पकड़ता जा रहा है, उस पर भी विचार करना चाहिये । उपाध्यक्ष महोदय, अब समय आ गया है, हम को यह सोचना पड़ेगा कि आज विभिन्न जातियों के लोग अपने नामों के आगे जो अपना कास्ट नेम लिखते हैं, क्या इसको आज कानून से रोका नहीं जा सकता है ? सर-नेम लिखने की जो प्रवृत्ति आज देश के अन्दर चल रही है, मैं समझता हूं कि इसको रोके बिना, इसको बंद किये बिना, इस देश से कास्टिज्म का जहर खत्म नहीं हो सकता है । मैं वाजपेयी जी से कहना चाहता हूं कि वह अपनी तरफ से शुरुआत करें, वे अपनी तरफ इशारा भी कर रहे हैं । मैं यह समझता हूं कि इस बारे में भी हमको कुछ और गम्भीरता से और नये परिप्रेक्ष्य में सोचना पड़ेगा कि यह कास्टिज्म इस देश के अन्दर एक नासूर बनता चला जा रहा है इस कास्टिज्म को कैसे खत्म करें, ताकि देश के अन्दर यह जो खाई पैदा होती जा रही है, इसको खत्म किया जा सके ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं । हमारी सर्विसिज के बारे में भी कुछ होना चाहिये । अभी सुखाडिया जी फर्मा रहे थे कि पिछली सरकार ने जो कमीशन्ज बनाये, उस के बाद सर्विसिज में डीमारलाइजेशन आ गया—यह बात बिलकुल सही है । आज भी सर्विसिज में यह डीमारलाइजेशन कायम है । इस के बारे में सोचना चाहिये कि सर्विसेज में पार्टी पोलिटिक्स के नाम पर जो स्थिति पैदा होती जा रही है उस को कैसे रोका जाय सर्विसिज में गिरावट को रोकने के बारे में हमें गम्भीरता से सोचना चाहिये ।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में गवर्नर्ज का एप्वाइन्टमेंट प्रेसिडेन्ट द्वारा होता है । मैं आज यह सवाल गृह मंत्रालय के सामने रखना चाहता हूं—क्या यह सही नहीं होगा कि सत्ता परिवर्तन के साथ गवर्नर्ज भी बदल जाया करें । मेरे दोस्त मधु दण्डवते जी इस बात पर हंस रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जो पार्टी सत्ता में आती है

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Madhu Dandavate will immediately resign.

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA: Thank you मैं इस बात को एक गम्भीरता का सवाल बना कर पेश कर रहा हूं । जो पार्टी सत्ता में आती है और वह जितने समय तक सत्ता में रहे, उस को अपने शासनतन्त्र को अपनी तरह से चलाने का मौका मिलना चाहिये । चुनाव के मौके पर लोग फैसला करते हैं और जिस पार्टी को अच्छा समझते हैं, उस को मत देते हैं, जिस को खराब समझते हैं उस को रिजेक्ट कर देते हैं । लेकिन कई दफा यह देखने को मिलता है कि गवर्नर और सरकार के बीच में ताल मेल नहीं होता और उस के अभाव में कुछ डेड-लाक्स पैदा हो जाते हैं । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय इस सवाल पर गम्भीरता से विचार करे या ऐसी कन्वेंशन्ज इस देश में होनी चाहिये कि जिस पार्टी की सरकार आये, उसके साथ ही गवर्नर्ज अपने आप इस्तीफे दे दें । हमारे सामने कुछ ऐसे प्रश्न आये हैं, मैं उन के नाम नहीं देना चाहता और न उस में जाने की आवश्यकता है, गवरनर्ज के बारे सदन में गरिमा से बात करनी चाहिये, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि नये परिप्रेक्ष्य, नई विचारधाराओं के बीच जो देश के हित में हो, हमें उस पर चलना चाहिये, आब्सोलीट या ऐसीमिटो व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहिये, भले ही कास्टीच्यूशन के हिसाब से वह सैक्रेड हो, लेकिन उसे भी बदलने की कोशिश करनी चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं और आपने मुझे बोलने का जो समय दिया है, उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: With the permission of the House, we will have to complete the discussion by this evening. I think the Government will have no objection extending the period so that we can complete the speeches by all the Members this evening whatever the time might be. At 4 P.M. the State Minister will intervene. The discussions must be over to-day evening. This is an important Ministry. I want to give chance to all the Members, irrespective

[Mr. Deputy-Speaker]

of the number of Members in any party provided you are prepared to sit late in the night. Home Minister will reply tomorrow. This is the programme.

PROF. MADHU DANDAVATE: It will be a matter of pleasure to hear couplets in the evening if the Home Minister could reply in the evening.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Chandra Shekhar Singh.

Every Member of the ruling Party will get not more than nine miutes.

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA: How have you come to this figure—nine? Is it an auspicious figure? It can be ten or twelve.

श्री चन्द्रशेखर सिंह : (बांका) उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में हुए वाद-विवाद को सुनने के बाद मन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि सारे देश के सामने एक मात्र समस्या महिलाओं पर अत्याचार या हरिजनों पर अत्याचार की ही है। इस पर काफी चर्चा हो गई है, इसलिये मैं उस के सम्बन्ध में कुछ कहना आवश्यक नहीं समझता हूं। और मैं यह अनुभव करता हूं कि गृह मंत्रालय का काम केवल फायर ब्रीगेड की तरह नहीं होना चाहिये कि जहां कोई अत्याचार का मामला हुआ, कोई दंगा हुआ या कोई फसाद हुए, तब गृह मंत्रालय की याद हमको आवे और गृह मंत्रालय की चर्चा हम यहां पर करें। इसलिये मैं उन मुद्दों की चर्चा करना जरूरी समझता हूं जिस से लोग आम तौर से भी उन के मंत्रालय को याद कर सकें और इस मंत्रालय के जरिये साकारात्मक कार्यक्रम पेश किये जा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, पहली बात तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रशासनिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन का एक मुख्य प्रश्न है। जो कुछ भी प्रशासन का मुझे अनुभव रहा है, उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि आज की जो यह प्रशासन व्यवस्था है, वह आज की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिये अनुपयुक्त सिद्व नहीं हो रही है और उस से जो अपेक्षायें है, वे पूरी होने की संभावनायें नजर नहीं आती हैं। एक बात यह बहुत स्पष्ट है कि आज इस व्यवस्था का बोझ इतना बड़ा हो गया है। मालूम पड़ता है कि सरकार की आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा इस व्यवस्था को चालू रखने में, उस को जीवित रखने में ही व्यय हो जाता है। अगर आप आंकडों को देखे तो यह पायेंगे कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को मिला कर लगभग 1 करोड़ सरकारी नौकर है और उन पर पिछले 30 वर्षों के अन्दर तीन गुना व्यय हमारे जी एन. पी का आज बढ़ गया है। 30 वर्ष पहले अगर उस का 10 प्रतिशत खर्च होता था, तो आज 30 प्रतिशत प्रशासनिक व्यवस्था पर खर्च हो रहा है और मैं अपने बिहार जैसे गरीब सूबे की चर्चा करूं, तो बिहार सरकार की अपनी जितनी आमदनी है, वह पूरी की पूरी बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को जीवित रखने में व्यय हो जाती है। आज यह स्थिति है और किस प्रकार इस भार को हम वहन कर सकते हैं, इस पर गृह मंत्रालय को विचार करना चाहिये लेकिन उस से भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज का यह प्रशासन हमें सही दिशा की ओर ले जाने वाला नहीं है। अगर हम देखें तो एक तो यह व्यवस्था ऐसी है, जिस में अनावश्यक समय लगता है और साथ साथ जिन जिन समस्याओं का निष्पादन जिस दिशा की तरफ होना चाहिये, उस दिशा की तरफ न हो कर हमें गलत रास्ता अख्तियार करने के लिये मजबूर होना पड़ता है। इसलिये मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार इस शब्द का मैं प्रयोग करना नहीं चाहता क्योंकि सुधार एक मामूली शब्द है, इस के लिये मैं जरूरी समझता हूं कि आमूलचूल परिवर्तन करना आवश्यक है। आज हम यह देखें और तमाम सदस्यों का यह तजुर्बा होगा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार आज देश में कायम है लेकिन जहां तक सर्वसामान्य लोगों का सम्बन्ध है, उन के लिये सरकार का रूप वही है। वही प्रखण्ड विकास अधिकारी है, वही थाने का दारोगा है उस का रूप आज भी वही है। उस की क्या दिशा है, हम आप, इस सदन के माननीय सदस्यगण, इस को अच्छी तरह से महसूस करते हैं। वे आज यह समझते हैं कि वे मालिक हैं, स्वामी है और जन प्रतिनिधि उस के सहायक नहीं हैं बल्कि उस के काम में बाधक हैं और जनता को जो कुछ मिलता है, उस को दान स्वरूप ही कुछ मिलता है और न्याय और इन्साफ पाने की वह अधिकारी नहीं है। अगर आज इस व्यवस्था को बदलने की आप चेष्टा नहीं करेंगे, तो चाहे जितनी अच्छी रूप रेखा आपके कार्यक्रमों की हो और चाहे जितनी अच्छी आपकी योजनायें हों, उनसे जनता को कुछ विशेष प्राप्त नहीं होने वाला है। मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आज यह बहुत जरूरी है। कि हमारे जो भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी हैं, उन की ट्रैनिंग का जहां तक सवाल है, उन की शिक्षण व्यवस्था का जहां तक सवाल है, उस में भी आप परिवर्तन करें। हम ने देखा है कि अच्छा काम वे कर सकते हैं, अच्छे कामों को पूरा करने की तरफ उन की रुचि है लेकिन उन की शैली इस प्रकार की है, जिस से जनता से कभी उन का सम्पर्क स्थापित नहीं हो सकता है और जनता उन तक पहुंच नहीं सकती है। इसलिये मैं यह जरूरी समझता हूं कि गृह मंत्रालय इस परमावश्यक समस्या की ओर ध्यान दे। और जो आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए वह करे।

मैं एक दूसरे विषय की चर्चा करना भी आवश्यक समझता हूं। मेरे विरोधी दल के सदस्यगण मुझे माफ करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में चाहे जनता पार्टी का राज रहा हो, चाहे लोक दल का राज

रहा, हो, उस अवधि में सब से बड़ा योगदान राजनीति में जो उनका रहा है वह साम्प्रदायिकता का रहा है, वह जातीयता का रहा है। मैं उसके विश्लेषण में नहीं जाना चाहता। मुझे याद है जब पटना शहर में, पटना जंक्शन पर सरसंघचालक का आगमन होने वाला था उस दिन उनके स्वागत के लिए कितने हीं विरोधी दल के नेतागण और वे नेतागण जो अपने को वामपन्थी कहते हैं, फूलमालाएं ले कर स्वागत करने के लिए तैयार थे। हिन्दुस्तान की राजनीति के लिए वह दिन एक काला दिन साबित हुआ। इसने हिन्दुस्तान कीं राजनीति की बुनियाद को ही धक्का पहुंचाया। हम यह समझते हैं कि सभी धर्मों के प्रति इज्जत, आदर और प्रेम का व्यवहार होना चाहिए और इसी मार्ग का हम अवलम्बन करते आये हैं। लेकिन खास तौर से पिछले तीन वर्षों में जिन तत्वों को प्रोत्साहन मिला है, गृह मंत्रालय का काम है कि ऐसे तत्वों को इस देश की राजनीति से, शासनतंत्र से बाहर किया जाए।

मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल स्पष्ट सुझाव दूंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह जरूरी है कि जो आर० एस० एस० की शाखाएं सार्वजनिक रूप से चलती हैं, सार्वजनिक जगहों पर चलती हैं और बेरोकटोक चलती हैं उनका कम से कम सार्वजनिक प्रदर्शन तो बंद ही होना चाहिए। इस सरकार की यह कार्यवाही तत्काल करनी चाहिए। (व्यवधान) किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ऐसी किसी भी संस्था को इस प्रकार का प्रदर्शन करने का अधिकार नही है, गैर कानूनी प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। कलक्टेरेट के मैदान पर, स्कूल के मैदान पर, रेल के मैदान पर शाखाएं नही लगायी जानी चाहिएं किसी व्यक्ति के घर पर उसकी जमीन पर शाखा लगा सकते हैं। किन्तु सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार के प्रदर्शन को, जो कि वैधानिक और कानूनी नहीं है बंद करने के लिये हमारी सरकार तत्परता से कार्य करे।

मैं इस बात को कोई आक्षेप के रूप में नहीं कहना चाहता हूं कि तीन वर्षों मे ऐसे तत्व हमारे शासन तंत्र मे आ गये है जिनका धर्मनिरपेक्षता मे विश्वास कमजोर है। मैं समझता हूं कि ऐसे तत्वों को शासनतंत्र से अलग किया जाये, उन्हे खोज कर निर्दयतापूर्वक अलग किया जाये। शिक्षण संस्थाओं मे ऐसे तत्वों का प्रवेश पिछले तीन वर्षों में अनवरत रूप से होता रहा है। इस देश में ऐसे विश्वविद्यालय ऐसी शिक्षण संस्थायें है जिनमें स्कालरशिप के द्वारा प्रोत्साहन दे कर ऐसे तत्वों को अध्यापकों को अन्दर लाने का षड्यंत्र किया गया है। मैं समझता हूं कि यदि आने वाली पीढी को सही दिशा देनी है, सही मार्गदर्शन देना है तो उन शिक्षण संस्थाओं को ऐसे तत्वों से मुत करना होगा, स्वच्छ करना होगा पवित्र करना होगा और उनमें राष्ट्रीय भावना भरनी होगी।

चौथी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सब से भयानक और गलत बात जो जनता पार्टी के राज में हुई वह इस देश के नन्हे और स्कूल में पढने वाले बच्चो की पाठ्यपुस्तको और इतिहास की पुस्तकों मे विकृत तथ्यों को प्रस्तुत करने की। मैं उनके विवरण मे जना आवश्यक नही समझता लेकिन यदि हम समझते है कि हमारे नन्हे बालकों में, बच्चों में राष्ट्रीयता की छाप रहनी चाहिये, धर्मनिरपेक्षता की छाप रहनी चाहिये तो ऐसी जो पुस्तकें है, उनको फिर से लिखवाया जाये। इस के लिये ऐसे विद्वानों की समिति बनायी जाये जिनका कि स्पष्ट रूप से विश्वास और आस्था धर्मनिरपेक्षता में हो और उनसे ऐसी पुस्तकें लिखवा कर प्रकाशित की जायें जिससे कि हमारे दश मे जातिगत एकता और मजबूत हो।

मैं अपने आदरणीय मित्र शर्मा जी ने सहमत हूं जिन्होंने यह कहा है कि यदि हमें जातीयता और जाति आधारित राजनीति को समाप्त करना है तो इस सरकार को साहस के साथ यह निर्णय लेना होगा कि जाति के आधार पर यदि कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है तो ऐसे कार्यक्रम को चलाने देने के लिये यह सरकार तैयार नहीं है। यह जरूरी समझता हूं कि अनेक प्रश्न इसके साथ जुड़े हुए हैं। समय के अभाव के कारण मैं इस के विस्तृत विश्लेषण में जाना नही चाहता हूं। लेकिन यह जरूरी है कि जिन पांच बिन्दुओं को मने आपके सामने स्पष्ट रूप से रखा है उन पर गृह मंत्री केवल चिन्तन ही न करें बल्कि कारगर कदम भी उठाएं। बलवे और दंगे जो हो रहे हैं उन को दबाने का ही आप काम न करे बल्कि साथ ही साथ इस देश की राजनीति और समाज व्यवथा को सही दिशा देने का जो आपका उत्तरदायित्व है उसको भी आप पूरा करें।

मै केवल एक और विषय की चर्चा करना चाहता हूं। पिछड़ी जातियों के बारे में इस सरकार का गृह मंत्रालय का खास संवैधानिक उत्तरदायित्व है। जहां तक हरिजनो और आदिवासियो का प्रश्न है मैं समझता हूं कि आज इस मौलिक प्रश्न की तरफ श्री नवल किशोर शर्मा ने संकेत किया है और उस संकेत को ले कर आपकों साहस के साथ आगे बढ़ना होगा, सोचना होगा। त्रिपुरा मे भी भंयकर घटनायें घटी है। मंडई में नर संहार हुआ है उससे तमाम लोगों को दुख और चिन्ता हुई है। लेकिन साथ साथ आपकों इस बात को याद रखना होगा कि वहां के आदिवासियों ने जो आज आन्दोलन कर रहे हैं, सब से महत्वपूर्ण मुद्दा जमीन का उठाया है। उनकी जमीनें दूसरे लोगों द्वारा छीन ली गई हैं वे उन्हें वापिस दी जायें या नहीं दी जायें और दी जायें तो किस तारीख से दी जाये, यह एक अहम मुद्दा है। सरकार को निर्णय लेना होगा कि जिस तरह से कई राज्यों में आदिवासियों की भूमि का हस्तातरण नहीं हो सकता है, उस पर रोक है, उनका ट्रांस्फर नहीं हो सकता है उसी तरह से सारे देश

[श्री चन्द्र शेखर सिंह]

के पैमाने पर हरिजनों और आदिवासियों की भूमि के ट्रांसफर के सम्बन्ध में रोक लगाने के बारे मे स्पष्ट और निश्चित कदम आपको उठाना होगा। सारे विवादों को खत्म करने के लिये यह एक आवश्यक कदम है। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि अनेक तरह के माइनोरिटीज के सवाल जो हमारे सामने आ कर खडे हो रहे है उनका भी कुछ हल हो। दूसरा भयंकर प्रश्न स्थानिक माइनोरिटीज का है। धीरे धीरे सुलगता हुआ यह भयंकर प्रश्न आज त्रिपुरा में उठ खडा हुआ है। त्रिपूरा मे जो प्रश्न उठ खडा हुआ है यह उसका एक फैसेट है, एक अंग है जिस की ओर हम सभी लोगों का ध्यान आंकर्षित हुआ है। ये जो तमाम प्रश्न है इनके बारे में आपकी स्पष्ट नीति और रुख होना चाहिये। आज सदन मे केवल इस बात की चर्चा होती है कि गृह मत्रालय ने बलवा रोकने मे, औरतो को सरक्षण प्रदान करने मे, हरिजनो और आदिवसियो को सरक्षण देने में अपनी जिम्मेदारी पूरी नही की है लकिन जिन मुददों को मैने आपके सामने उपस्थित करन की चष्टा की है, उनके बारे मे आप साहस के साथ स्पष्ट कदम और ठोस कदम उठाऐगे, ऐसी मैं आप से आशा करता हू। ऐसा आपने किया तो निश्चत रूप से इस सदन मे गृह मंत्रालय के सबन्ध मे एक दूसरा रुख पैदा होगा और गृह मंत्री महोदय को यह देश धन्यवाद देगा कि एक सही दिशा एक सही रास्ता देश को दिखलाने की और सही रास्ते पर देश को प्रेरित करने की उन्होने कोशिश की है।

एक अंतिम बात कह कर मैं समाप्त करता हूं। श्री जेठमलानी यहा नही है। उन्होने हमारे मित्र श्री बालेश्वर राम के भाषण की बडी चर्चा की। उन्होने यह आशंका व्यक्त की है कि शायद जिस प्रतिशोध की भावना से प्रेरित हो कर तीन वर्ष तक जनता पार्टी जलती रही और जो ज्वाला उसके मन में सुलगती रही शायद उसी ज्वाला मे हम भी जलेगे और वही ज्वाला हमारे हृदय मे भी सुलग रही है। मै उनको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी वह नीति नही है जो जनता पार्टी की नीति थी, जो लोक दल की नीति थी। जनता ने जो आज इतिहास के कूडेदान मे उनको फक दिया है उनकी अपनी गलतियो की वजह से अब उनको सहारा दे कर हम फिर उनको आगे ले चलने वाले नही है, उनको आगे बढाने वाले नही है। आज बदले की भावना से हम काम करे यह हमारी चिन्ता नही है। हमारा विश्वास राजनीतिक एप्रोच में है। हम समझते है कि जो कोई सरकार या जो कोई दल गलत कार्यक्रम अपनायेगा, गलत नीति अख्त्यार करेगा, उसका उत्तर देश के आम लोग देगे। हम प्रतिशोध की भावना से कभी प्रेरित नही है। इन्ही शब्दों के साथ मैं गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हू और आशा करता हूं कि हमारे योग्य गृह-मंत्री और राज्य गृह-मंत्री और हमारी सरकार इन मददों पर फैसला करगी और इस बात को स्पष्ट करेंगी कि हमारी नीति फायर ब्रिग्रेड की नीति नहीं है, हमारी नीति पौजिटिव है, सापेक्ष है, सही दिशा देने की नीति है।

SHRI FRANK ANTHONY (Nominated-Anglo-Indians): Mr. Deputy-Speaker, I have given notice of two cut motions. They are complementary in character. The first is about the need for the declaration of an emergency in the State of Assam. The second is about the need for a much fuller application of preventive detention in the country.

I realise that the cut motions or the issues that they seek to raise will perhaps tend to raise the hackles of certain disparate elements in the House—pseudo democrats, crypto totalitarians masquerading as democrats and those who, in fact, worship at totalitarian shrines. But so far as Assam is concerned, I feel—and I have studied the problem perhaps more than most people—that the declaration of emergency is long overdue. In the last nine months the Prime Minister has done everything that is humanly possible to meet more than half way the various agitating groups. She has accepted insults and abuse from the youth whose megalomania has grown because of her continuing lenient treatment.

All the ingredients for declaring an emergency have been postulated by the Government at different times in the House. The Home Minister is here. He told us on one occasion that the agitation had got beyond control or out of the hands of the students. He told us that it was being supported from outside, but he was reluctant to name the outside agency. Members of this House have indicated a particular party that has got both feet in the agitation and is seeking to encourage this agitation. The position is one of stark insurgency. And as I see it as a lawyer, what is happening there and what has happened speaks raucuously of nothing but rank insurgency. And as I see it, and I have discused matters with leading Members from Assam, lawyers and ex-Ministers, and they tell me that at least 70 per cent of the population today are looking for deliverance from what is happening to the Centre.

Half the population consists of minorities. They have been living in terror. Thank God today they are beginning to re-assert themselves. The poor have been deprived of their livelihood, they form the major element. Students are without education. I have just written a pathetic letter to the Prime Minister. Brilliant students are being deprived of employment only because of this insane insurgency in Assam. They, as I say, are looking to the Centre for storong and even ruthless measures.

Let me say without qualification that the motives of those who talk of negotiation are not only oblique, but they are demonstrably *mala fide*. I anticipated what my friend Ram Jethmalani was going to say. The people who are talking in terms of negotiation know that their efforts are disingenuous. They do not intend to negotiate. The same formulae—the cut off date, 1952 electoral rolls—are being projected again and the paralysis continues, the blockade of supplies continues both in the State and to the rest of the country, and the killings continue to grow.

I know that some elements in the country are seeking to reap political dividends. Because Mrs. Indira Gandhi's massive mandates have reduced them to divisive rumps, they feel that if they can accentuate this trouble in sensitive areas, they may be able to reap some kind of political dividends.

You probably know that the power to declare an emergency is posited in article 352. It postulates that when the President is satisfied than an emergency exists whereby the security of India or any part is threatened by war or external aggression or internal disturbance, a declaration may be made in respect of the whole or the part. Today, what do we see? I am speaking now very frankly to the Home Minister. This is not an internal disturbance. It is an internal disturbance in a way, it is an internal disturbance in the most vulnerable, the most sensitive part of the country. But it is much more than that. It is overlaid with external aggression, because what is happening today in Assam is a deliberate, direct invitation to aggression from outside. Haven't we got aggression from outside? Aggression takes different forms. We have almost an over aggression from outside. Everyday, we are told about Seven Sisters, China arming people, including the people from Assam, training them and giving them arms. And that is a direct consequence of this so-called interenal disturbance. It has taken on all the overtones of an external disturbance of endangering security by way of external aggression. What do we do? What are the other ingredients? You have internal disturbance, you have external aggression, covert, if not overt; then you have the minorities in grave and increasing danger. I had some people send a message to me, they were Assamese, they refused to join the movement, and they were threatened, their wives and daughters were threatened with mutilation, with death if they do not join this movement. What more do you want? The administration is at a stand-still. The country is being starved of all kinds of crucial supplies. Can there be a stonger case for declaration of Emergency? The danger is to the whole Country. The longer you delay, the position will get infinitely worse. This is the poison that is spreading, it has already begun to spread and you would only encourage it by continuing leniency. I know the Prime Minister has gone out of her way. But people now identify this leniency with weakness and already as see, it is playing into the hands of secessionists in Assam, and it is playing into the hands of the people who are trying to take advantage of this troubled area in order to try and if possible get this whole area to break away from the rest of the country.

I was going to deal with what Mr. Ram Jethmalani said, although I will not be able to deal with him as fully as I would like to. I will come to that

[Shri Frank Anthony]

a little later. But the first thing that will have to be done is to dismiss all the senior officials who identify themselves with rank insurgency. That is the first thing you have to do apart from all other actions you may take in order to keep your administration going.

I knew that my friend, Ram Jethmalani—I will come to him now—would use this so-called declaration of partial conditional suspension of the agitation for trying to support the claim of the agitationists. The attitude of the party to which he belongs has been demonstrably maladroit. The motives have been there for everybody to see. They want to see this whole area troubled so that....

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (New Delhi): That is wrong.

SHRI FRANK ANTHONY: My friend is saying, it is wrong. But every action speaks for itself.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Can you cite a single example?

SHRI FRANK ANTHONY: I am going to prove it now. What have they been saying? They have been saying this and the students have only been repeating what they have been telling them. In this partial suspension, what have they said? They say: 'You reinstate the government servants'. Now they are asking this Government to reinstate the people who are supporting nothing but rank insurgency. They want this Government to create a precedent for Government servants in the States and the rest of the country to be able to join in rank insurgency movements for secession and then to claim to be re-instated: that is the formula borrowed from my friends like Mr. Jethmalani and his colleague, my friend, Mr. Atal Bihari Vajpayee.

Another part of the formula is that you withdraw the repressive measures. Only a knave or a fool—they are not fools—can suggest that you withdraw the alleged repressive measures. What repressive measures? You have alerted the armed forces, you have taken some of your central police forces there and they want preventive detention withdrawn. What would happen? See this partial suspension order. What have they said? The whole thing is a disingenuous ploy to gain time, because after a fortnight—God forbid—if you do anything like this, if you reinstate the senior officials, if you lift preventive detention, they will immediately come forward reinforced. Look at what they have said. They have asked their regional organisations to strengthen themselves. They have said that the legislators who do not immediately join them should be boycotted. It is an euphemism for terrorising them. And last but not the least, they have repeated their intransigent formula. They have said, the only solution will be the 1951 National Citizenship Register and the 1952 electoral rolls. And my friend is going along with them. The whole thing is demonstrably disingenuous and this disingenuous formula, they have borrowed from my friends, Mr. Vajpayee and Mr. Jethmalani. This is what they have done.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: May I thank the hon. Member for giving me credit, which is not due?

SHRI FRANK ANTHONY: Look at what they are continuing to do. The Prime Minister has said: 'Yes, you withdraw it unconditionally, we will also come unconditionally to the negotiating table.' I think, she went too far. But anyway, that is the offer. Look at their conditions, the blockade of oil, essential supplies and all commercial products to Assam and from Assam to the rest of the country will continue. They have told all their units to strengthen themselves for a likely final showdown. This is an offer which could only, as I see have been processed in the offices of the Bharatiya Janata Dal or whatever they call themselves. Because they are callow youth, they do not know. Somebody is conditioning them, somebody

from inside and somebody from outside. Obviously, this conditioning has been done by not incapable lawyers from inside.

My next cut motion is of a complementary character and that is, preventive detention should be applied much more fully in the rest of the country. I know that we have no preventive detention generally. The Janata Party tried to have mini-MISAs in Bihar and Madhya Pradesh. We have preventive detention for economic offences. I am not talking so much now of COFEPOSA, which is meant essentially for smugglers. We have put on the statute book 'The Prevention of Black-marketing and Maintenance of Essential Supplies Act'. I know my friend, the Home Minister will say, he has no direct concern with this. I say, he has a direct concern with this. Technically it may be the concern of the Civil Supplies Ministry but I say it is the direct concern of the Home Ministry because it is the dominent Ministry so far as the security of the country is concerned. Blackmarketeers profiteers and hoarders who are the constituents largely of a particular Party—I do not have to name it; Mr Vajpayee will get offended—are undermining the security of the country. That is why I want preventive detention to be used very much more liberally. (I do not know whether it is a contradiction in terms—'preventive detention' and 'liberally'...

14 hrs.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Only a nominated Member can make this type of speech!

MR. DEPUTY-SPEAKER: But he is an Hon. Member of the House.

SHRI FRANK ANTHONY: My friend does not know that a nominated Member who has defended....

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no difference between a nominated Member and an elected Member: all are Hon. Members.

SHRI FRANK ANTHONY: If my friend Atal Bihari were preventively detained, probably the first lawyer he would come to is myself because I have had more people—arrested under MISA—released than perhaps any other lawyer in the country.

Let me tell my friend, the Home Minister something else. We see what is happening in Delhi. Prices are going up every day. Let us be quite frank: who is responsible for this?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Atal Bihari Vajpayee!

SHRI FRANK ANTHONY: No, No; it is Atal Bihari Vajpayee immediately behind the scene and Atal Bihari Vajpayee's constituents very much on the scene.

You see what is happening. Shops are working cheek by jowl. There is no tag They charge whatever they take. I do not know what is happening to the Government. They have no tags and there is no preventive detention I want to tell my friend: 'Apply preventive detention liberally, but apply it carefully', because it is only today a news item appeared that some people who allegedly dealt with thousands of kilograms of sugar were preventively detained, but obviously the law was not correctly applied because three sitting judges of the Delhi High Court ordered their release. So, you see that even people who were preventively detained because of every safeguard have been released.

I do not know why Mr. Vajpayee should be preventively detained. He may be, but there should be all kinds of safeguards That is why I have always insisted on the continuance of a judicial review. I know that preventive detention is not the only answer, but it is a powerful instrument by which, in Delhi, overnight you can bring down the prices of your vegetables, you can bring down the prices of

[Shri Frank Anthony]

your essential commodities—if you lockup a thousand of Mr. Atal Bihari Vajpayee's constituents under the Preventive Detention Act. I do not know why you don't do it. They don't have tags. As I say, more and more shops, cheek by jowl, are charging what they want and at varying rates.....

MR. DEPUTY-SPEAKER: Why don't you get a list from Mr. Vajpayee and hand it over to the Government?

SHRI FRANK ANTHONY: Therefore preventive detention is the cutting edge. That is why I want preventive detention to be applied with regard to the maintenance of essential supplies.

I was reading a statement the other day of a very distinguished Economist. He said that if the level of man-days that were lost during the unfortunate Janata regime in 1979 could be brought down even by half, you can add between 500 and 1000 crores to your production. The man-days were lost by, as I say, professional labour agitators —union leaders competing with one another. That is why I say that there also preventive detention should be applied very much more.

And may I say this,—I am almost ending—I read an article that in Britain they were suffering from runaway prices, and this article said 'We wish we could import an Indira Gandhi into this country with her Emergency' because, during the Emergency, Indira Gandhi had done, in the first year, what was very necessary for the country. As I argued before the Shah Commission, in the first year the Emergency was the best thing that happened to the country. In the second year, as I conceded before the Commission, there were certain aberrations but in the first year what happened? You found that the Emergency gave the country much needed discipline. Let me say this, that we are among the most undisciplined nations in the world. Let us be quite frank. But during the first year of the Emergency we had respite from hoarders, blackmarketeers and profiteers, the constituents of Mr. Vajpayee's Party, the much-needed respite from professional agitators who themselves have not, usually, earned any honest penny. I will not tell you what happened when I cross-examined one of the most outstanding labour leaders in this country he is now a member of one of the leading Parties; he never earned money all his life, he never paid income-tax all his life: suddenly he became a Minister. And I put to him the allegations, about what had happened to him after he had become the Minister. Anyway, let that go.

What happened during the Janata rule? It precipitated decay: all round; slack in every direction, administration, the services, the police, and rampant, corruption; that is the terrible legacy which Shrimati Indira Gandhi has received; it is more than a full plate; it is going to take a great deal of time to correct this slack.

My last submission is this. Do not think, when I plead for preventive detention, that I think that it is anything internally good. I think, preventive detention is an evil. I have always spoken against it. But in the conditions of the country today, it is a very necessary evil, And I feel that you must always have judicial review, a judicial scrutiny. That is why I was one of the people who had condemned so much that unfortunate majority judgment of the Supreme Court in Shukla's case. Before that, even during the Emergency, even during the suspension of Fundamental Rights, the High Courts—nine of them—said, we will scrutinise; judicial review is our function". They struck down every case with one bad ground; I think, I did 14 cases in the Delhi High Court; where on one irrelevant ground detention was struck down. So, preventive detention, as I say, is an evil, but it is not an unqualified evil, it is a necessary evil today, and that is why, wherever you have preventive detention, you must have judicial scrutiny. If also you have an Emergency in Assam, I would be all in favour a review of Shukla's Judgment. So, that there also,

you will have judicial scrutiny. I know that preventive detention is abused; I know that either from motives of vindictiveness or motives of sheer venality people are preventively detained. But, as long as you have the courts, there will always be the safeguard, the safeguard that preventive detention will not be applied venally or vindictively; one bad ground or one irrelevant ground, detention will be struck down.

Emergency in Assam is long overdue and preventive detention should be applied much more fully in the country generally.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Frank Anthony, you have not moved your Cut Motions, though you have made the speech. Mr. Tytler.

SHRI JAGDISH TYTLER (Delhi Sadar): Mr. Deputy-Speaker, Sir, what is happening today is nothing but an extension of the hangover of the mismanagement of the previous regime, the regime of what was called the Janata Party. I am not going to make a political speech. But I have a few suggestions to make for the consideration of the hon Home Minister; and if he thinks that they are worthwhile, then he can take them into consideration. But, before I do so, I would like to give an analysis of the situation prevailing before the Janata Government took over and when the Janata Government was in power. I will start with the communal situation.

From 218 communal incidents in 1974, the then Congress Government had brought the number down to 186 in 1977; during the period under review, the number of deaths due to communal riots had been brought down from 87 to 36. Compared to these figures, the moment our friends Opposite, the champions of democracy, took over the reins of the Government, the number of communal incidents shot up to 230 in 1978, with the number of deaths going up from 36 to 110. 1979 was no better in respect of communal tensions. There were 304 incidents with 261 deaths. These are the figures pertaining to communal tensions only. Of course, when the new Government took over nobody expected that the situation in law and order and mess they left would improve suddenly. Naturally, it will take some time before the situation is brought under control.

Sir, coming to the labour situation, industrial unrest which had shown a sudden spurt with the withdrawal of emergency showed a slight sign of decrease in 1979. Though the percentage of violent incidents increase to an all-time high 15.7 per cent as compared to 11.6 per cent in 1977. The percentage of violent incidents in the first two months of 1980 was 9.4 per cent but this should be viewed in the context that what we have inherited from them is a complete mis-management which only our leader Shrimati Indira Gandhi can improve and save this country from, the situation they had left. Time will only bear testimony to what I say.

Sir, coming to student unrest—I am little hesitant to mention about it —since the time Mrs. Gandhi took over we have not had any student unrest. I do not know whether the Opposition will take a clue and start something. During the Janata regime in 1979, 9,200 incidents took place of which twenty per cent were accompanied by violence. This was particularly true in the State of Assam, Punjab, West Bengal and Kerala. As in the case of labour, during the first two months of this year there were 1800 incidents of which 15 per cent turned violent.

Sir, much has been said about Assam. It is not right for me to repeat what the Opposition members and our own Members have spoken but I would like to find out from the Hon'ble Home Minister which is the party or which is the regime which led the situation to what it is today in Assam. Who are the people who are responsible for the happenings in Assam? It is a strange thing that Central Government has no control. Central Government says that Assam is out of

[Shri Jagdish Tytler]

control. The local administration is a complete failure. Universities are closed. The schools are closed. The factories are closed. People are not allowed to say anything outside. Even our refineries are closed and the only thing which is working is: 'shakhas'. Strange! How is it that with all the powers we cannot get things done in Assam and only RSS shakhas are being held and I believe they are increasing day by day. I do not say that these are the only people who are responsible for what is happening in Assam. The Home Minister has suggested—he has even said in his speech in the Question Hour—that there are foreign elements and powers which are responsible for what is happening. I would say if the Home Minister has a clue or they suspect—they have their own agency to find out—any foreign power or any foreign diplomat is involved, I think, we should ask them to pack-up and close the diplomatic relations straightway. These are the hard steps which you may have to take otherwise things are not going to be done. Until and unless you come strongly on the agitators who are agitating not only for Assam people but also for people with more dirty designs behind it.

It is completely one thing to break away from us. If anybody tries to do that, may be from our party or from the Opposition party, he should be locked up. This is what I would suggest.

Coming to the rape case which we hear from the newspaper everyday—of course it is horrible crime—it should be condemned. In fact atrocities on women who are our sisters, daughters and mothers, should be condemned by all. I would like to ask the Opposition Leaders and the Press, when a mass killing happened in Tripura, how much did they protest and how much did they grill the Government? You know what happened in Tripura. Are the people there not part and parcel of our brothers and sisters? Are they not part of our family? I think such a thing should be condemned by all even if the things involved is one or two here or there. Who is responsible for this? (Interruptions) It is the government which is running there which is responsible.

Coming to the crime situation, I would say that the Opposition Leaders too whenever such a crime against women takes place or a rape case is brought to their notice they should help us and the police in trying to catch hold of the culprit responsible for that. I would ask the Home Minister that if he cannot bring forward a Bill, at least, he should issue an Ordinance as it was done in the case of Shah Commission etc., to which I wil come later. Whenever a crime against women takes place or a rape case comes, why not the judges of the High Courts or the Sessions Courts or the Lower Courts take up the cases on a priority basis? I think the trials should be held day to day and the culprit will have to be brought to book and should also be severely punished. It should not be taken lightly. I hope the Home Minister will take note of this.

Coming to Delhi proper, I am not going to defame anybody on what is happening in Delhi. But that is not a nice thing. People here are feeling insecure. There is a strange thing that has happened. Whenever a robbery takes place in Delhi or whenever a crime takes place or whenever an assault takes place, it is the leaders of the Janata Party—not the public, not the police—who know it first. I do not know how they come to know. I am not even stating that there is connection between the Janata Party and the crime incident. It is for you to judge.. I will give you one instance. I took the hon. State Home Minister to one or two places in Kirti Nagar and Model Town, where a robbery had taken place. A very interesting thing happened. We had gone to a house. The Home Minister was there. There

were a lot of people collected there. There were some ladies who had just come in and said that they saw a dead body lying in front of a woman they pointed at a little distance. The hon. Home Minister and myself wanted to visit the spot then. We were told that ~~that~~ there was nothing of that kind and a group of women were buying vegetables. We know who were the people who were spreading the rumours. This is not something new. To-day it is this kind of rumour which is spread. I would not like to cast any aspersion on the press. But there is one incident that took place in Kirti Nagar. But the press has blown out this incident out of proportion. As reported a person was robbed and his daughter was dragged from the house and shots were fired. We had gone there to see the spot. It is not that I am making a mockery of the poverty. But, I was surprised to find that the house about which the newspaper had printed in their publication had hardly any *charpoi* to sit on. That house belonged to a very very poor person. May be, he did not have one rupee in his pocket. But the things were presented in such a way. Of course local leaders, Janata leaders, R.S.S. leaders were there. They did give a different version to us. The things were stolen from there. When we had gone there to see the house, we asked the people there as to what happened. They said that some people were running shouting *'chor chor'* And somebody fired a few shots. One of them said that when his daughter went to the bath room, somebody tried to snatch things from the house. This is all to the story. Compared to this what we read in the papers or what was pointed out by the RSS people while demonstrating in front of the police station was completely false. I am not saying for a moment that the whole reporting concerning crimes is wrong. No. Not at all. I would like the Home Minister to take note of the fact that we need drastic changes. During the last three years when the Janata party was in power we would like you to investigate the officers who were taken; the police constables and sub-inspectors and so on who were taken. Just find out their background, their communal feelings and their association and you will come to know, what the Janata party has done.

Now, I am coming to the Grants which the Home Minister has asked for. I would like to say that even the police people are feeling insecure and why are they feeling insecure? Because in the three years of Janata party rule—I wish my colleague Shri Jethmalani should have been here because I am one person who had seen how he operated through Government machinery and this is one of the reasons that the police is demoralised and they cannot do it because they were made political and they were used. I know how they were used. Let him deny if it is wrong that they had not taken a room in the Janpath hotel. We got a Youth Congress boy to look on the room. We kept a watch on the room. How the witnesses were harassed**....Let him deny that.

AN HON'BLE MEMBER: Whisky to whom?

SHRI JAGDISH TYTLER: Whisky to the witnesses. I was once present in the Kissa Kursi Ka case hearing. We had protected a witness where CBI people used to harass them. What happened as soon as he had given his evidence in the court of law before Sessions Judge**

I do not want to comment on them. This is for everybody to judge what the result is. Why it was done—but I would like to tell you that as soon as the witness, a prominent witness in Kissa Kursi Ka case, came out of the Judge's room our late leader

**Expunged as ordered by the Chair.

[Shri Jagdish Tytler]

Shri Sanjay Gandhi who knew every trick these people were playing to try to bring false cases against him and against Shrimati Indira Gandhi and other Congress leaders. He said, "You surround this witness because he is going to be whisked away." Six or seven of us surrounded that witness and did not allow the witness to be touched. You know what happened! The police registered a case against us of kidnapping a person and on top of that at 12 O'clock at night that witness was taken from his house and brought back to the den. I would call it a den which they had kept in the Janpath hotel where they spent the exchequers money. We would like to know who paid for the liquor and other things?

Sir, coming back to the newspaper reporting about which Shri Jethmalani said I do not at all give credibility to what he has spoken because the same paper had mentioned something about Vajpayee, that when Vajpayee wants to visit a foreign country**

I say I do not want to give credibility to that thing and neither want to give credibility to what Mr. Jethmalani says.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I am prepared to face any inquiry.

SHRI JAGDISH TYTLER: Sir, Mr. Vajpayee has not listened to the latter part of my sentence. I say I do not want to give credibility. May be I am trying to save you which I should not.

Now, the most important part which I am coming to is the suggestions part and I would like the Home Minister to make a special note of it. Sir, we have the National Defence Fund. What do we have for the police people when they retire? I think Rs. 5,000 or Rs. 10,000 is the maximum that a constable gets who is all the time facing danger. I would like the Home Minister to get funds allotted or they can get more funds and create a national police fund which should take care of the policemen who get disabled during performance of their duty and to take care of the kith and kin of those killed in action to look after their children for purposes of scholarships and look after the people when they cannot get jobs. I would like the Home Minister to attend to this, because this is a very necessary thing. Because, until and unless you create the credibility of the police men in the eyes of the public, until and unless they feel that they are secure, they cannot perform their duties. Government may come and Government may go, but we are going to make use of them. I would also like the Government to make sure that the police officers are not used by any political party, might be our party, might be an opposition party. Let there be an ordinance, let there be anything else, saying, the police officer should be used only to look after the welfare of the people for which the treasury pays, for which the people pay, they pay income-tax to the treasury and so on. The police officer should be there exclusively to do his duty. Of course, a very strange thing is happening in our police force. We do have some different branches. There is a Detective branch, there is a CBI branch, there are so many branches. But whenever there is a shortage of one constable in one police station the Police Department does not hesitate to bring in a detective to take his place, as a constable. What I am trying to say is this. If the Home Minister does not give credibility to the post they are holding, the qualifications they hold, how do you expect the policemen to perform their duties?

In the end I have to make one more suggestion, Sir. If you take the ana-

**Expunged as ordered by the Chair.

lysis of the communal incidents, atrocities on harijans, backward classes. minorities and so on, you will find that as our colleague Mr. Subramaniam Swamy has put it, there are some fifty districts in the whole country which are involved. Why can't we create Peace keeping force for those districts? These peace keeping force may comprise of representatives of the weaker sections, harijans, minorities and others in equal proportion. Mind you, I am not saying that any particular portion of the society should not form a part of this peace keeping force. A beginning can be made by each State constituting one or two battalions depending upon the size and the requirements. Such a force needs to be exclusively used for maintenance of communal harmony and prevention of atrocities against weaker sections. In this whole exercise, the hon. Home Minister must try to involve the local people in the Peace-keeping force. I say this because this is very important. In Delhi there was a committee which was attached to each Police Station. But these have been removed now. I don't know the reason for it. Since I belong to Delhi, I would like to say this, that the Peace-keeping force attached to the police station should be brought back.

With these words I conclude my speech. I support the Demands for Grants of the Home Ministry.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Tytler, although you said 'It is a maiden speech', yet, you have made a very good speech.

Now, regarding certain things, like mentioning of some hon. Member of the House, I will go through the proceedings. If anything damaging or something other than parliamentary is there, I would go through the proceedings and I will expunge them. This is general.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is what I said.

(Interruptions)

SHRI JAGDISH TYTLER: Excuse me, I might say this since he has brought up the subject, she was very much there.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have said already. You must know that it is a maiden speech of Mr. Tytler; then you may not take very much objection to it.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Unless these remarks are expunged they are likely to be reported by the Press. Only the other day hon. Speaker had called a meeting of the Leaders of Opposition. The Treasury Benches were also represented there.

MR. DEPUTY-SPEAKER: If Mr. Jagdish Tytler has mentioned about family members of any hon. Member of this House, I would go through it I have told you already. Those things will be expunged.

Now, Mr. M. Satyanarayan Rao.

SHRI M. SATYANARAYAN RAO (Karimnagar): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am rising to speak on the Demands for Grants of the Home Ministry. I support the Demands for Grants of the Home Ministry. This Home Ministry is a very important Ministry. Some people may say that this Ministry does not deal with the economics of the country, but compared to other Ministries, I consider it more important because the performance of the other Ministries depends on the performance of this Ministry. If the Home Ministry fails, then everything goes wrong. We have noticed the experience of the Janata Government. When they were ruling the country, they failed miserably in so far as the administration by the Home Ministry was concerned. There were failures on all fronts and everything had gone

[Shri M. Satyanarayan Rao]

wrong and ultimately the Government had to go. That is why I give so much importance to this Ministry.

In this regard I would like to submit that we have inherited so many bad things from the Janata Government. As has already been pointed out by my colleagues here, it was during the regime of Janata Government that all these things happened. I am very sorry to bring to the notice of the august House the demoralisation of the Police officials. About whatever is happening in this country, I do not say that it is happening only now; but it had happened during the previous regime also. There were crimes during Janata regime. But because of the poor performance of the Janata Government and because they took certain steps against police officers, it demoralised the whole machinery. As soon as they came to power, they appointed many Commissions. They were not interested in the development of the country; they were interested only in seeing that somehow or other our leader, Mrs. Gandhi was put behind the bars. They were interested in putting behind the bars other leaders also. Their concern was that during the Emergency those officers who were acting as per the orders of the Government were to be put behind the bars. Immediately after they came to power, they took certain steps for constituting Shah Commission and other Commissions. That was the only thing in which they were interested. They were not interested in developing the country. The people of this country elected them to serve this country, to develop this country, to chalk out certain programmes which would benefit the country. They did not do that. They were concerned with instituting criminal cases against our leaders and others. The police people were very much demoralised when they found that their officers—DIGs. and I.Gs. also in some places—were put under lock-up and were hand-cuffed. The Sub-Inspectors and other small police personnel were silent spectators. They were not taking any action against the criminals and after the Janata Government came to power they released all the smugglers, dacoits and the black-marketeers who were put behind the bars during Emergency. After they were released during the Janata Government regime, they indulged in all kinds of anti-social activities and lawlessness.

SHRI SATISH AGARWAL (Jaipur): This is wrong.

SHRI M. SATYANARAYAN RAO: That is why you are there. Otherwise your Government would have continued.

SHRI SATISH AGARWAL: As regards the release of smugglers, they were released on 21st March, 1977, the day the Emergency was lifted.

SHRI M. SATYANARAYAN RAO: Mrs. Indira Gandhi released the leaders of other parties, but not the smugglers, blackmarketeers, etc. All these people were behind the bars. You please go through the record. The hon. Home Minister is here and he will tell you about this. He has got all the records. You know all these things. That is why you are there. Otherwise you would have continued as hon. Finance Minister with your Janata Government. I pity you, but I cannot help you. These are the things which were done during Janata regime and all sorts of atrocities like rape on women, etc., are happening new because of the release of those anti-social elements, smugglers, etc.

Here I would like to mention particularly about atrocities on Harijans during the Janata Government regime. During this period the landlords had started acting against the Harijans. I do not know about other places, but about my district and my State, Andhra Pradesh, I do. The so-called landlords became very bold. They used to tell the Harijans "Now your *amma* is not there; you cannot go to anybody; you do whatever we want,

otherwise we will kick you, beat or even kill you." These were the threats given by those people to the Harijans. The same thing must have happened in other districts also. That is why so many atrocities took place during the Janata regime. We had allotted land to these poor people, Harijans, Girijans and backward people. After the Janata Party came to power, they were trying to snatch away that land forcibly. The poor Harijans and others naturally resisted. They thought that this land had been allotted to them, they had become the rightful owners. Why should they be deprived of that? In that protest, these people, the poor people, got killed. The Belchi incident occurred because of land dispute only. These atrocities were committed during the Janata regime and are still continuing also. I would request the Home Minister to see that these atrocities are not committed against the poor people, particularly Harijans and Girijans. I know the Home Minister has been taking certain steps in that direction and these have been indicated in the report also. These people must be protected under all circumstances. Of course, I do not support Shri Frank Anthony when he said that even prevention detention should be used or something like that or emergency should be declared. I do not want emergency to be declared in this country under any circumstances for such purposes. But I do support any measures in order to protect these people. You must bring before this House any legislative measures that you consider necessary in order to protect these poor people and those would be supported uanimously. All of us are very much interested in protecting these Harijans, Girijans and other weaker sections.

Then, there were a number of communal incidents that took place during the Janata rule, for example, at Jamshedpur, Aligarh and several other places. And, they are blaming us now as to what we are doing in order to curb such incidents. In our regime also. such incidents have taken place; I do not say that there were no such incidents, but during Janata rule many communal incidents took place and there were lots of atrocities against these people. This was because Jan Sangh party was a part and parcel of the Janta Party. The communal outlook of that party is known to all of us. That party was responsible for all these things and that is why so many incidents took place then. Now, of course, we cannot have any excuse; we must see and ensure that these incidents do not occur in future.

I will now touch upon the Assam situation. It is a very serious situation. We have debated this recently on last Friday, the non-official day. Shri Parulekar also participated in that. Some hon. Members have been saying that it is a political question and should be dealt with politically. I do not agree to that. Definitely, certain political issues are involved. but at the same time, economic issues are very much involved. Without economics there is no politics. As I said on that day, the economic development in that region did not take place at all. Economically, that region, whether it is Assam, Manipur, Tripura, Meghalaya, or Mizoram they are quite backward. They have been completely neglected after independence continuously. We must take steps to see that proper developmental activities take place in that region. The Home Mininster is responsible for the Union Territories also and I would request him that unless you develop that region, bring about industrial and agricultural development and improve their conditions, you cannot solve this problem. however much you may try. The agitation which has been going on there, unfortunately, has fallen in the hands of unsocial and anti-national elements. You must take steps to see and find out who these people are. My friend,

[Shri M. Satyanarayan Rao]

Shri Tytler has just demanded, on Friday last we all demanded, the Government to find out who was the power behind it? Who are the parties behind this agitation? Our hon. Minister mentioned about the RSS: Though it is there, I do not blame it completely because they do not believe in the secessionist movement; they believe in Akhand Bharat. They are the people with national outlook. I do not blame that party. Then, who is responsible? There must be some party. We say that the students are good people, people with national otulook, but they have become prisoners in the hands of certain other people. Who are those people? You must clarify that. You must identify them.

You are evading this question. There was a calling attention motion; there was a question. In spite of all these things, you have only said that there seems to be some big power behind them; there seins to be some political parties. But you are not mentioning their names. Now the time has come for mentioning those things in your reply when you reply to the debate.

When our party came into power, our leader Smt. Indira Gandhi took immediate steps. She sent our hon. Home Minister to Assam to have a talk with them and to negotiate with them on this issue. Not only that, she invited those people also who were agitating. She also went there. In spite of all these things, they are not coming for this negotiation. I only request this whole House, don't think that this is a political matter: this is not a political issue. If you are really interested in the integrity of the nation, then you must stand as one man, all parties, irrespective of this party or that party, so far as Assam problem is concerned. Let us make an appeal to the people of Assam; let the whole House make an appeal to the people of Assam, to the students there.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are 35 members from your party.

SHRI M. SATYANARAYAN RAO: I was under the impression that I will get more time. Anyhow, I will finish within five minutes. My request to the hon. House is that let us make an appeal to them, all parties together, to stop this agitation. I am happy that the agitation has been suspended. Let them come to Delhi for negotiation with our government. Our government is very sympathetic towards their cause, their economic development. Unless they are economically developed, this problem cannot be solved. Ultimately, this is the problem of employment, because they are not having opportunities of employment. So, this agitation is there. I request the hon. Home Minister also to consider this problem sympathetically

Regarding Mizoram, I am very happy that he has met our hon. Home Minister and the Prime Minister and says that he will cooperate with the government; he will also see that MNF activities will be stopped there. In this respect, I am told that Brig. Sailo is also very happy at this outcome, but at the same time, he entertains some doubt about his sincerity; whether he is sincere or not, it seems he has cautioned. In spite of all this, I would only request the hon. Home Minister to see that they come together. If they come together, the Mizoram activities will cease. Mizoram is a very backward area; that should

also be developed. I will not touch that point. I will take up the National Commission on Police, because everything depends upon the police. Every day, Opposition members are bringing forward matters against the police people saying that they are not taking any action. Rapes are taking place. In fact, police people themselves are involved in rape cases and other cases. I will request through you the Home Minister to see that certain facilities should be provided to these police people. We must realise the difficulties of the poor Constable After all, what is his pay? That is not sufficient for the duties which are assigned to him. Almost 24 hours they will have to work What you are paying to them? You are paying nothing; as a matter of fact, you are paying more to a peon in the banks They are not getting much pay. Unless you satisfy them, you cannot expect them to perform their duties well. My request to you is that you plase see that their amenities are increased.

I was also a member of the State National Police Commission in Andhra Pradesh. We have submitted our report there suggesting that investigation should be separated from law and order situation in the sense because what happens in the police station is this. Once a Sub-Inspector is there, that Sub-Inspector has to go a village, where any crime has taken place; whether it is a dacoity or whether it is a murder or something else. Then the same man will have to go to the court. That is why he is not able to attend to his duties properly. (*Interruptions*) That duty is also there whenever a Minister comes. Whenever a Minister goes there, he has to attend to the duty of bandobust. That is why my appeal to the hon. Minister is that this should be separated from the maintenance of the law and order duty. Maintenance of law and order should be separated from investigation; then only you can expect good performance from the police people.

Regarding pension to political sufferers, Prof. Ranga was keen about this; the sum of Rs. 500 p.m. was mentioned. In genuine cases you can increase it by Rs. 200 or 300. But there are so many bogus cases. At least in my district, some bogus cases have come to our notice. Because of that there is a budren on our Exchequer. Please find out who are the genuine political sufferers and help them; I am one with Prof. Ranga that their pension should be increased. There is difficulty since there are bogus political sufferers also. This should be taken into consideration.

Which are the parties getting foreign contributions? It is a serious matter. I know certain people are visiting foreign countries; some go to China, to Pakistan, to America and other countries. How are they going, with whose money? If at all those countries are giving, what is the source? Do you know the activities of those people? Which countries are contributing, how much? It will be dangerous. In Assam also something is happening; it may happen in other states also.

Lastly, the Home Guards. They are playing a very useful role; you have sanctioned five lakhs; there are only four lakhs or so. You must utilise all those people who are registered in the home guards not only in districts but in cities and the rural areas also; they are playing a very good role.

SHRI K. ARJUNAN (Dharmapuri): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to say a few words on the demands for grants of the Home Ministry on behalf of the DMK party. At the outset, I should like to say

[Shri K. Arjunan]

that as an ex-police personnel I have to frankly admit that the needs of police personnel and specially the state police personnel are being neglected...

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your party has been allotted 16 minutes; you conclude within 16 minutes.

SHRI K. ARJUNAN: The service conditions, the pay and allowances of the state police personnel are far below compared to these of police personnel and their employees of the Central Government. My suggestion is that this difference should go forthwith if we want policemen to maintain law and order properly. Now-a-days the Press, the politicians and the cinema are all accusing policemen. Policemen are also human beings; they are recruited from amongst us. They are not recruited to commit rape or molestation. You should recruit good persons and give proper training and give them attractive pay. Then there will be change in the image of the policemen. Is everyone of us a perfect gentlemen in every institution? Politicians, pressmen and cinema men are tarnishing the image of policemen. Is our politician or pressman or cinema omnipotent? They are also committing crimes but there is no enquiry. We are not discussing about the call girls. They are a menace to decent people; we are not discussing about them, or why they solicit people. But if there is a report about a policeman, there will be a hue and cry that policemen are doing this and policemen are doing that; the opposition political parties will say that it happened to a Harijan girl and it happened to a Harijan woman. If you go on accusing like this, naturally policemen will not go to seek criminals and law and order will not be maintained. I do not mean to say that policemen should commit such atrocities; I am not defending the guilty. Those who commit attrocities should be severely punished, specially if they commit rape or molest people when in the custody of the police. Political parties in the opposition take political advantage to bolster up their image by accusing the police force. No policeman will maintain law and order if you find fault with policemen for each and everything.

KADITHOCHI MELLA VERIKA NEDITHAKKA NEENGARANA VENDUBAVAR

The guilty should be severely punished. At the same time the innocents should not be punished.

If you go too near the fire, it will burn you. On the other hand, if you go too far away, you will not get the warmth and support. If you go on suppressing and accusing policemen, your hands will be burnt. Similarly, if you ignore their genuine grievances, you will lose their support.

The strength of policemen has not been increased. The equipments have not been modernised. At each police station there is one sub-inspector, one head contable and ten constables. They will have to look after *bandobast*, investigations, court, village Bad Character check and everything Their strength should be doubled. I am saying this because now-a-days there are a lot of agitations—by the union people like trade unions and others. There are several troubles in the industrial areas. Police faces a lot of trouble. Whereas the strength of the police should be increased, the number of vehicles for patrolling should be increased as the number of vehicles is also quite inadequate to meet their demand. Each police station should be supplied with a van.

Our films in all languages tarnish the image of police. They are made a fun of. It creates a bad impression. "To make fun of human frailties is no crime. But to make fun of human failures is really a crime." "Police is always at the receiving end. It is a helpless force." I request you to redress their genuine grivances and raise their image.

In regard to pay, I may submit that the figures supplied in the First Report of the National Police Commission by

its Chairman Shri Dharma Vira, are pathetic. The Driver of the nationalised bank is getting Rs. 690 p.m. and the Clerk is getting Rs. 730 but the Delhi Police Constable is getting Rs. 328 p.m. If you compare this the policemen is not getting even half of what is being taken by the peon of the nationalised bank. An employee in the Public Sector Undertakings in Bangalore gets Rs. 723 p.m. but the policeman is getting Rs. 350 p.m. The constable should be rated as a skilled worker and suitable pay structure should be evolved.

Weekly off is not given to the policeman. He is expected to work for all the 24 hours. Overtime allowance is not given. Special qualification pay is not granted to him. He should be given full travelling allowances. Eight hours duty should be insisted only. The police man is working 24 hours and weekly off is not given. This is not fair. Extra remuneration or overtime allowance of Re. 1 to 2 per day is given to them. This is quite inadequate.

Regarding housing, in our country not even 50 per cent of the non-gazetted police personnel have been allotted housing. In Bihar it is 4 per cent Punjab 10 per cent, U.P. 15 per cent, Delhi 20.7 per cent and in other States, it is slightly better than this. So, I request that provision of housing facilities should be given top priority. The policemen are finding great difficulty in securing houses, because they have to pay excess rent. Their house rent allowance is just Rs. 30 a month but they have to pay Rs. 100 or 150 for a house. Also, the house-owners have got certain rules and procedures, which the policemen will have to follow. Hoarders, criminals and anti-social elements are house-owners and the policemen have to mingle with them because they are residing in their houses. How can they act freely? So, immediately a police housing corporation should be formed and the construction of houses should be speeded up. The present house rent allowance is meagre. So, free accommodation to all policemen, including the higher officers should be given. Policemen's Cooperative Housing Societies should be formed and adequate funds should be allotted for this purpose. The orderly system should go.

Regarding policemen's association, this is not a trade union. It is just meant to represent the grievances of the policemen. So, there should be no outsiders as members of the union. Only serving policemen should be members of the union. The police union shall not resort to any coercive method, agitation and indiscipline. It should be non-political and proper election should be conducted for the association.

The most important aspect is training Nowadays policemen are not given proper training. That is why this sort of allegations and accusations are coming from all parties. Enough fund is not allotted for the training. Policemen are treated like harbour coolies in the police training college. Proper persons are not selected and inadequate training is given to them. The teachers in the police training college and police recruitment school are selected from the police personnel. Only unwanted elements are selected for this purpose. Improper treatment during training is given. Sufficient funds are not allotted. That is one of the reasons for the accusations. I will take the Home Minister to the P.R.S. at Coimbatore so that he can see the status and treatment given to policemen. Those who teach at the training college should be given at least Rs. 200 as additional pay because they do not get TA and other facilities in the training college. Experts in the various fields should be recruited as teachers in those fields. Experts in medical jurisprudence, IPC, psychology and other fields should be employed as teachers. Policemen should not be allowed to teach. Only experts should be allowed to teach. If the Government looks after these basic requirements of training, the image of policemen will be better in future.

[Shri K. Arjunan]

In State Governments, a select list is prepared for promotion of Deputy Superintendents as IPS officers. This is valid only for one year. After the expiry of one year another list is prepared. That is wrong, because the juniors are able to find a place in the list due to political influence. The select list should be prepared for three years. Unless there is a proved charge of corruption or such thing against an officer and he is given punishment for that, his name should not be deleted from that list. Mere enquiry or allegation should not be the ground to delete his name from the list.

15 hrs.

To give enthusiasm to subordinate police officers, there should be 50 per cent promotion quota from the rank of constable to sub-inspector. If you do this, the image of the Police will be better.

At present, there is no reservation for backward classes in the All-India Services. It should be provided 10 per cent of the reservation should be given to he most backward community in the All India Service.

IPS officers are doing better job than the IAS officers. They should be posted as Secretaries in Central and Managerial posts such as tourism, transport, sugar cooperative factories, etc.. in the States.

I want to tell one thing about Tamil Nadu Police which was considered once second to Scotland Yard. Now, its image has gone down. The opposition party has no freedom in communication. The letters are being censored, telephone conversations are being tapped by SB CID Police. They recruit ADMK men as functionaries to abuse K. Karunanidhi and his family members in such a filthy languages which I do not want to mention here. It is also there in the SB CID tapes. The Chief Minister of Tamil Nadu is tapping the conversation like Nixon did in America, which was called Watergate scandal. Perhaps, he will also meet the same fate as Nixon. But I do not compare him with Nixon because he has got no such intelligence or ability as Nixon has. I would request the Home Minister to get it enquired from the CBI.

In Government functions, the Chief Minister of Tamil Nadu talks politics in the presence of the Governor. He accuses the DMK party. Once the Governor of Tamil Nadu had stated and expressed his desire that AIADMK was expected to come to power and he prayed to Lord Venkateswara for that.**

He should be transferred forthwith.

In my constituency, One Mr. Sivan, Headmaster of Kalappamadi School was murdered by 50 CPI men in broad daylight at his residence. The Headmaster and his wife requested for Police *bandobast* in advance. But the Police failed to do so. If the Police *bandobast* was there, the murder could not have taken place. The CPI is in alliance with the ADMK there. So far no action has been taken against the CPI volunteers who committed this murder. Yesterday, I received a telegram from widow Sanjeevi. In Mettur, the DMK Town Secretary, Shri Murugesan and his family members were beaten severaly by ADMK men. But action was taken against DMK men by the local police.. The police is partial. The Police force in Tamil Nadu including the IPS officers are dancing to the tune of ADMK men. A top offender under the Prohibition Act, is elevated as MLC because he was a ADMK men. Police is not in a position to enforce the Prohibition Act because the Government is protecting the prohibition offenders.

**Expunged as ordered by the Chair.

The activities of anti-social elements under the protection of AIADMK Government are rampant.

15.05 hrs.

[SHRI SHIVRAJ V. PATIL *in the Chair*].

Regarding Harijans, they have no protection under the AIADMK Government. The Untouchability Act is not enforced properly. By the existing law untouchability cannot be eradicated. Only by inter-caste marriage, socio-economic development can be achieved. The Harijans should be allowed to perform *puja* in all temples. Legislation was made by Shri Karunanidhi when he was the Chief Minister in Tamil Nadu. If you want the real socio-economic development of the Harijans, if you want untouchability to go, inter-caste marriages should be encouraged. Those who marry people from the Harijan families should be given job opportunities in all walks of life.

Regarding railway police, I am told that 50 per cent of the expenditure is shared by the Central Government and 50 per cent by the State Government. The railway Protection Force is nothing but watch and ward. They have no investigating power because the State Government is sharing 50 per cent of the expenditure They are not interested in handling the crimes committed within their jurisdiction in the railways. The strength of the Railway Protection Force is very very meagre. That is why the robbery and dacoity in the railways is rampant. So, the entire organisation should be with the State Government or the Central Government.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): Mr. Chairman, Sir, it is really my unique privilege to intervene when you are in the Chair. I thank you very much.

Sir, before I proceed with my intervention, it will be very relevant if I just point out and quote a few observations made by our Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi only a few days back while addressing the All-India Social Workers' Conference. She dwelt at length on the various problems that are facing the country and also the condition of the weaker sections and the other backward and Scheduled Castes and Scheduled Tribes. She said that her ambition is to give a new direction to the country and make it stronger. The country would not become strong and powerful if the majority of the people remain weak socially and economically. Therefore, it is of the utmost importance that their lot should be improved.

Referring to the atrocities on Harijans in the country, she said:

> "Many causes should be attributed. People who have for long enjoyed all the benefits of the country could not tolerate the Harijans trying to improve their socio-economic status and the right to come on par with them."

These are the main points which she has mentioned only a few days back.

Under the leadership of Shrimati Indira Gandhi, during the last elections our Party got a massive mandate and the faith of the weaker sections and Scheduled Castes and Scheduled Tribes is complete and total in so far as her leadership is concerned. So, it has been our endeavour to see that not only facilities are given to them, but also that the services attune themselves to the new situation, so that they not only get adequate representation in the various services but also get the confidence that their interests are protected.

The Department of Personnel with which I am concerned is connected

[Shri P. Venkata Subbaiah]

with the nodal and substantive function relating to the infrastructure of the machinery which is going to implement Government policies.

There are more than 35 lakhs of Government servants, and you can imagine how complicated and complex are the problems faced by us in this department. The services have got a very heavy responsibility in implementing new policies and programmes for which, as I have already mentioned, the people have given us their mandate.

The successful implementation of our policies would naturally depend upon the way in which the services attune themselves to the new challenges before them. For this purpose the services have to reorient themselves to the changes in the environment and the challenging tasks before them to acquire the motivation and capability to acquit themselves in a creditable manner.

The bureaucracy, as we call them, whether it is at the Centre or in the States, comes in for severe criticism for various acts of omission and commission in the discharge of their day to day responsibilities. The services, therefore, have to keep in mind the fact that their first and foremost duty is to see that the weaker and vulnerable sections of our society are given all the protection needed and that they have faith and confidence in the interest and sincerity of the Government and its executive arm in implementing the programmes for their uplift and welfare.

Besides this it is necessary to involve all sections of society in the tasks of nation-building, and for this we have to provide adequate opportunities to the weaker sections for joining the various services, including those involved in law enforcement.

To instil a sense of confidence in the fairness of recruitment, it will be pertinent to point out that the UPSC, which is the primary recruiting body for higher posts in the Government, is headed by an eminent person who comes from the scheduled caste, while the previous Chairman hailed from a minority community. The first Chairman of the other main recruiting agency, namely the Staff Selection Commission, was a person belonging to a minority, and the new Chairman of this Commission also hails from a minority group, and is a lady. For considering the claims of the minorities and other backward classes, the Minorities Commission and the Backward Classes Commission have already been entrusted with the task of making recommendations in this regard. Government will be able to take a view on these recommendations as soon as the reports of these two commissions are received.

This House had an occasion to discuss the report of the UPSC, and many valuable suggestions were made by the Members in the course of their speeches. We have already forwarded these suggestions to the UPSC and requested them to take expeditious action wherever feasible.

As Members of the House are aware, a new scheme of examinations for recruitment of IAS, IPS and other civil services has been introduced last year based on the report of the Kothari Committee, whose report was also placed on the table of this House. It will be of interest for the members to know that the new schemes has been so modelled as to attract meritorious candidates with a rural background and from weaker sections. The salient features of this system of examinations are : the paper on English is of matriculation or equivalent standard and qualifying in nature, the marks in this paper are not counted for the competitive ranking; option to answer the subject papers either in English or in any of the Indian languages included in the Eighth Schedule to the Constitution has been given to the candidates. The marks allotted for optional papers have sought to reduce the weightage of papers in general studies. The optional papers carry 1200 marks

while general studies papers carry 600 marks. The Interview Board can allow a candidate to answer in an Indian language if the candidate so desires because of his inability to express adequately in English. The upper age limit has been raised from 26 to 28 years. The additional papers of post-graduation level for IAS, IFS including the old scheme of examinations have been dispensed with in the new scheme of examinations.

The Ministry is responsible for taking measures to give proper representation in the service to Members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Constitutional provisions enable reservation for these classes of persons in the services.

Even though complaints and apprehensions have been voiced that the measures taken so far have not led to adequate results, I want to emphasise the fact that within the framework of the reservation orders, considerable progress has been made during the last 20 years. We have to remember that while reservations have been there since long, such reservations have been extended to posts filled by promotion, both by seniority and selection only in the last decade. It is also necessary to have an adequate number of suitable personnel in the lower grades who are fit for promotion to higher grades. This is necessarily a gradual process and we shall get a large number of suitable candidates in course of time. I may tell the House that it is a matter of great satisfaction that as far as recruitment to the top civil services for the country such as the IAS, IPS, IFS services and other central services are concerned, in recent years, we are getting adequate number of suitable candidates belonging to the scheduled castes for filling up all these reserved vacancies. However, in view of the fact that reservations in promotions have been provided for only during the last few years and also due to the fact that certain segments such as scientific and technical posts in Group A services were completely exempted from the reservation orders till 1975, the overall representation still appears to be low. We are now taking special steps to impart special coaching on pre-examination and pre-selection training for members of scheduled castes and scheduled tribes so that they can better equip themselves for making themselves suitable for the civil service under Government for which recruitment is made by competitive examinations and selections. With the increase in the number of such persons in the lower and middle groups, they are becoming available in increasing numbers for promotion. In order to equip them better for appointment and promotion to higher posts, in the matter of in-service training, we propose giving them their due place and ensure that they take full advantage of the training schemes. What I want to emphasise in this House is, on the whole we have made a considerable progress specially when we remember that the reservation was only 12 1/2 per cent and 5 per cent before 1970 so far as the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are concerned and it has now been increased to 15 per cent and 7 1/2 per cent. In order to continuously monitor the progress in this regard and also to examine in depth the reasons for short-falls, a high-power Committee under the Chairmanship of the Prime Minister has been constituted to periodically review the situation and give different directions to the various Ministries for appropriate action to ensure that the representation orders are given effect to in a realistic and fuller manner. For instance, for appointment to the reserved posts of Under Secretaries in the Central Secretariat, a special examination was held exclusively open to the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and 27 officers were appointed in the reserved vacancies of 1978 and 31 in the reserved vacancies of 1979.

The progress in this field will be evident from the fact that from 1971

to 1980, the number of officers belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Indian Administrative Services has increased from 190 to 373 so far as Scheduled Castes are concerned and from 80 to 170 so far as Scheduled Tribes are concerned. In the Indian Police Service, the corresponding figures are 102 to 216 for Scheduled Castes and 28 to 82 for Scheduled Tribes. In the appointments made in 1979 on the results of combined competitive examination, the entire reserved quota of 18 per cent and 10 per cent for Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been completely filled up. This is also so in the case of Indian Forest Service, Income-tax Service and Indian Customs & Central Excise Service.

In the totality of the picture, the representation of Scheduled Castes has exceeded reservation percentage in group 'D' services and is reaching that level in group 'C' services. Only in higher groups 'A' and 'B' services, in view of the fact that reservations in promotions were provided for much later, the overall shortfall is slightly higher and special steps are under way. In regard to group 'B' services, the Ministries which are in charge of services and posts for large-scale recruitment have been asked to take special measures to intensify pre-selection coaching and training so as to enable the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to fully take advantage of the reserved posts.

One of the other significant measures provided for is to carry forward the reserved vacancies for a period of three recruitment years in case suitable members of these classes are not available for appointment in the first year. There seems to be a slight misapprehension in regard to de-reservation of these vacancies. By this method, we ensure that even though there may not be a suitable candidate available from the reserved classes for appointment during the first year, the orders provide carry forward of the reserved vacancies for the next three recruitment years so that suitable candidates as and when they become available are appointed against such reserved vacancies. At the same time, the posts have to be filled up by general candidates so that the work of the Government can go on which may not be achieved by keeping these vacancies unfilled. As far as the reserved categories are concerned, these vacancies are still available for being fully filled in only by these categories in the second and third year also.

I will be failing in my duty if I do not pay a compliment to the members of the services for their determination and for their hard work put in by them. They have always risen to the occasion in this task and I have no doubt in my mind that they will give their fullest and utmost cooperation in implementing the policies and programmes of this Government.

One word more, before I conclude, with regard to creation of new all-India services. The All-India Services Act, 1951 was amended by Parliament in September, 1963 to bring within its scope the creation of three all-India services, namely, the Indian Forest Service, the Indian Service of Engineers and the Indian Medical and Health Service. The Indian Forest Service was constituted with effect from 1st July 1966 and all the State Governments are participating in it. Orders constituting the Indian Medical and Health Services with effect from 1st February 1969 had been issued but action to constitute the State cadres and to make initial recruitment thereto could not be taken up by the Government of India as some of the State Governments which had earlier agreed to participate in the Services subsequently either refused or withdrew their consent or expressed certain reservations about the need for constituting the services.

No formal orders constituting the Indian Service of Engineers were issued because a few State Governments which had earlier agreed to participate in the Service expressed their disinclination to take part in the Service. The then Janata Government felt that addition to the list of all-India Services would not be consistent with the policy of decentralisation—or, for whatever reasons they have done it, we do not know. Therefore, in March 1978 the then Government decided that the question of constituting the all-India cadres of Indian Medical and Health Services and the Indian Service of Engineering should not be pursued. But I may tell you in this connection that this matter is engaging the attention of the present Government of Smt. Indira Gandhi and we are earnestly looking forward to making some headway in this direction.

With these few observations I may reiterate that the Government of India in the Ministry of Home Affairs, under the leadership of the Home Minister Shri Zail Singh, is doing its utmost in all spheres to provide the necessary conditions for the protection of the weaker sections, the minorities and other backward communities. Whatever steps are required to do this and also to implement the progressive policies of the Government are being taken with utmost care, taking all the factors into consideration. I once again thank you for giving me this opportunity.

SHRI CHINGWANG KONYAK (Nagaland): While I rise to support the Demands for the Ministry of Home Affairs, I would like to make a few observations for the consideration of the Home Minister. Firstly, I would like to start with my own State. Ever since the British Imperial power had transferred the best portion of our territory into their own jurisdictions in order to achieve their objective and to gain the maximum economic benefits, our people have been demanding to return our land transferred to other Districts of Assam from the then Naga Hills district. In 1960, a memorandum was presented to the then Prime Minister, the late Shri Jawaharlal Nehru. The Naga delegation discussed with the Government of India the question of restoring those areas which were transferred by the Britishers. They were told that this referred to the provisions in Art. 3 and 4 of the Constitution, prescribing the procedure for transfer of the areas from one State to another. Now it is running 17 years since Nagaland attained Statehood but, so far, nothing has been done to solve the boundary problem of Assam and Nagaland.

Because of this, every now and then there is a trouble along the Assam-Nagaland border. A few years back there was an exchange of fire between the Assam armed police and the Nagaland armed police, and you are all aware that on 5th January, 1979 there was firing and killing in border areas resulting in the loss of many lives. Unfortunately, just after the 5th January incident, during the Janata regime both at the centre and the State of Assam instead of solving the problem, they created more problems by allowing the Assam Government to construct the roads in the disputed areas all along the border. That has further hurt the sentiments of the Naga people. Our people have been demanding setting up of a Boundary Commission to settle this long-pending problem. But it appears that the Centre is not taking this issue seriously. In this year's Home Ministry's Demands for Grants also, no provision has been made for setting up of a Boundary Commission. If the Centre is not serious about solving this problem, then who will solve this problem? And how long will this problem be kept pending and how long should the people living on the border continue to suffer? I, therefore, urge the Home Minister to set up a Boundary Commission to settle this issue once and for all.

Now, coming to the second point, that is, in regard to the north-eastern

region, during this Session many Members of this august House have spoken with deep concern on the situation prevailing in the north-eastern region and have asked for special attention to be given to develop the north-eastern region, realising the importance of this north-eastern region for the security of the country. The north-eastern region has international boundaries, with China, Burma and Bangladesh, and this region is a very sensitive area. In fact, we can call this north-eastern region as the sentinel of India. But, despite its strategic importance, no special effort has been made to develop this region and to bridge the communication gap between the north-eastern region and the rest of the country. As compared to the other parts of the country, this region still remains socially and economically backward, even after 30 years of independence. So, the people of that region feel that they are neglected and they are not looked after properly. Seeing the discontent of the people, the inimical forces are working quietly; they are encouraging and helping some of the local people to keep this insurgency movement alive in the north-eastern region, and are also instigating some of the local people to create more and more peoblems in this region.

The problems which we are facing in the north-eastern region are not merely law and order problems and, therefore, should not be treated or taken only on those lines. These problems are complex; they are human problems, they are political problems; no doubt, they are also law and order problems. Therefore, these problems should be tackled as such, and these problems need the immediate attention of the Government of India. But, as I see today, the Home Minister is overburdened with the problems of the rest of the country, specially with the problems happening in the big States. Because of those problems, less attention is given to the problems of this region; because of those problems, the Home Ministry is not in a position to give full attention to the more serious problems of this region. Unless we have a separate Ministry to look after the North-Eastern region, our problems will always be overshadowed by the problems of other big, big States and if we delay this, more and more problems will come up. I, therefore, urge the Prime Minister through you to create a separate Ministry to look after the North-Eastern region for a speedy development of the region and to effectively deal with the problems of the region and this Ministry should be personally looked after by the Prime Minister herself who knows the peoples and the areas of the region. If this is done, I am confident that with the sympathetic and imaginative guidance of our Prime Minister, it would not only ensure socio-economic progress but further strengthen the unity and integrity of the country.

Thirdly, I would like to say a little about the problem of the underground. During this session we have been discussing about the north-eastern region's problems and many had said that secessionist tendencies have come up among the people of the region. That is a fact. Therefore, to curb this tendency and also to curb the infiltration of the undergrounds who are living across the border inside the Burmese territory, I suggest to the Home Minister to get more funds to raise more Village Guards in the border areas. Because only these Village Guards can be able to deal effectively in the border areas. Our people who are living in the border areas, if they are recruited into these Village Guards and if they are properly trained and equipped, I am sure the people of that area who know the problems, who know the terrain and who know the tactics of the underground, can fight the tactics of the underground elements.

Fourthly, I would like to say a little about the Assam situation. Much has been said about the agitation in Assam. I would like to remind the hon. Members of this House that this

problem is a complex one. There is no doubt that there is a genuine problem the people of Assam are facing. But the agitation at the moment said to be against the foreign nationals is not purely on the foreign national issue Among the Assamese people there are also some like the Ahoms who are saying, 'We have never been in India. So we must start this secessionist movement'. Here you may recall the 1955-56 communal riots between the Bengalis and Assamese. Still among the Assamese this feeling is there. I come from Nagaland and my constituency is very near and I used to pass through their place very often and I used to mix up with these people and inquire what is their actual feeling and what is the actual problem. So, this is a complex one. Therefore, it is not only a foreigners issue but the feeling against the Bengalis is there and there are some people who say, 'We have never been in India and along with Nagas and Mizos we must work to go out from India.'

So, we have to be very careful and Home Ministry has to instruct the Administration to deal effectively with the problem. Lastly, I would like to reply to some of the points raised by some of the Opposition Members yesterday and today.

Sir, yesterday, Shri Dhaniklal Mandal, former Home Minister was charging the Government that the dissolution of the 9 State Assemblies was unconstitutional. I do not know whether he would call the dissolution of the Congress Governments in 1977 as constitutional or not. I would like to remind the hon. Members of the Opposition that we acted according to Constitution. We are following the very same thing as they did during the Janata rule.

About an hour back, Shri Jethmalani was mentioning about a Minister going to a swimming pool in Bombay in a Five Star Hotel. I think there is nothing wrong if a Minister goes to a Swimming Pool. But, I would like to tell this House that in 1977—I would not mention the name of the Minister—one of the Janata Ministers came to Nagaland with one young lady. The people there mistook her to be the wife of that minister and offered her shawls etc. The Minister was staying in Raj Bhawan at that time. We came to know a little later that the lady was a socialist Member. In the Nagaland Assembly of which I was once a Member there was a discussion about this. This was what happened and so the Raj Bhavan should be cleaned as it was adulterated. I am telling this because the Ministers of the Janata Government used to bring this socialist lady to Nagaland whenever they visited Nagaland.

MR. CHAIRMAN: Shri V. Kishore Chandra S. Deo.

You have thirteen minutes.

SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO (Parvathipuram): Mr. Chairman, Sir, I rise to speak today on the Demands for Grants of the Home Ministry when a chaotic situation is prevailing throughout the country. Everyday when you read the newspapers you will find that in all the front pages, news is splashed about atrocities on women and scheduled tribes, backward class and harijans that are committed.

Mr. Chairman, before I deal with this, first I would like to discuss about the North-Eastern region which has been charged with a lot of violence in the last few months. I had myself been to Tripura and I was there for four or five days. Of course, as far as that is concerned, we will be giving a full report. I would like to know from the hon. Ministers as to what they had been doing all these days ever what happened there. In Tripura the trouble has not started either yesterday or the day before. It has been brewing since three or four months. The State Government has been writing and sending reminders to the Central Government to send

Central forces there. I do not know whether the Central Government has any sort of intelligence agency working at all in the north-eastern region of the country. We have the international border with Bangladesh. In Mizoram we have the insurgent elements getting trained even by the Chinese and they are trying to indulge in such insurgent activities. Yet, all this was happening and the State government's request went unheeded. The Central government did, not have an inkling of what was happening there in Tripura last month.

The Assam situation is now continuing for a long time and the situation in Assam, according to my personal information, has also definitely had its impact in Tripura because it is only after that agitation started, that the chauvinistic tendencies of the Bengalies in Tripura also gained momentum and it is only after this that even the tribal Tripura leaders started demanding for a cut-off year and expulsion of foreigners, etc. This was not there in their earlier demands. Why was this trouble allowed to go on in Tripura? I ask. The hon. Home Minister had the wisdom of audacity to declare that the Central Government is capable of handling a hundred situations like the one in Tripura. You sit here in Delhi and declare that you can handle a hundred such situations. Think of what is happening in Assam. Things have been allowed to drift. The student leaders are prepared to come and discuss the issue over the negotiating table. Why don't you release those 28 student leaders who were put in prison? This is not the way. If you want to solve the problem, you will have to do things in a pragmatic way and a consolidated plan has to be chalked out for the entire north-eastern region and the Central government has also to give a lot of aid to improve the economic conditions of those areas which are largely dominated by very backward and economically backward people and tribals who constitute a large portion of the population of those parts.

Coming to other parts of the country, in the capital city of Delhi crimes have been increasing every day. While the crimes have been increasing over here, our Police Commissioner has found time to go to Moscow for the Olympic games. I really wonder how the Home Minister has been left behind. When the members from that side were sitting with us here, when the Belchi incident took place, Shrimati Indira Gandhi took all the trouble to ride on an elephant to reach Belchi. Then they made a lot of political capital out of the Narainpur incident. But what has happened in Baghpat? What has happened in Unnao? What has happened in Durg? And the list is endless. I just cannot go on reading out the names of the various places where atrocities have taken place. What have you done about them?

One should go into the reasons why all those atrocities have been taking place. Recently, the Police in U.P. have been recruiting a large number of people from Hoshiarpur district which happens to be the constituency of our Home Minister and also from Gurdaspur district which happens to be the constituency of another hon. Member of this House who happens to be the wife of the Police Commissioner. If you start recruiting people from your respective constituencies and if you supersede 150 to 200 officers and make some one the Inspector General of Police, what will be the morale of your Police force? Mr. Bhinder was made Commissioner of Police superseding about 150 senior Police officers. Is this, how you are going to keep up the morale of your police force?

In Bihar 6 Yadavas were beheaded by some miscreants. So far no action has been started and no inquiry report. When the elections were going on in Bihar, the brother of an MLA, Mr. Ram Saran Yadav was shot dead by a DSP. What have you done about that? Have you

taken any action? This is how things are going on.

To supporters of the Congress-I in Sehore Assembly constituency in Sitamarhi district of Bihar burnt down quite a lot of huts of the Harijans and they killed one person and prevented the people from going to the polling booth. What action has your government taken so far? Even the FIR was not filed and no inquiry started...

MR. CHAIRMAN: FIR not filed?

SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO: FIR has not been registered by the Police. The Police have refused to register the FIR.

Then, Sir, what is happening in Andhra Pradesh? Andhra Pradesh never had any communal riots because it is a peaceful State. There, in the capital city of Hyderabad, after Dr. Channa Reddy's government came to power, there were two communal riots. Only two cases were reported. But several other instances were there in the State. Several crores worth of properties were destroyed. Several people were killed. Andhra Pradesh has never witnessed such things before. Now such sorts of things are gaining more and more momentum. And what did the Prime Minister do? At that time Mrs. Gandhi did not even offer any lip sympathy to these communal minorities of Andhra Pradesh. I do not know what she intends to do just now.

As far as the Home Ministry is concerned, I wish to point out one thing. In the whole country we have almost 52 per cent people belonging to the backward classes. But they have not got their proportionate representation in the Police Service and other Government services. This should be looked into. These are the facts which I wanted to mention. If I have to refer to fully to the bad law and order situation, even if you give me 12 hours, I will not be able to cover all the points. The Home Minister cannot solve any problem by just uttering *shairis* in the House. While trouble is going on in Tripura, he just comes here, and makes a statement saying that he is capable of controlling hundreds of such situations. Why should he make such an irresponsible statement? We have had enough of this. It is high time you did something about it or you quit your post.

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं आज यहां महिलाओं के बारे में कुछ बातें कहना चाहती हूं। आजकल हमारे भाई जो महिलाओं के बारे में बहुत बोलते है पता नहीं वे हमारी महिलाओं के बारे में क्या सोचते है। जिन बातों के बारे में व यहां बोलते है उनमें तो महिलाये बहुत पीछे है। हमारे अपोजिशन पार्टीज के भाईयों को भी और हमारी पार्टी के भाइयों को भी यह सोचना चाहिये कि महिलाओं की किसी बात से इज्जत कम न हो। मैं अपने अपोजिशन के भाइयों से कहती हूं कि हमारी महिलाओं को सड़कों पर न लाया जाये। आज जब हम अखबारों में ऐसी बाते छपावते है, या पार्लियायेंट में ऐसी बातें लाते हैं तो उससे हमारी बहिनें एक्सपोज होती है जो कि नहीं होनी चाहिये। जो बातें हमें महिलाओं के लिये करनी चाहिये वे तो नही हो रही है, जो नहीं करनी चाहिये वे बातें हो रही है। जिस तरह से पोलिटिकल पार्टी के लोग अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं उसी तरह से वे महिलाओं की भी इज्जत बनाये। औरतों के साथ जो रेप की घटनायें हो रही है या एट्रोसिटीज उन पर हो रही हैं यह तो कोई भी रजीम रहा हो होती रही है। जनता का रजीम रहा हो या कम्युनिस्टों का रहा हो, होती रही हैं। लेकिन अब जरा कम हो रही है, हमारी प्रधान मंत्री की लीडरशिप में इन में कमी आई है। जनता के रजीम में बहुत ज्यादा हुई थीं। ये बिल्कुल न हो इसकी आपको कोशिश करनी चाहिये। मैं किसी को दोष देना नहीं चाहती हूं। जो भी गवर्नमट हो औरतों को इज्जत देना उसका कर्तव्य है, भारत देश का कर्तव्य है। मैं अपोजिशन पार्टी वालों से भी विनती करती हूं कि वे भी हमारी बहनों को जरा इज्जत दें। आप भी जरा हमारी तरफ से बोलिये। जो कुछ हो रहा है उस पर आप भी जरा सोचिये। यह सोसाइटी की रिसपांसिबिलिटी है, किसी पार्टी की रिसपांसिबिलिटी नहीं है। जब इस तरह की घटना हो जाती है, महिला पर अत्याचार होता है तो मैं यह पूछना चाहती हूं कि हम क्या करते है हमारे भाई क्या करते हैं। किसी गांव में इस तरह की घटना होती है तो हमारे भाई लोग क्या करते हैं। एक महिला के साथ रेप की घटना हो जाती है तो सब यह कहते हैं और सरकार को दोष देते है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि जिस गांव में वह घटना घटी है उस गांव में जा कर आपने क्या किया है।

हमारे बारे में वहां चिल्लाना ही काफी नहीं है। गांव में जिन लोगों की वजह से वह घटना घटित हुई है, जो उस में इनावाल्व्ड है, उनको पकड़ने के लिये और उनको पकड़वाने के लिये और सजा दिलाने के लिये आपने क्या किया है? कौन सा प्रयत्न आपकी ओर से हुआ है। अखबारों में इस तरह की घटनायें जब छप जाती हैं तो यहां पर उस सवाल को उठाया जाता है। एक महिला होने की दृष्टि से मुझे यह अच्छा नहीं लगता है कि इस तरह से उसको उछाला जाये। उनकी जो समस्यायें है उनको कैसे हम सातव कर सकते है, यह सब को सोचना चाहिये। हम जनता के प्रतिनिधि है। महिलाओं की जो समस्यायें है, जो रेप केसिज है, जो एट्रासिटीज उन पर होती है, वे किस तरह से बन्द हो, इस पर हम सब को गम्भीरता के साथ सोचना चाहिये। यह काम केवल इस सरकार का नही है बल्कि यह जो रिसपांसिबिलिटी है वह सारी सोसाइटी की है और सारी सोसाइटी को आगे आना होगा और रक्षा के उपाय करने होंगे।

हमारे देश में अलग अलग रिलिजंज के, अलग अलग कास्ट्स के लोग रहते है। हिन्दुओं में एक आदमी एक ही शादी कर सकता है। लेकिन कुछ रिलिजंज और कुछ कास्ट्स ऐसी भी है और जहां आदमी दो दो, तीन तीन और चार चार शादियां भी कर सकता है और कर लेता है। इस तरह से महिलाओ की इज्जत नही बढ़ती है। मेरा सुझाव है एक भाई को एक ही शादी करनी चाहिये। दो और तीन शादियों का जो सिस्टम है, यह जो बिगामी है इसको खत्म कर दिया जाना चाहिये। मेरी होम मिनिस्टर से विनती है कि बिगामी को खत्म कर क्या जाना चाहिये। इससे हम महिलाओं की इज्जत बढ़ेगी। मेरा सुझाव है कि स्पेशल मैरेज एक्ट जो 1954 का है वह सभी रिलिजंज और कास्ट्स पर लागू होना चाहिये ताकि एक भाई एक ही शादी कर सके, दूसरी शादी न कर सके। ऐसा करने से हमारी महिलाओ को इज्जत मिल सकती है।

हमारे भाई जितना काम करते हैं उतनी ही काम हम महिलायें भी करती हैं। लेकिन एग्रिकलचर में, इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि हम को उनके बराबर वेजिज नहीं दी जाती है। ईक्वल वेजिज फार ईक्वल वर्क का सिद्धान्त अपनाया जाना चाहिये और महिलाओं को भी पुरूषों के बराबर वेजिज दी जानी चाहिये।

सर्विसिस में भी महिलाओं को कम संख्या में लिया गया है। उनकी संख्या को वहां भी आपको जरा बढ़ाना चाहिये। जरा ज्यादा हम को सर्विसिस में मौका मिलना चाहिये।

पुलिस में भी महिलाओं का परसेंटेज जरा बढ़ाना चाहिये। मेरी होम मिस्टिर से विनती है कि महिलाओं को पुलिस में ज्यादा संख्या में लिया जाना चाहिये। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक जो घटनायें महिलाओं के साथ हो रही हैं, उनको आप कम नहीं कर सकेंगे।

डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, 1961 का जो है उसका मैं समर्थन करती हूं। मैं कहना चाहती हूं कि प्राहीबीशन एक्ट है हम प्राहीबीन और डाउरी नहीं चाहते, हमारा कहना है कि महिलाओं के लिये लीगल राइट टू प्रापर्टी होनी चाहिये। जब तक यह नहीं देगे तो जो इस प्रकार की दुर्घटनायें होती है, वह कम नहीं हो सकती हैं। इसलिये जब लीगल राइट होगा, तो जो आदमी महिलाओं को छोड़ते है उनके बारे में भी सोचना पड़ता है। मेरा कहना है कि जो भाई बहनों को छोड़ देते है, उसके लिये लीगल राइट होना चाहिये। जब लीगल राइट होगा तभी हम अपने समाज में अपने पांव पर खड़ी हो सकती हैं। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि प्रापर्टी में लीगल राइट दिया जाये।

16 hrs.

रिमूवल आफ अन टचेबलिटी का एक्ट भी है। वह अंडर आर्टिकल 338 है, उसके लिये हम काम कर रहे हैं। समाज में हम सारे इंसान एक ही हैं। हमारी स्टेट में हरिजनों के सेफगार्डज भी दिये हुए हैं। जो हरिजन भाई या बहिनें अदर कास्ट में मैरिज करते है उनको सेफगार्ड हमारे समाज में देना पड़ता है। जो नान-हरिजन हरिजनों में मेरिज करते है वह हरिजन का नाम भी नहीं लिखना चाहते है। इसलिये हम कास्ट्लैस सोसाइटी चाहते हैं। ऐसा करने वाले बहुत लोग हैं, उनको सेफगार्ड मिलना चाहिये और जाब्ज भी मिलनी चाहिये। महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिये उनकों जॉब्ज दी जानी चाहिये, मंत्री महोदय से ऐसा मेरा सुझाव है।

बौंडिड लेबर के बारे में मै कहना चाहती हूं कि 66 परसेंट आफ दी वार्जेड लेबर हरिजनों में से होते हैं। यह तो अच्छा नहीं लगता है। इसके बारे में भी हमें सोचना है। सेल्फ एम्पलायमेंट स्कीम जब तक इन्ट्रोड्यूस नही करेंगे तब तक बौंडिड लेबर को हम नही निकाल सकते हैं। बैंक्स वगैरा से लोन लेने के लिए उन को सिक्योरिटी देनी पड़ती है, और सिक्योरिटी देने के लिये उनके पास प्रार्टी नहीं होती है, वह सिक्योरिटी तो गवर्नमेंट को ही देनी हैं। यह होगा तभी हम बौंडेड लेबर को हटा सकते है। बौंडेड लेबर को निकालने के लिये सोशल आर्गेनाइजेशन्स और सोशल वर्कस को, जो गवर्नमेंट की कमेटी होती है, उनमें लेने से अच्छाई हो सकती है।

सेल्फ एम्पलायमेंट स्कीम में कुछ बहनों और भाइयों को काम दे सकते है। बहिनों को कुछ काम करने के लिये हमारे समाज में और अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये। जब बहनें काम करेंगी तो वह भी पैसा कमा सकती हैं और अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। इस चीज की तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिये।

हमारे कांस्टीट्यूशन में एबलिशन आफ अन टचेबलिटी के लिये आर्टिकल 338 है, इसमें शिड्-

यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये व्यवस्था है। जनता के रिजीम में एक कमीशन उन्होने बनाया था, उसकी क्या पावर है और हमारे शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज के लिये क्या पावर है? डबल रोल हो रहा है। इसलिये इन लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिये कमीशन को क्या करना है, यह भी हमें सोचना है यह हमारा सजेशन है।

एट्रोसिटीज और महिलाओं के साथ रेप वगैरा जो होते है, उनको मिटाने के लिये हमारे गांव और टाउन में पीस कमेटी होनी चाहिये। जब तक हम पीस कमेटी नही बनायेंगे, वहां पर कोई रैस्पोसेब्लिटी नहीं लेता है। यह कहते है कि गवर्नमेंट की रैस्पोंसेबलिटी है। जब तक समाज रिस्पोंसेब्लिटी नहीं लेगा तब तक गवर्नमेंट के लिये काम करना मुश्किल होगा। इसलिये पोस कमेटीज को स्थापित करना चाहिये और इस तरह हम समाज के बैड एलीमैंटस को निकाल सकेंगे।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): I am thankful to the hon. members who have participated in this debate of the Ministry of Home Affairs. Many hon. members have made very good suggestions and we have taken note of them. But there are some criticisms from the opposition benches and that criticism sometimes was quite unhealthy. Therefore, I want to give particular outlines of what the Ministry of Home Affairs has done during this period of six months.

After assuming office maintenance of law and order was given top-most priority by this Government. A review of the functioning of the Police as a law and order enforcement agency. therefore, was immediately called for. The hon. members are aware of the serious inroads into the discipline of the Police Forces during the previous regime and its adverse impact on law and order was naturally felt by the people at large

Law and order is a State subject as such, it is primarily the responsibility of the State Government to maintain law and order in their respective States. However, faced with constraints of finance, the States could not provide adequate resources for the modernisation of their police. The Central Government, therefore, took the initiative in 1969 and formulated a scheme for providing assistance to the State Governments for modernisation of their police forces. From 1969-1970 till 1973-1974, the pattern of assistance was 25 per cent grant-in-aid and 75 per cent loan. However keeping in view the importance of the scheme the pattern of assistance has been changed to 50 per cent grant-in-aid and 50 per cent loan. The amount is intended to enable the State Governments to meet any urgent law and order situation which they are unable to deal with within their own resources. Central assistance of the order of over Rs. 52 crores has been provided to the States upto 1979-80. The present Central Government have agreed to the continuance of the scheme for another 10 years with the proposed outlay of Rs. 100 crores.

Central assistance to the extent of over Rs. 78 crores has been provided to the States since the inception of the scheme till 1978-79. States have also spent Rs. 88.93 crores from their own resources. The present deficiency is for 3.86 lakh houses for police personnel. The previous government had transferred the scheme from the Central to the State Sector from 1979-80. However. considering the importance of the scheme and the States' inability to provide all the required funds in their plans, we are seriously thinking to revive the scheme in the Central sector which had lapsed during the year 1979.

Keeping in view the urgent need for upgrading the standard of police administration in the country, the 7th Finance Commission have recommended a total outlay of Rs. 252 crores, consisting of Rs. 169 crores of revenue expenditure and Rs. 83 crores of capital expenditure. The revenue expenditure will enable 9 States to upgrade their standard of police administration. The Capital expenditure would enable 15 States to provide residential accommodation to police personnel. The Revenue expenditure is intended to increase

the strength of civil police or strengthen Home Guards Organisation etc. and to improve staff training, welfare transportation, aquipment and aids to scientific investigation.

During 1979-80 a total amount of Rs. 1063 lakhs was sanctioned to the state governments; during the current financial year the amount sanctioned was Rs. 1114 crores. The Governments of U.P. and M.P. have already launched extensive programmes for providing training to police personnel and to reorient their attitude towards the public by introducing basic as well as refresher courses for all levels. In the centrally run police training institutions like national police academy, institute of criminalogy and internal security academy, Mount Abu courses are in progress for officers of the level of DYSP and above to reorient their approach.

Many things are said about Northeastern states by the hon. Members I would like to give a brief account of what is going on in the Northeastern states. The northeastern region of our country has been in a disrupted state for sometime now. Certain misguided elements took recourse to violence and caused unrest in Nagaland. Mizoram and Manipur. After the signing of the Shillong Agreement 1975, there has been peace in Nagaland. In Mizoram fresh initiatives have been taken to open dialogue with MNF. At the same time government are determined to maintain peace and to protect the lives of peaceful citizens in Manipur. The state government have been given all help to speedily bring the situation under control and deal firmly with miscreants.

For over ten months now, Assam has witnessed an agitation over the foreigners' issue. Development activities in Assam and also in the northeastern region have been seriously affected. A climate of suspicion, distrust and bitterness has engulfed the entire state. Anti-national and anti-social elements have taken advantage of the atmosphere created by the agitation and have caused large scale violence in which several innocent people lost their lives and many rendered homeless. Government have been striving hard to persuade the agitators to give up the path of agitation and have spared no effort in this regard. The agitators have been assured time and again that government was not rigid in its approach and that the issue could be solved through discussions. Government still hope that saner counsel will prevail.

The climate of violence created in Assam has had its fall-out in other parts of northeast, especially in Meghalaya and Tripura. In Meghalaya the state government has taken effective steps to deal with the situation. There was a sudden outbrust of violence in Tripura in which over 540 persons lost their lives and over 600 were lujured. The central government is rendering all possible assistance to the state government to meet the situation and provide speedy relief to those affected. Government are fully aware of the need for speedy economic development of the region. At the instance of the Prime Minister a Committee of Ministers and an official level committee were set up for this purpose. They have already been meeting and taken certain decisions which are being followed up.

The Government of India is deeply concerned about the problems of the scheduled Castes and are conscious that they are subjected to the dual oppression of economic exploitation and social discrimination. Government also realise that there is a clear nexus between the weak economic condition of the Scheduled Castes and the atrocities and social disabilities of which they are the victims. The atrocities against them are not sporadic or accidental phenomena, but are rooted in obvious and endemic socio-economic factors. The Home Minister has conveyed to the States a very clear analysis of the basic cause of the atrocities against the Scheduled Castes.

It is a measure of the Government of India's earnestness and seriousness about the rapid economic development of the Scheduled Castes that the present Government expeditiously commenced Special Central Assistance to the States Special Component Plans for the Scheduled Castes. The Hon'ble Members may have noticed the provision of Rs. 100 crores made for this purpose for 1980-81 at page 75 of the document of Demands for Grants of this Ministry which is before them. As Hon'ble Members are aware, the State Governments have been asked to prepare optimal Special Component Plans. The Prime Minister has impressed upon the Chief Ministers/Governors of the States the importance of the Special Component Plans and has emphasised the need for the rapid socio-economic development of the Scheduled Castes by her d.o. letter of 12th March, 1980. She has stressed that thereby 50 per cent of the Scheduled Castes should be enabled to cross the poverty line within the Sixth Plan period. The focus is on categories like agricultural labourers. leather workers, fishermen, handloom workers and other artisans, small and marginal farmers including share croppers, *safai karam charis*, who form the vast majority of the Scheduled Castes and who are in the greatest need of developmental assistance. Shortly after that, Special Central Assistance was commenced in order to give direct and tangible support to the States for the formulation of optimal Special Component Plans and their effective implementation. The Government are anxious that the benefits should reach the Scheduled Castes. Therefore. the quantum of Special Central Assistance to the States will be related to the size and content of their Special Component Plans. In particular, their efforts and performance will be taken into account. Thus the Special assistance will have a multiplier effect on their State Special Component Plans and thereby will catalyse the economic development of the Scheduled Castes. The State have also been told to provide in their Special Component Plans for removing the developmental lag of the Scheduled Castes in the matter of education, especially at the primary and adult levels; drinking water; electrification of the Scheduled Castes habitations, housing and slum improvement. The States have been asked to go about the task in a very systematic manner, indentifying the developmental needs of the Scheduled Castes families, preferences of identified beneficiaries, market opportunities, etc. with co-ordinated and composite approach ensuring all necessary linkages. I am myself visitng State after State and discussing with the State Ministers and officers the Special Component Plans and pointing out to them where and how substantial improvements are possible and necessary.

While the thrust has to be on the development, especially economic development of the Scheduled Castes, we are also giving close and concentrated attention to the atrocities situation.

The Members had occasions to go through the comprehensive guidelines of the precaunonary and preventive, punitive and rehabilitative measuers communicated by the Home Minister in his D.O. letter dated 10th March, 1980 and its enclosures. These guidelines contain every aspect that we can think of and what hon. members have been rightly emphasising. For example, in para 10 of his D.O. letter to the Chief Minister/Governors, the Home Minister has emphasised the necessity to have an immediate special recruitment to bring up to the desired level the representation of the Scheduled Castes in the police force at all levels, especially at the cutting edge level, which particularly includes SHOs, Writers, Moharrers. Munshis, Head Constables and Constables. The necessity of this step in respect of certain other posts like those of village officers, Survey and Settlement Department, Revenue Department and Labour Department has also been stressed. During my visit to State Governments, I am

discussing with them not only the Special Component Plans, the Scheduled Castes Development Corporations and other developmental programmes, but also the implementation of the Home Minister's guidelines on atrocities. Both these aspects of development and protection of Scheduled Castes were discussed in detail in the meetings of State Chief Secretaries on 3rd April, 1980 and Chief Ministers/Governors on 8th April, 1980. The implementation of the guidelines on atrocities was also discussed at the meeting of the State Home Secretaries held on 15th July, 1980. We are pround that we have come to grips with the problem, but we are not complacent about the magnitude of the task. We trust that we shall have the full cooperation of all sections of this august House.

A number of hon. members have sponsored cut motions for the failure of Government to protect the life and property of scheduled castes and scheduled tribes and other religious minorities. Government appreciates the concern of hon. members over protection of weaker sections of the population. I may assure the House that the Government is as keen to see that the weaker sections of the population are made to feel secure. The Central Government has been addressing the State Governments to wield law and order machinery to ensure security for the weaker sections.

Since the Fifth Five Year Plan, Tribal Sub-plan has been in operation in 16 States and 2 Union Territories in the country. In brief, the Tribal Sub-plan consists of demarcating areas of tribal concentration and making extra physical effort with the help of extra financial resources. The approach of the Tribal Sub-plan is area development with focus on development of scheduled tribe communities therein. The Tribal Sub-plan areas in States have been split up into Integrated Tribal Development Projects, each of such project aggregated to a number of development blocks.

Guidelines have been issued that in preparing the project reports, the culture, tradition and customs of the scheduled tribe communities should be kept sepcifically in view as development programmes should relate to their occupation, skills and natural resources endowment. In other words, steps are being taken to ensure that while on the one hand all possible socio-economic development measures are taken to make the tribal communities self-reliant, at the same time the personality and individuality of the tribals is preserved.

Exploitation of tribals has been a bane of tribal economy. Since the tribal economy is essentially a subsistence economy, tribal families have had to borrow money from money-lenders in years of drought and scarcity.

To counter the nefarious activities of money-lenders, merchants, traders, middlemen, etc. large sized multipurpose societies have been organised with three-fold functions of purchase from the tribals his farm and forest produce at remunerative rates, sale to him of consumer necessities at reasonable or controlled prices and extension to him of production and consumption credit. Over 2000 LAMPS have started functioning in the country. Some of them have been rendering good service, but the performance of others has been indifferent.

Apart from agriculture, forest produce is the next major source of income of the tribals. State Governments have been advised to reorient forest policy to strengthen the tribal economy. Social forestry is becoming an important element of the forest policy. Secondly, forest labour cooperatives are to be encouraged so that tribals are able to derive a fair wage as well as a share in profits. It is hoped that these measures will go a long way in improving the economic development of the tribals.

Shri Verma has urged the need to accept the demand of the original inhabitants of Chhota Nagpur for a separate State of Chhota Nagpur and Santhal Pargana in Bihar.

The Government feel that such demands can only lead to fissiparous tendencies which can endanger ultimately the unity of the country. On the contrary, gains from such a move will be not only minimal but also illusory. What the country needs today has already been prescribed by the Constitution, *viz.* special attention for the backward and weaker sections. We can undertake this in a much better way within the framework of the existing political structure through such mechanism as the Tribal Sub-Plan. The Tribal Sub-Plan assures earmarked financial resources for special physical effort through specific administrative machinery. I do not think that much purpose will be served by creation of a separate State for tribals.

Many things have been said about Delhi and Delhi Police. The present Government inherited an awefully deteriorated law and order situation in the Union Territory of Delhi. The moral of Delhi Police force was low, the criminals had a free play and the citizens suffered from a sense of total insecurity. We immediately addressed ourselves to the task of extricating the law and order situation from the mess in which it had fallen by taking some immediate measures, like dividing the Union Territory of Delhi into two ranges, creating two new posts of Addl. Commissioners of Police, setting up of six new Police Stations, improving morale of the police force, sanctioning Rs. 2.8 crores for police housing, etc. and planning long term measures, like opening more police stations and police posts, creating new DAP battalions replacing a large number of condemned police vehicles, modernising Police/Traffic Control Rooms, strengthening the CID, other modernisation steps etc. While long term measures will yield results in due course, steps already taken have started showing results. Upto 15th July, 1980, when compared with the corresponding period of 1979, all heinous crimes, except murder have shown a steep decline. For example, dacoity has come down from 45 to 22, attempt to murder from 180 to 155, robberies from 345 to 184, riots from 170 to 99, snatching from 181 to 85, burglaries from 1609 to 1435. Crime under other heads, like thefts, motor vehicle thefts, miscellaneous IPC has also shown a significant fall. The police morale and vigilance has reflected in increased detections. 7275 cases were registered under the local and special laws upto 15th July, 1980, as against 6719 in the corresponding period of 1979. While quoting these figures, I am drawing on the same source of data which the hon. Members of the Opposition have used for criticising the functioning of the police force in Delhi. However, all will concede that there has been a significant improvement in the crime situation in Delhi, we are nonetheless conscious that more needs to be done. There have been legal impediments hampering effective functioning of the Delhi Police in spite of introduction of the Commissioner system. These impediments have to be removed and all other administrative and financial support must be there to make the force an ideal and efficient one for the Capital. For this purpose, I would solicit cooperation of all sections of the House to strengthen, modernise the Delhi Police and equip it with an infra-structure required to make it effective. This would include....

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): If you allow me to interrupt, I would say that only recently there was a news report about the meeting held by the Home Minister in which the prominent Police officials were present, and it was a report—it might be wrong—that the Home Minister is very much upset, and he said that 'there is a terrible deterioration in the law and order situation and you must take all possible precautions to see that the situation in Delhi improves'. If you throw some light on this, I would be very happy.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: You are right that the Minister showed his concern about this. But at the same time, it is not because there is more deterioration. It has improved, but we are not satisfied. -(*Interruptions*) This would include opening of new police stations, police posts, provition of more vehicles and equipment, modernising the scientific aids of investigation of crime, interrogations communications, monitoring traffic flow and its regulation, etc. We should also strengthen the intelligence support to the police for collection of the information regarding law and order and crime.

PROF. N. G. RANGA (Guntur): Weeding out of bad and inefficient officers is very necessary.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Yes, yes. We are doing all that. Though the Delhi Police had creditably remained aloof from the Police unrest of 1979, we must appreciate the hard work they have put in, the long hours of duty they have to perform, the stress and strain they have to undergo, the publicity attack they have to suffer and the nervous strain they have to bear, the Government is fully alive to the need of improving their welfare and conditions of service.

Sir, many Members referred to the Freedom Fighters' scheme and many Member suggested that the income limit etc. should be removed. Regarding that, I have to mention that the Government are well aware of the grievances of Freedom Fighters. The hon. Members would be pleased to know that out of 2.4 lakhs applications received, 1.18 lakhs applications have been sanctioned. 37,133 cases could not be finalised for want of adequate evidence or recommendations from the State Governments. These persons are given another opportunity to produce evidence so as to enable them to get their pensions. So far, 93,507 cases have been rejected because of lack of valid documentary evidence. The State Governments have set up Advisories Committees to find out bogus freedom Fighters. It has also been decided to extend the facility of drawing the pension through Public Sector Banks with effect from 1st August, 1980.

I would like to inform the House that Government are taking all positive measures to redress the grievances of the Freedom Fighters.

PROF. N. G. RANGA: When?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: In the near future.

With these words I request the hon. Members to pass the Demands of the Ministry and to withdraw their cut motions.

SHRI RATANSINH RAJDA (Bombay South): The way in which Shri Makwana read the speech just now so pathetically gave me the impression of a high school student reading his lessons.

That apart, the people of this country in general, and we in this House in particular, have been watching for the last seven months—193 days to be precise—the performance of this Government. People have been watching their performance since they came to power on the crest of a massive mandate as they call it by promising that they would give a government which governs. They told the people to vote for a government which governs, they told the people that they would establish law and order in this country. Now, at the end of 193 days people are very much dismayed.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN (Satara): You are counting days?

SHRI RATANSINH RAJDA: The days of the Government are numbered.

The performance of the Government during this time is before the people of this country, and we can take a detached view, not with a view to pull down this Government, not to criticise merely for the sake of criticism, but to find out the truth, whether there is real performance by the Government,

whether this Government has governed this country, whether this Government is capable of governing and delivering the goods. That is the problem I am posing today before you and through you to the entire country.

The performance of this Government can be judged on the basis of their approach to problems. People are crying hoarse that there is tide of violence throughout the length and breadth of this country. I have tried to hear the case of the Government, I thought I should do justice to them. If there is a case, if there is some evidence and if there are arguments to substantiate that evidence, I would have very much appreciated it. Instead of giving substantial arguments, only one thing has come out. Whenever any member of the ruling party or Minister speaks, he has got only one argument, namely that whatever is happening today, whatever bad is taking place, is because of the past performance of the Janata Party. If this is the burden of their song, I may tell them with the due humility and with the full strength at my command that the reins of power have been with them for seven months now and even after this time if they give the same excuse of something wrong done by the previous Government, that is not going to help them. Merely chanting Janata, Janata is not going to help. People are now very much dissolusioned and therefore the earlier you give up the parrot-like chanting of Janata, Janata, the better it will be for you. Please address yourself to the tasks ahead. Do not put the entire blame at the doors of the opposition parties and their leaders. Please tell us what concrete things you have done and people are there to judge you. I am reminded of one couplet. You are very fond of sher:

आती है मुझ को हंसी हजरते इंसान पर
कारे बद तो खुद करे लानत करें शैतान पर।

AN HON. MEMBER: I congratulate the hon. member for calling the Janata Party *'Shaitan'*. (*Interruptions*)

श्री रतन सिंह राजदा : मुझे मालूम नही था कि आप लोगों की इतनी कम अंडरस्टैंडिंग है...

(व्यवधान) शैतान आपकी पुलिस है, आपकी मशीनरी है। दूसरों की बात आप क्या करते हैं।

I think the hon. Members feel uneasy when I am telling the truth. If that is not palatable to some of the hon. members, I can't help it.

There is a tide of violence throughout the country and there are certain statistics. Every time, statistics are flung at the opposition parties to show that the crimes are much less than they were during the previous regime. Actually, that is not so. We should take a detached view. Let us see the way in which the press is describing the present situation. The unprecedented crime wave is of such a magnitude that such crimes of rape by police have never taken place in any previous regime during the last thirty years, not only during Janata regime, during earlier regimes also. We should all hang our heads in shame. Instead, you are trotting statistics to show that the crime wave is much lessened. Just now I tried to understand Makwanaji. His only pet thing was to give figures to show that the crimes are much less as compared to the number during the previous regime. May God bless them, but I wonder, God is not going to bless them, if they go on in this way.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur): God will bless them by sending them out of power.

SHRI RATANSINH RAJDA: An editorial of the *Times of India* has this heading: 'Portriat of violence'. Another article has this: 'Worse than Dacoity'. Actually, the police throughout the country are on a rampage. They think they are the law unto themselves. The custodians of law and order have taken law into their own hands. Our Home Minister, still, wants us to believe that everything is all right and that the law and order is completely safe in his 'able' hands. With all humility, may I tell the Home Minister that he has stepped into the shoes of giant

like Sardar Patel. This Home Ministry was adorned by great people like Sardar Vallabhai Patel. Of course, nothing is common between Sardar Vallabhai Patel and the present Home Minister, except the world 'Sardar'. Mr. Zail Singh should imbibe the spirit of Sardar Vallabhbhai Patel and by that, he would be able to do some justice to the people of this country, to our mothers, sisters, and daughters, who are being raped day in and day out. If that is done, I thing, the entire country would bless the Home Minister and we would also be the first person to give him our blessings and to shower all encomiums on him.

Another editorial starts like this: 'criminals in uniform'. This is the way in which the police is behaving. We are spending a colossal amount on Central Police.

From 1-12-1979 to 31-5-1980, during the last six months, 223 communal incidents have taken place in this country, 56 person were killed and 1,114 people were injured. I will now come to the crimes against Scheduled Castes and Scheduled Tribes. They always feel that it is their monopoly to talk about Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the down-trodden, as it was done in 1971, when their slogans was 'Garibi hatao' and actually, instead of removing poverty, they removed the poor people. The same thing they are doing now. Slogan-mongering is the best art that they have mastered. The number of crimes between 1-1-80 and 31-3-80 have also increased to a great magnitude with regard to atrocities on Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Harijans.

Then, we are incurring a colossal expenditure on the Central Police Force, that is, about Rs. 275 crores. We have to see whether there is any justification or, whatever amount we are spending, whether people get justice at the hands of the police and whether the police force is doing their duty. I think, on the basis of all these facts that are before us, the police force today has become completely a degraded force. The people are very much angry with the functioning of the present-day police under the stewardship of our Home Minister, Sardar Zail Singh and Mr. Makwana.

Now, I would like to say a few words about cur north-estern region. I was a member of the Janata Party delegation which visited north-eastern region. It was my privilege to meet many people there. When we met Mr. Nripen Chakravartty, the Chief Minister of Tripura, we told him, "The holocaust has taken place. How is it that you could not prevent it?" He told the entire delegation, "I have been making frantic calls to the Central Government to send the army, to send reinforcements. But the Central Government has failed in their duty." If that is so, that becomes a very serious matter. This is a problem, a question, a challenge, that has been posed by the Chief Minister of Tripura. The Central Government is answerable to the people, not only to the people of Tripura but the people of the entire country. If the Government would have rushed that help to the Tripura Government, I think, all those precious lives could have been saved. The Central Government here, according to the Chief Minister of Tripura, was completely negligent and there was dereliction of duty as far as the Home Ministry is concerned. I do not know whether there is any truth in that. If it is true, then it is a very serious matter.

As regards the Assam problem, when we met the students and the leaders of AASU, the impression that we have got is that students are prepared to sit at the negotiation table. They are of course for 1951 formula. But they told us that they are prepared to meet and talk. They do not accept the Gandhi Peace

Foundation formula *in toto*. But they told us that they are prepared to take up that as a basic for further negotiations. When we returned here, we saw that the Government had adopted a strong-arm tactice against students. Our impression is that the students are patriots and are not secessionists. There is no foreign hand as far as the students are concerned. If we deal in such a cruel manner with our own boys, I do not know what we can do with other citizens. They are our kith and kin. We should not come out heavily on them. We must try to win over them. We can logically argue with them; we can win their confidence. Whatever their demands are, we can meet them half-way in the best national interest. If that is done, I think, the Assam problem can be solved. Though there are complexities and there is some confusion, still it is not a insurmountable. With a sense of goodwill on both sides, the problem can be easily solved.

As far as Manipur, etc. are concerned, in Imphal definitely there is visible a secessionist hand and, there also, we made it clear to the people that the people of India are prepared to pay any price to maintain the integrity of India and, in this, whatever steps the Government takes, the entire country will stand behind the Prime Minister and the Home Minister.

Now, coming to Delhi...

MR. CHAIRMAN: Please, you have taken more time.

SHRI RATANSINH RAJDA: You don't want me to repeat things. But new facts are coming to light every day. The other day somebody telephoned me and told me that in Model Town and Greater Kailash some miscreants...

MR. CHAIRMAN: That is a new point.

SHRI RATANSINH RAJDA: I am giving this example. When the miscreants went there, a complaint was lodged with the Police that every day thefts are taking place, dacoits are coming and the people are put to great harassment. At that time, the concerned two policemen who went there said:

इसमें क्या कम्प्लेंट करते हो। यह तो रोज की बात है। यह तो रोज हुआ करता है।

I am prepared to bring their names or whatever you want.

So, those citizens are prepared to give a memorandum in writing. You can find out what is the truth.

Therefore, today, people have a sense of insecurity. Nobody in Delhi itself feels secure. Of course, the Hon. Home Minister has remoustrated and rebuked the police force here and I hope that something good will come out of it.

Having said this, I would like to make a few suggestions and those suggestions are, firstly, that the police force requires complete overhauling. First of all the rule of law has got to be respected by everybody. If the rulers themselves by their own attitude and by their conduct do not express or exhibit respect for the rule of law, other limbs of law are not going to respect it. I just heard that one of the top men in Goa (*Interruptions*) came very late to catch a fight. The plane had already started If the rulers themselves behave like this....

MR. CHAIRMAN: Now please. There is no time for anecdotes.

SHRI RATANSINH RAJDA: I am not talking about anything else. I am not talking about the romanticism of Ministers etc. I am merely telling you a fact. The plane had already started moving. It had already started and ran along the runway and, at that time, the highest officer in Goa came and run after the running plane. Of course, the plane took off. The pilot did not hear anything and he took off. But later

two policemen were suspended because the plane took off.

SHRI EDUARDO FALEIRO (Morrmugaod): This man was appointed by the Janata Government. He is your own appointee—a political appointment of the Janata Goverment.

SHRI RATANSINH RAJDA: My hon. friend Mr. Faleiro, by making or interjecting these remarks, thinks he has achieved something great in his life. Well, he can be happy. If he has achieved something concrete, I don't mind.

MR. CHAIRMAN: Mr. Rajda, please. Now, you have made all good and important points. Give up other points: there are others who would like to speak. I have a list of 47 Members before me and it was stated in the House that they are going to exhaust the entire list. We will not be able to cover all these. Please!

SHRI RATANSINH RAJDA: Very well Sir. I obey at your behest.

With these words, I conclude.

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगज): कब्ल इसके कि मैं बहस शुरू करू, मै यह अर्ज करना चाहता हुं मोहतरिम चेयरमैन साहब, कि जब मैने आप से अनुरोध किया था यह जानने के लिये कि मेरा नाम किस नम्बर पर है और आप बाराज हो गये, मेरा मकसद आप की एथारिटी को चैलेज करना नही था। मुझे कुछ जरूरत थी, इसीलिये मैने पूछा कि मैं किस नम्बर पर हूं। आप नाराज खामखवाह हो गये . (**व्यवधान**)

मोहतरिम चेयरमैन साहब, होम मिनिस्ट्री की डिमांड्स पर पाच बजे बोलने का जो मौका आपने इनायत फरमाया है . (**व्यवधान**) . . . जब कि यह हमारे फास्ट का चौदहवा घंटा शुरू है आप समझ लीजिये कि इस वक्त मेरा मिजाज कैसा होगा। और चार घंटे या तीन घंटे मुझे फास्ट करने है। 7 बजकर 30 मिनट तक मेरा यह फास्ट होगा।

सभापति महोदय: आप नाराजी मै मत बोलियेगा।

श्री जमीलुर्रहमान: जी हां, इसीलिये मैने कहा, आप सोच लीजियेगा मेरा मिजाज इस घड़ी कैसा होगा?

मुल्क की हालत 1973-74 मे जैसी थी वह बताने की इस सदन मे अब जरूरत नही है. . . (**व्यवधान**) . . बात सुनिये शास्त्री जी, आज के लिये शेर भी एक लिखा हुआ है। एजीटेशन, हगामा, पीपल्स रेप्रेजेन्टेटिव्ज को मारपीट करना, बेइज्जत करना और हर वह हरकत करना जिस से मुल्क को नकसान हो, समाज को नुकसान हो, कौम को नकसान हो, मसलन रेल की बन्दी सूबे की बन्दी, कारखाने को बन्दी, गर्ज कि जिस कदर भी सारा कारोबार बन्द होना था, वह किया गया। 1973-74 से शुरू करने के बाद बन्दिश ही बन्दिश हुई। टोटल रेवोल्यूशन के नाम पर यह सारी बात शुरू हुई। मुल्क के एक हिस्से गुजरात से शुरू हो कर पूर्वी हिस्से बिहार मे जा कर इस का मामला किसी हद तक चला। गर्ज कि सारे मुल्क मे सनसनी फैली। ये हालात उस वक्त मुल्क के थे और उन्ही हालात मे एमर्जेन्सी लगायी गई। मुल्क के कुछ हालात सुधरे। हमारे मोहतरिम चव्हाण साहब भी उस वक्त हमारे साथ थे। उस वक्त जितने भी अनासिर ऐसे थे जो मुल्क को, समाज को नकसान पहुचाते थे, ब्लैकमार्केटियर्स और एंटी सोशल एलीमेटस वगैरह, उन सारे लोगो को बन्द किया और उन को बन्द करने के बाद बीस सूत्री कार्यक्रम और पाच प्वाइंट प्रोग्राम संजय जी मरहूम का शुरू हुआ। कुछ अच्छा काम शुरू हुआ। लेकिन इसी जगह, शास्त्री जी आप के लिये एक शेर है। जब 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू हुआ तो यह कुछ लोगो को पसद नही आया।

हम ने चाहा था कि भारत मे कोई भखा न हो
हमने चाहा था कि भारत में कोई विधवा न हो।
20 सूत्री कार्यक्रम दे कर जनता को जगाया था मगर, चन्द लोगो ने चाहा यह कार्यक्रम पूरा न हो:

(**व्यवधान**) .

आप तो पहली बार यहा तशरीफ लाई है जरा सुनिए।

यह बात हमारे अपोजीशन को अच्छी नही लगी और उन्होने कहना शुरू किया कि डिक्टेटरशिप हो गई है और एक ही आदमी का राज हो गया है। जम्हरियत खतरे में हैं और जम्हरियत खत्म हो चुकी है। एक साजिश के तहत यह सारा वातावरण और यह हवा चली।

इस के बाद आप ने देखा कि एलेक्शन हुए 77 में और जो ठप्पामारी के जरिये दण्डवते भाई तशरीफ लाये वह कहने की कोई जरूरत नही है क्योंकि वह वक्त बीत चुका है। नया वक्त है? उस के बाद आप ने जो काम शुरू किये वे क्या थे? वह कमिशनों की सरकार थी। लोगों ने जो आप को मैन्डेट दिया था उसके बरअक्स आपने और

कार्यवाही शुरू की। सिर्फ इतना ही नहीं आप ने ऐसे आदमी को चेयरमैन बनाया जिन का एक खास पार्टी से ताल्लुक था। जहां तक कुछ मुझे मालूम है, उन चेयरमैन साहब के खिलाफ, भाई लिमये साहब होते तो ताईद करते या भाई फर्नाण्डीस साहब होते तो शायद इस बात की याद करते, शायद मधु दण्डवते जी ताईद करे, उन के खिलाफ इम्पीचमेंट की दरख्वास्त थी, 199 एम पीज और लीडर्स उस के सिगनेटरीज थ। ऐसे आदमी को चेयरमैन बनाया गया था और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने दौरान प्रोसीडिंग्स जो सब अल्फाज इस्तेमाल किये वह हमारे दोस्तों के याद होंगे। और इससे जाहिर हुआ वे जज की हैसियत में नहीं बैठे थे एक पार्टी वर्कर की हैसियत से बैठे थे। बाद में यह बात साबित भी हो गई उन्होंने बम्बई से जनता पार्टी का टिकट मांगा था, जब वह रफा-दफा हो गया तब उन्होंने जनता पार्टी के लिये काम शुरू किये बम्बई में। यह बात कोई गलत नहीं है। इसलिये में जानना चाहूंगा, मंत्री जी से मैं इसका जबाब चाहूंगा कि जितने कमीशन्स बहाल हुए फजूल, बेवुमूर लोगों के खिलाफ, उन पर कितना खर्चा हुआ पब्लिक एक्सचेकर का। जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टस के डिसीजन्स इन मामलों पर हो गए कि सारी बातें गलत थीं तो पब्लिक एक्सचेकर का जो रूपया नाजायज तौर पर उन कमीशन्स पर सर्फ हुआ है, उसकी वसूली के लिये आप क्या तदबीर और क्या काम करने जा रहे है—मैं यह जानना चाहूंगा।

17 hrs.

एक बात म और भी जानना चाहूंगा। हमारे राज्यसभा में भी यह बात आई थी, वहां पर रेजोल्यूशन पास हुआ था, श्री कांतिभाई देसाई के खिलाफ कुछ चार्जेज थे जोकि साबित भी हुए इसके सिलसिले में कोई कदम उठाकर मुकदमा चलाने की बात आप सोच रहे है या नहीं, इस बात का जबाब भी आप मेहरबानी करके दें।

एक बात और भी है जिसको ध्यान में रखना चाहिये। 1977 से 1978 तक चाहे पुलिस में बहाली हो या आल इंडिया रेडियो में बहाली हो, उसमें बिल्कुल एक खास कमिटेड आर० एस० एस० के तबके के लोगों की बहाली हुई है। ऐसे लोग मुल्क में और समाज में दंगे फसाद करवाते है और करवाये हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को निकालने के लिये आप क्या कर रहे हैं। जो ऐसे अनासर मुल्क के दुश्मन है जिनका सिकुलरिज्म, सोशलिज्म पर कोई विश्वास नहीं है, उनको वीड-आउट करने के लिये आप क्या करने जा रहे हैं?

पिछली सरकार के वक्त में मुल्क में जो फितने और फसाद हुए मैं उनके आंकडे यहां पर देना नहीं चाहता लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि नीरो का नाम आपने सुना होगा, जब रोम जल रहा था तो नीरो बैठा बांसुरी बजा रहा था। उसी तरह से जब जमशेदपुर में मुसलमानों का खून बह रहा था तब श्री कर्पूरी ठाकुर वहां पर गेस्ट हाउस में बैठे हुए खाना खा रहे थे। (व्यवधान)

इस तरह से जब आपकी पार्टी की सरकार आई तो आपने सारे ऐन्टी सोशल एलिमेन्ट्स को, सारे सजायफ्ता को छोड दिया, सारे स्मगलर्स और ब्लेक मार्केटियर्स को छोड़ दिया। नतीजा क्या हुआ? सारे मुल्क में चाहे खाने-पीने के मामले में, चाहे पहनने के मामले में, चाहे समाज में चलने फिरने के मामले में, मां-बहनों के चलने फिरने के मामले में—सभी कुछ मुश्किल हो गया।

इतना ही नही, हमने अपने वक्त में गरीबों, हरिजनो को कुछ जमीनें दिलाई थी। मैं और स्टेट्स की बात नही करता, कम से कम बिहार की बात मैं बता रहा हूं, उस वक्त के हमारे चीफ मिनिस्टर डा० जगन्नाथ मिश्र ने गरीबों, हरिजनों को जमीनें दिलवाई थी। मैंने पिछली बार भी यहां पर यह बात कही थी लेकिन सरकार ने उस पर कोई ध्यान नही दिया। मेरे हल्के में मैने गरीबों को हरिजनों की जमीनें दिलवाई थीं लेकिन जब हम हार गये तो उन लोगों को बेदखल कर दिया गया। मै लोगों को लेकर कलक्टर के यहां गया लेकिन उसने अनसुनी कर दी। मैं मंत्री जी से जबाब चाहूंगा कि हमारे दौरे हकूमत में गरीबो, हरिजनों को जो जमीन दी गई थी, जोकि बाद में जनता सरकार के वक्त में छीन ली, उन जमीनों को वापिस दिलाने के लिये आप क्या करने जा रहे हैं?

मै धनिक लाल मण्डल जी की बात यहां पर सुन रहा था, उन्होंने कहा कि आपने असेम्बली तोड दी। 1977 में आपने असेम्बली तोड़ दी थी, हमने बात मान ली थी कि ठीक है, लोगों का फैसला है जबकि लोगों का फैसला नहीं था, उसी तरीके से इस बार मेजारिटी हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को मिली, हमारी लीडरशिप को मिली, उसी की तहत हम भी कह सकते है कि आपने लोगों का कांफिडेन्स खो दिया उस हलत में सुबाई एलेक्शन्स फिर से हों ताकि सेन्ट्रल और सुबाई सरकारें मिलकर आर्थिक प्रोग्राम को चला सकें। मैं एक बात और बताता हूं। हमारे कुछ दोस्तों ने, जैसे श्री धनिक लाल मंडल ने शिकायत की है कि हमारे पुलिस कमीश्नर साहब दिल्ली में कुछ नही कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैं एक बात होम मिनिस्टर साहब को बता दूं और फिर सवाल करके उनसे जानना चाहूंगा। यह बिल्कुल जाहिर है कि दिल्ली आर० एस० एस० का गढ़ रहा है और श्री भिण्डर साहब को उनकी काबलियत की वजह से उन को इस जगह पर लाया गया है। उनके आने से ऐसे-ऐसे अनासिर, ऐसे-ऐसे तत्वों, ऐसे-ऐसे लोगों को खतरा पैदा हो गया है कि अब एक सख्त आदमी आया है, जो इन लोगों को बाहर निकालेंगे। अगर कुछ त्रुटि है, तो उससे निपटा जा सकता है,

लेकिन साथ-ही-साथ उन्होंने जो अच्छे काम किये हैं, हमें उनकी तारीफ करनी चाहिये। इसलिये मैं होम मिनिस्टर साहब आप के जरिये श्री भिण्डर से कहूंगा कि क्या वे ऐसे लोगो का पता लगायेंगे जो 1977 से 1979 तक किसी खास पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग, पुलिस फोर्स या दूसरे शोबो में भी घुस गये है, उनके पिछले करैक्टर को देखकर, कोई कानूनी कार्यवाई की जायेगी, जिससे मुल्क में अमन हो, मुल्क बचे और समाज बचे।

अब आप जरा जरायम की हालत को भी देख लीजिये। 1977 में जब इन लोगों की सरकार थी, उस वक्त शेड्यूल्ड कास्ट्स और शड्यूल्ड ट्राइब्ज पर जुल्म हुए उनकी संख्या 10879 थी। 1978 में संख्या बढ़कर 15070 हो गई। उसके बाद जब हम लोगो ने सत्ता संभाली, अभी सात आठ महीने ही हुए है, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज पर 3786 जुल्म के मुकदमे हुए हैं। इससे आप अन्दाजा लगा सकते है कि किस के राज में जुल्म कम हुए है।

अब आप दूसरे आंकडे भी सुन लीजिये। जब जनता पार्टी की सरकार थी 1977 में उस वक्त मर्डर 312 हुए, ग्रीवस हर्ट के मुकदमें 1294 हुए और रेप के बारे में तो मेरे कान पक गये हैं सुनते-सुनते, वे 310 हुए आर्सन के मुकदमे 707 हुए,। 1978 मे भी जब आपकी सरकार थी तो 443 मर्डर हुए, 1535 ग्रीवस हर्ट के मुकदमे हुए, 517 जिना बिलजब्र हुए, 1794 आर्सन के मुकदमे हुए और दूसरे मुकदमें 11123 हुए।

अब आप बिहार को लीजिये।

सभापति महोदय : हर स्टेट के आकड़े देने की जरूरत नही है। शास्त्री जी को आप बाद में भेज दीजिएगा।

श्री जमीलुर्रहमान : 1977 में बिहार में 32 मर्डर हुए, ग्रीवस-हर्ट मुकदमे 113 हुए, रेप 70 हुए, जब आपकी सरकार थी। आर्सन के 84 मुकदमें हुए और 1978 में 63 मर्डर हुए है, 146 ग्रीवस-हर्ट के मुकदमें हुए है, रेप के केसेज 76 हुए हैं और आर्सन के मुकदमें 260 हुए और 1979 में भी 185 ग्रीवस-हर्ट के मुकदमें हुए हैं, 79 रेप हुए, 337 आर्सन के मुकदमें हुए अब इस के बाद घनिक लाल मंडल जी क्या कहना चाहते हैं। इस वक्त वे हाउस में हाजिर नहीं हैं हम जानते थे, वे असलियत को फेस नहीं कर सकेंगे।

आनरेबिल होम मिनिस्टर साहब की तरफ से सारे सूबों को एक खत गया था, जिस का नं० है 11011/(4)/80 एन० आई० डी०/एच० एफ० ता० 10-3-1980। यह खत उस वक्त भेजा गया था जब कि सूबो में जनता पार्टी और लोकदल की हुकूमत थी, जिस में उन से कहा गया था कि जो मेजर ट्रबल स्पाट्स हैं उन को आइडेन्टिफाई किया जाय, मामलों का फौरन इन्वेस्टीगेशन हो, प्यूनिटीव फाइन्ज किये जाय, जैसे जमशेदपुर में हुआ था और विक्टिम्ज को फौरन रिहैबिलिटेट करने का काम किया जाय। इस तरह की डायरैक्जन्ज गई थी, लेकिन आप की सरकारों ने, जो लोकदल और जनता पार्टी की सरकारें थी, उन्होने उन डायरेक्टिव्ज को नही माना ....

सभापति महोदय : अब टाइम खत्म हो गया।

श्री जमीलुर्रहमान : मै इस मिनिस्ट्री के बारे में पहली बार बोल रहा हूं, मुझे 5-7 मिनट और दे दीजिये।

चेंयरमैन साहब, बिहार में मेरा जिला पूर्निया है, जो एक अमन पसन्द जिला था, लेकिन एक बदनामी का दाग जनता पार्टी की सरकार के जमाने में लगा। पहली बार वहां पर कम्यूनल फिसादात हुए। किसने कराये - मै नाम नही लूंगा, कानून के मुताबिक नाम लेना मना है, लेकिन वह बिहार के एक एम. एल. ए. थे, जो इस बार भी लोकदल के टिकट पर जीत गये है। इन के बरअक्स अगर देखा जाय कि हम ने क्या किया? होम मिनिस्ट्री ने वही कम्यूनल हार्मोनी सेल बनाया, स्पेसल पीस टास्क फोर्स बनाया, डयू-रेप्रेजेन्टेजन टु मुस्लिम्ज, हरिजन्ज, आदिवासीज इन फार्सेज के बारे में कार्यवाही करने जा रहे है। हम ने यह भी तय किया कि ट्रिप्राटाइट पीस कमेटीज होनी चाहिये। पिछले तीन सालो मे क्यूंकि इण्डस्ट्रीयल एरियाज मे काफी गडबड़ पैदा हुई थी, उस को दूर करने के लिये यह जरूरी थी, ताकि मुल्क की पैदावार बढ़े और हमारा माल बाहर जाये, जिस से हमे फारन एक्सचेंज की आमदनी हो और देश के लोग सुखी सम्पन्न हो।

अखबारो को लीजिये एक अखबार इण्डियन एक्सप्रेस है, जिस ने अपने 7-7-1980 के अखबार में एक खबर छापी थी .....

सभापति महोदय : आप डिटेल्ज को छोड़ दीजिये, अहम चीजो को बतला दीजिये और अपने भाषण को खत्म कीजिये।

श्री जमीलुर्रहमान : मैने आप का हुकम मान लिया, अभी खत्म करता हू। हमारे मैनीफैस्टों के मुताबिक काम होता जा रहा है। हमारे मैनीफैस्टों में था कि जहां जहां उर्दू बोलने वालो की अक्सरियत होगी, वहां वहां उर्दु को स्टेट जुबान बनाया जायेगा। मै बधाई देता हूं डा. जगन्नाथ मिश्र--- को, उन्होंने वहां उर्दू जुबान को उस का सही हक अता किया है, उसको दूसरी जुबान बनाया है। इससे उर्दू बोलने वाले तबकों में बहुत खुशी पैदा हुई है। हमारी लीडर श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अलीगढ़ यूनीवर्सिटी को अकलीयती किरदार बहाल किया है, जिस के लिये हम उन के शुकगुजार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो कदम उठाये जायेंगे, वे हमारे मैनीफेस्टो के मुताबिक होंगे।

अब मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं--पुलिस फोर्स और दीगर सरकारी दफ्तरों में अकलीयतों की बहाली हो रही है और करने की हिदायत दी गई है। मैं चाहता हूं कि बहाली कमेटी जिले-जिले में जा कर पुलिस और सी० आर० पी० की बहाली करे तीन चार जिलों को मिला कर बहाली की जाय, जिस से मुल्क में अमन और शान्ति कायम हो सके।

17.14 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

जहां तक पुलिस का ताल्लुक है उन्हें राहत भी देनी होगी। उन के रहने, लिबास और बच्चों के पढ़ने दवा दारू का अच्छा इन्तजाम किया जाय ताकि वे मुस्तैदी से काम कर सकें। मैं जानना चाहता हूं कि इस मद में आप ने कितना रुपया रखा है? जब आप जवाब दें तो इस के बारे में भी बतलायें।

आखिर में, मैं नार्थ ईस्ट रिजन के बारे में कहना चाहता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

श्री जमीलुर्रहमान. नार्थ ईस्टर्न रीजन की बात यहां पर कही गई है। इस के बारे में मेरा कहना यह है कि यह आज का मामला नहीं है। यह मामला बहुत दिनों से चला आ रहा है और श्री वाजपेयी जी की पार्टी के जैसे लोग जब यहां रहेंगे तो वहां पर मुसलमानों का कत्लेआम होगा। मैं होम मिनिस्टर साहब की तारीफ करता हूं आप ने और हमारी बजीरेआजाम श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आसाम के सिलसिले में जो कदम उठाया है वह निहायत मुनासिब कदम है। यह बात साफ है कि भारत के हर हिस्से पर हर कोने पर हर कोने में, हर इंच जमीन पर सारे लोगों का बराबर का अधिकार है और किसी को यह कहने का अख्तियार नहीं है कि वहां पर कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से रहते है और वे लोग जिन के बाप-दादा वहां पैदा हुए हैं। वहां मरे है और वहीं गढे है, वे फारेनर्स हैं। ऐसी चाल किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है इसी सिलसिले में एक शेर अर्ज करता हूं।

> "मश्विरे सब दोस्तों के हमने माने हैं सदा
> मश्विरों को हम उसूल अपना बना सकते नहीं
> सारी दुनिया की भलाई चाहते हैं हम मगर
> सर किसी ताकत के आगे हम झुका सकते नहीं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude. I am going to call your own party member, Shri Ghulam Nabi Azad.

श्री जमीलुर्रहमान: अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। कानूनी हालत को मजबूती से सुधारिये। दूसरा सुझाव है कि मिक्स्ड पुलिस फोर्स बनाइये, हरिजनों, आदिवासियों और मुसलमानों की मिक्स्ड फोर्स बनाइये ताकि जहां ऐसे गडबड़ी वाले और रायट-प्रोन एरियाज हैं, वह वहां जा कर अमल बहाल करे और लोगों में कांफीडेंस बहाल करे। आम लोगों की जो जमीने ली गई हैं, उन को वापस दिलाइये। जमीनों के कानूनों को जोर-शोर से लागू कीजिये और होर्डस और ब्लेक मार्केटियर्स को पकड़ कर बन्द कीजिये और सब से ज्यादा इम्पोर्टेन्ट चीज यह है कि चीजों के दाम कम कीजिये।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shri Ghulam Nabi Azad..

SHRI JAMILUR RAHMAN: I am *placing the papers*..

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please give it to the Home Minister.

[شری جمیل الرحمن (کشن گنج) :

قبل اس کے کہ میں بحث شروع کروں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں محترم چیئرمین صاحب کہ جب میں نے آپ سے انرودھ کیا تھا یہ جاننے کے لئے کہ میرا نام کس نمبر پر ہے اور آپ ناراض ہوگئے - میرا مقصد، آپ کی آتھورٹی کو چیلنج کرنا نہیں تھا - مجھے کچھ ضرورت تھی اس لئے میں نے پوچھا کہ میں کس نمبر پر ہوں - آپ ناراض خوامخواہ ہوگئے - ... (انٹرپشن) ...

محترم چیئرمین صاحب ہوم منسٹری کو ڈیمانڈ پر پانچ بجے بولنے کا جو موقع آپ نے عنایت فرمایا ہے - ... (انٹرپشن) ... جب کہ یہ ہمارے فاسٹ کا چوتھواں گھنٹہ شروع ہے - آپ سمجھ لیجئے کہ اس وقت میرا مزاج کیسا ہوگا - اور چار

[شری جمیل الرحمن]

کھلتے یا تھوں کھلتے مجھے فاسٹ کرنے ھیں - سات بجے کو تیس منٹ تک - میرا یہ فاسٹ ھوگا -

سبھا پتی مہودے : آپ ناراضی میں مت بولئے گا -

شری جمیل الرحمن : جی ھاں اسی لئے میں نے کہا آپ سوچ لیجئے کا میرا مزاج اس گھڑی کیسا ھوگا -

ملک کی حالت ۷۴-۱۹۷۳ ع میں جیسی تھی وہ بتانے کی اس سدن میں اب ضرورت نہیں ھے - . . . . (انٹرپشن) . . . بات سنئے شاستری جی آپ کے لئے شعر بھی ایک لکھا ھوا ھے - ایجیٹیشن ھنگامہ پبلک پراپرٹیز کو مار پیٹ کرنا بے عزت کرنا اور ھر وہ حرکت کرنا جس سے ملک کو نقصان ھو سماج کو نقصان ھو قوم کو نقصان ھو مثلاً ریل کی بندی صوبے کی بندی کارخانے کی بندی غرض کہ جس قدر بھی سارا کاروبار بند ھونا تھا وہ کیا گیا - ۷۴-۱۹۷۳ ع سے شروع کرنے کے بعد بندھ ھی بندھ ھوئی - ٹوٹل ریولوشن کے نام پر یہ ساری بات شروع ھوئی - ملک کے ایک حصے گجرات سے شروع ھو کر پوروی حصے بہار میں جا کر اس کا معاملہ کسی حد تک چلا - غرض کہ سارے ملک میں سلسلی پھیلی - یہ حالات اس وقت ملک کے تھے اور انہیں حالات میں ایمرجینسی لگائی گئی - ملک کے کچھ حالات سدھرے - ھمارے محترم چوہان صاحب بھی اس وقت ھمارے ساتھ تھے - اس وقت جتنے عناصر ایسے تھے جو ملک کو سماج کو نقصان پہنچاتے تھے - بلیک مارکیٹیرس اور اینٹی سوشل ایلیمینٹس وغیرہ ان سارے لوگوں کو بند کیا اور ان کو بند کرنے کے بعد بیس سوتری کاریہ کرم اور پانچ پوائنٹ پروگرام سنجے جی مرحوم کا شروع ھوا - کچھ اچھا کام شروع ھوا - لیکن اسی جگہ شاستری جی آپ کے لئے ایک شعر ھے - جب بیس سوتری کاریہ کرم شروع ھوا تو یہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا -

ھم نے چاھا تھا کہ بھارت میں
کوئی بھوکا نہ ھو -

ھم نے چاھا کہ بھارت میں
کوئی ودھوا نہ ھو -

بیس سوتری کاریہ کرم دے کر
جنتا کو جگایا تھا مگر
چند لوگوں نے چاھا
یہ کاریہ کرم پورا نہ ھو -
. . . (انٹرپشن) . . .

آپ تو پہلی بار یہاں تشریف لائی ھیں ذرا سنئے -

یہ بات ھمارے اپوزیشن کو اچھی نہیں لگی اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ڈکٹیٹرشپ ھو گئی ھے اور

بعد میں یہ بات ثابت بھی ہوگئی - انہوں نے بمبئی سے جنتا پارٹی کا ٹکٹ مانگا تھا - جب وہ رفیوز ہو گیا تب انہوں نے جنتا پارٹی کے لئے کام شروع کیا بمبئی میں - یہ بات کوئی غلط نہیں ہے - اس لئے میں جاننا چاہوں گا منتری جی سے میں اس کا جواب چاہوں گا کہ جتنے کمیشن بٹھائے ہوئے فضول بے قصور لوگوں کے خلاف ان پر کتنا خرچ ہوا پبلک ایکس چیکر کا - جب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ڈسیژن ان معاملوں پر ہو گئے کہ ساری باتیں غلط تھیں تو پبلک ایکس چیکر کا جو روپیہ ناجائز طور پر ان کمیشنس پر صرف ہوا ہے اس کی وصولی کے لئے آپ کیا تدبیر اور کیا کام کرنے جا رہے ہیں - یہ میں جاننا چاہوں گا -

ایک بات میں اور بھی جاننا چاہوں گا - ہمارے راجیہ سبھا میں بھی یہ بات آئی تھی وہاں پر ریزولیوشن پاس ہوا تھا - شری کانتی بھائی ڈیسائی کے خلاف کچھ چارجز تھے جو کہ ثابت بھی ہوئے اس کے سلسلے میں کوئی قدم اٹھا کر مقدمہ چلانے کی بات آپ سوچ رہے ہیں یا نہیں - اس بات کا جواب بھی آپ مہربانی کر کے دیجئے -

ایک بات اور بھی ہے جس کو دھیان میں رکھنا چاہئے - ۱۹۷۷ ع ایک ہی آدمی کا راج ہو گیا ہے - جمہوریت خطرے میں ہے اور جمہوریت ختم ہو گئی ہے - ایک سازش کے تحت یہ سارا واتاورن اور یہ ہوا چلی -

اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ الیکشن ہوئے ۷۷ میں اور جنتا پارٹی کے ذریعہ ڈنڈوتے بھائی تشریف لائے - وہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے - کیونکہ وہ وقت بیت چکا ہے - نیا وقت ہے - اس کے بعد آپ نے جو کام شروع کیا کہئے وہ کیا تھے - وہ کمیشنوں کی سرکار تھی - لوگوں نے جو آپ کو مینڈیٹ دیا تھا اس کے برعکس آپ نے اور کاروائی شروع کی - صرف اتنا ہی نہیں آپ نے ایسے آدمی کو چیئرمین بنایا جن کا خاص ایک پارٹی سے تعلق تھا - جہاں تک کچھ مجھے معلوم ہے ان چیئرمین صاحب کے خلاف بھائی لمئے صاحب ہوتے تو تائید کرتے شاید مدھو ڈنڈوتے تائید کریں ان کے خلاف امپیچمنٹ کی درخواست تھی ۱۹۹ ایم - پی - اور لیڈرس اس کے سگنیٹریز تھے - ایسے آدمی کو چیئرمین بنایا گیا تھا اور صرف اتنا ہی نہیں انہوں نے دوران پروسیڈنگس جو سب الفاظ استعمال کئے وہ ہمارے سارے دوستوں کو یاد ہونگے - اور اس سے ظاہر ہوا وہ جج کی حیثیت سے نہیں بیٹھے تھے ایک پارٹی ورکر کی حیثیت سے بیٹھے تھے -

نتیجہ کیا ہوا ؟ سارے ملک میں چاہے کھانے پینے کے معاملے میں چاہے پہننے کے معاملے میں چاہے سماج میں چلنے پھرنے کے معاملے میں ماں بہنوں کے چلنے پھرنے کے معاملے میں سبھی کچھ مشکل ہو گیا -

اتنا ہی نہیں ہم نے اپنے وقت میں غریبوں ہریجنوں کو کچھ زمینیں دلائیں تھیں - میں اور اسٹیٹس کی بات نہیں کرتا کم سے کم بہار کی بات میں بتا رہا ہوں اس وقت کے ہمارے چیف منسٹر ڈاکٹر جگن ناتھ مشرا نے غریبوں ہریجنوں کو زمینیں دلائی تھیں - میں نے پچھلی بار بھی یہ بات کہی تھی لیکن سرکار نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا - میرے حلقے میں میں نے غریبوں کو ہریجنوں کو زمینیں دلوائی تھیں لیکن جب ہم ہار گئے تو ان لوگوں کو بے دخل کر دیا گیا - میں لوگوں کو لے کر کلیکٹر کے یہاں گیا لیکن اس نے ان سنی کر دی - میں منتری جی سے جواب چاہوں گا کہ ہمارے دورے حکومت میں غریبوں ہریجنوں کو جو زمینیں دی گئی تھیں جو کہ بعد میں جنتا سرکار کے وقت میں چھین لیں ان زمینوں کو واپس دلانے کے لئے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں -

میں دھنک لال جی کی بات یہاں پر سن رہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے اسمبلی توڑ دی - ۱۹۷۷ء

[شری جمیل الرحمن]

سے ۱۹۷۸ ع تک چاہے پولیس میں بحالی ہو یا آل انڈیا ریڈیو میں بحالی ہو اس میں بالکل ایک خاص کمٹڈ آر - ایس - ایس - کے طبقے کے لوگوں کی بحالی ہوئی ہے - ایسے لوگ ملک میں اور سماج میں دنگے فساد کرواتے ہیں - اور کروائے ہیں - تو میں آپ سے جاننا چاہونگا کہ ایسے لوگوں کو نکالنے کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں - جو ایسے عناصر ملک کے دشمن ہیں جن کا سیکولرزم سوشلزم پر کوئی وشواس نہیں ہے ان کو ریڈ آوٹ کرنے کے لئے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں -

پچھلی سرکار کے وقت میں ملک میں جو فتنے اور فساد ہوئے ہیں ان کے آنکڑے یہاں پر دینا نہیں چاہتا لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ نیرو کا نام آپ نے سنا ہوگا جب روم جل رہا تھا تو نیرو بیٹھا بانسری بجا رہا تھا - اسی طرح سے جب جمشیدپور میں مسلمانوں کا خون بہہ رہا تھا تب شری کرپوری ٹھاکر وہاں پر گیسٹ ہاؤس میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے - ...(انٹرپشن)...

اس طرح سے جب آپ کی پارٹی کی سرکار آئی تو آپ نے سارے ایمنٹی سوشل ایلیمینٹس کو سارے سزایافتہ کو چھوڑ دیا - سارے اسمگلر اور سارے بلیک مارکیٹیرس کو چھوڑ دیا -

تعریف کرنی چاهئے - اس لئے میں هوم منسٹر صاحب آپ کے ذریعہ شری بھنڈر سے کہوں گا کہ کیا وہ ایسے لوگوں کا پتہ لگائیں جو ۱۹۷۷ء سے ۱۹۷۹ء تک کسی خاص پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ پولیس فورس یا دوسرے شعبوں میں جو گھس گئے ہیں ان کے پچھلے کریکٹر کو دیکھ کر کوئی قانونی کاروائی کی جائیگی جس سے ملک میں امن ہو ملک بچے اور سماج بچے -

اب آپ ذرا جرائم کی حالت کو بھی دیکھ لیجئے - ۱۹۷۷ء میں جب ان لوگوں کی سرکار تھی اس وقت جو شیڈیولڈ کاسٹ اور شیڈیولڈ ٹرائبس پر ظلم ہوئے ان کی سنکھیا ۱۰۸۷۹ تھی - ۱۹۷۸ میں سنکھیا بڑھ کر ۱۵۰۷۰ ہو گئی - اس کے بعد جب ہم لوگوں نے سترا سنبھالی ابھی سات آٹھ مہینے ہی ہوئے ہیں شیڈیولڈ کاسٹ اور شیڈیولڈ ٹرائبس پر ۳۷۸۶ ظلم کے مقدمے ہوئے ہیں - اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس کے راج میں ظلم کم ہوئے ہیں -

اب جب آپ دوسرے آنکڑے بھی سن لیجئے - جب جنتا پارٹی کی سرکار تھی ۱۹۷۷ء میں اس وقت مرڈر ۳۱۲ ہوئے گریوس ہرٹ کے مقدمے ۱۲۹۴ ہوئے اور ریپ کے بارے میں تو میرے کان پک گئے ہیں سنتے سنتے وہ ۳۱۰ ہوئے آرسن کے مقدمے میں آپ نے اسمبلی توڑ دی تبھی ہم نے بات مان لی تھی کہ ٹھیک ہے لوگوں کا فیصلہ ہے جبکہ لوگوں کا فیصلہ نہیں تھا - اس طریقے سے اس بار میجوریٹی ہمارو سرکار کو ہماری پارٹی کو ملو ہماری لیڈر شپ کو ملی اس کے تحت ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کا کونفیڈینس کھو دیا اس حالت میں صوبائی الیکشن پھر سے ہوں تاکہ سینٹرل اور صوبائی سرکاریں مل کر آرتھک پروگرامس کو چلا سکیں -

میں ایک بات اور بتاتا ہوں - ہمارے کچھ دوستوں نے جیسے شری دھنک لال منڈل نے شکایت کی ہے کہ ہمارے پولیس کمشنر صاحب دھلی میں کچھ نہیں کر رہے ہیں اس سلسلہ میں میں ایک بات هوم منسٹر صاحب کو بتا دوں اور پھر سوال کرکے ان سے جاننا چاہوں گا - یہ بالکل ظاہر ہے کہ دھلی آر - ایس - ایس - کا گڑھ رہا ہے اور شری بھنڈر صاحب کو ان کی قابلیت کی وجہ سے ان کو اس جگہ پر لایا گیا ہے - ان کے آنے سے ایسے ایسے مقاصد ایسے ایسے تتوں ایسے ایسے لوگوں کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب ایک سخت آدمی آیا ہے جو ان لوگوں کو باہر نکالے گا - اگر کچھ تروٹی ہے تو اس سے نپٹا جا سکتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو اچھے کام کئے ہیں ہمیں ان کی

[شری اجمل الرحمن]

۷۰۷ ہوئے - ۱۹۷۸ء میں بھی جب آپ کی سرکار تھی تو ۴۴۳ مرڈر ہوئے ۱۵۳۵ گریوس ہرٹ کے مقدمے ہوئے ۵۱۷ زنابالجبر ہوئے ۱۷۹۴ آرسن کے مقدمے ہوئے اور دوسرے مقدمے ۱۱۱۷۳ ہوئے - اب آپ بہار کو لیجئے -

سبھا پتی مہودے : ہر اسٹیٹ کے آنکڑے دینے کی ضرورت نہیں ہے - شاستری جی کو آپ بعد میں بھیج دیجئے گا -

شری جمیل الرحمن : ۱۹۷۷ء میں بہار میں ۳۲ مرڈر ہوئے گریوس ہرٹ کے مقدمے ۱۱۳۴ ریپ ۷۰ ہوئے جب آپ کی سرکار تھی آرسن کے ۸۴ مقدمے ہوئے اور ۱۹۷۷ میں ۶۳ مرڈر ہوئے ہیں ۱۴۶ گریوس ہرٹ کے مقدمے ہوئے ہیں ریپ کے کیسز ۷۶ ہوئے ہیں اور آرسن کے مقدمے ۲۶۰ ہوئے ہیں اور ۱۹۷۹ء میں بھی ۱۸۵ گریوس ہرٹ کے مقدمے ہوئے ہیں ۷۹ ریپ ہوئے ۳۳۷ آرسن کے مقدمے ہوئے - اس کے بعد دھنک لال منڈل جی کیا کہنا چاہتے ہیں - اس وقت وہ ہاؤس میں حاضر نہیں ہیں ہم جانتے تھے وہ اصلیت کو فیل نہیں کر سکیں گے -

آنریبل ہوم منسٹر صاحب کی طرف سے سارے صوبوں کو ایک کہا گیا تھا - جس کا نمبر ہے - ۱۱۰۱۱/۴/۸۰ این - آئی - ٹی ایچ - ایم مورخہ ۱۹۸۰-۳-۱۰ یہ خط اس وقت بھیجا گیا تھا جب کہ صوبوں میں جنتا پارٹی اور لوک دل کی حکومت تھی جس میں ان سے کہا گیا تھا - کہ جو میجر - ٹربل اسپاٹس ہیں ان کو انڈیا ہائی کیا گیا - ان کا فوراً انسٹیگیشن ہو یونٹ فارمز کئے جائیں جیسے جمشید پور میں ہوا تھا اور وکٹمز کو فوراً ری ہیبلٹیٹ کرنے کا کام کیا جائے - اس طرح کی ڈائرکشن گئیں تھیں - لیکن آپ کی سرکاروں نے جو لوک دل اور جنتا پارٹی کی سرکاریں تھیں انہوں نے ان ڈائریکٹوز کو نہیں مانا..... :

سبھاپتی مہودے : اب ٹائم ختم ہو گیا -

شری جمیل الرحمن : میں اس منسٹری کے بارے میں پہلی بار بول رہا ہوں مجھے ۵-۷ منٹ اور دے دیجئے -

چیئرمین صاحب بہار میں میرا ضلع پورنیہ ہے جو ایک امن پسند ضلع تھا - لیکن ایک بدنامی کا داغ جنتا پارٹی کی سرکار کے زمانے میں لگا - پہلی بار وہاں پر کمیونل فسادات ہوئے - کس نے کرائے - میں نام نہیں لوں گا - قانون کے مطابق

نام لینا منع ہے لیکن وہ بہار کے ایک ایم - ایل - اے تھے جو اس بار بھی لوک دل کے ٹکٹ سے جیت گئے ہیں - ان کے برعکس اگر دیکھا جائے کہ ہم نے کیا کیا - ہوم منسٹری نے وہاں کمیونل ہارمونی سیل بنایا اسپیشل پولیس - ٹاسک فورس بنایا گیا - ریزرویشن - تو مسلم ہریجنز آدی واسیز ان فورسز کے بارے میں کاروائی کرنے جا رہے ہیں - ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ تری پارٹایٹ پولیس کمیٹی ہونی چاہئے- پچھلے تین سالوں میں چونکہ انڈسٹریل ایریاز میں کافی گڑبڑ پیدا ہوئی تھی اس کو دور کرنے کے لئے یہ ضروری تھی تاکہ ملک کی پیداوار بڑھے اور ہمارا مال باہر جائے جس سے ہمیں فارن ایکسچینج کی آمدنی ہو اور دیش کے لوگ سکھی سمپن ہوں -

اخباروں کو لیجئے - ایک اخبار انڈین ایکسپریس ہے جس نے اپنے ۷-۷-۱۹۸۰ کے اخبار میں ایک خبر چھپی تھی ....

<u>سبھاپتی مہودے :</u> آپ ڈیٹیلز کو چھوڑ دیجئے اہم چیزوں کو بتا دیجئے اور اپنی سماعت کو ختم کیجئے -

<u>شری جمیل الرحمن</u> - میں نے آپ کا کہا مان لیا ابھی ختم کرتا ہوں -

ہمارے مینیفیسٹو میں تھا کہ جہاں جہاں اردو بولنے والوں کی اکثریت ہو گی وہاں وہاں اردو کو اسٹیٹ کی دوسری زبان بنایا جائے گا - میں بدھائی دیتا ہوں ڈاکٹر جگن ناتھ مشر کو انہوں نے وہاں اردو زبان کو اس کا صحیح حق دلایا گیا ہے اس کو دوسری زبان مانا ہے - اس سے اردو بولنے والے طبقوں میں بہت خوشی پیدا ہوئی ہے - ہماری لیڈر شریمتی اندرا گاندھی نے علیگڑھ یونیورسٹی کا اقلیتی کردار بحال کیا ہے - جس کے لئے ہم ان کے شکرگزار ہیں - ہم عہد کرتے ہیں کہ آگے بھی جو قدم اٹھائے جائیں گے وہ ہمارے مینی فیسٹو کے مطابق ہوں گے -

اب میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں - پولیس فورس اور دیگر سرکاری دفتروں میں اقلیتوں کی بحالی ہو رہی ہے اور کرنے کی ہدایت دی گئی ہیں - میں چاہتا ہوں کہ بحالی کمیٹی ضلع ضلع میں جا کر پولیس اور سی - آر - پی کی بحالی کریں تین چار ضلعوں کو ملا کر بحالی کی جائے- جس سے ملک میں امن اور شانتی قائم ہو سکے -

17. 14 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

[شری جمیل الرحمن]

جہاں تک پولیس کا تعلق ہے - انہیں راحت بھی دینی ہوگی- ان کے رہنے اور لباس اور بچوں کے پڑھنے دوا - دارو کا اچھا انتظام کیا جائے تاکہ وہ مستعدی سے کام کر سکیں - میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس مد میں آپ نے کتنا روپیہ رکھا ہے - جب آپ جواب دیں تو اس کے بارے میں بھی بتلائیں -

آخر میں میں نارتھ ایسٹ ریجن کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں -

MR. DEPUTY SPEAKER: Please conclude now.

شری جمیل الرحمن : نارتھ ایسٹ ریجن کی بات یہاں پر کہی گئی ہے اس کے بارے میں میرا کہنا یہ ہے کہ یہ آج کا معاملہ نہیں ہے - یہ معاملہ بہت دنوں سے چلا آ رہا ہے اور شری واجپئی جی کی پارٹی کے جیسے لوگ جب وہاں رہیں گے جو وہاں پر مسلمانوں کا قتل عام ہوگا - میں منسٹر صاحب کی تعریف کرتا ہوں آپ نے اور ہماری وزیر اعظم شریمتی اندرا گاندھی نے آسام کے سلسلے میں جو قدم اٹھایا ہے یہ نہایت مناسب قدم ہے - یہ بات صاف ہے کہ بھارت کے ہر حصے پر ہر کونوں میں ہو ان پر سارے لوگوں کا برابر کا ادھیکار ہے اور کسی کو یہ کہنے کا اختیار نہیں ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ قانونی غیر طریقے سے رہتے ہیں اور یہ لوگ جن کے باپ - دادا وہاں پر پیدا ہوئے ہیں وہاں مرے ہیں اور یہیں گڑے ہیں وہ فارنرس ہیں - ایسی بات کسی قیمت پر بھی برداشت نہیں کی جاسکتی ہے - اس سلسلے میں ایک شعر عرض کرتا ہوں -

مشورے سب دوستوں کے ہم نے مانے ہیں سدا
مشوروں کو ہم اصول اپنا بنا سکتے نہیں
ساری دنیا کی بھلائی چاہتے ہیں ہم مگر
سر کسی طاقت کے آگے ہم جھکا سکتے نہیں -

MR. DEPUTY SPEAKER: Please conclude. I am going to call your own party member. Shri Ghulam Nabi Azad.

شری جمیل الرحمن : اب میں کچھ سجھاؤ دینا چاہتا ہوں - قانونی حالات کو مضبوطی سے سدھارئے- دوسرا سجھاؤ ہے کہ مکسڈ پولیس فورس بنائیے ہریجنوں آدی واسیوں اور مسلمانوں کی مکسڈ فورس بنائیے تاکہ جہاں ایسے گڑبڑی والے اور رائٹ یورن ایریاز ہیں وہ وہاں جاکر امن بحال کریں اور لوگوں میں کانفیڈینس بحال کریں عام لوگوں کی جو زمینیں لی گئی ہیں ان کو واپس لائیے - زمینوں کے قانونوں کو زور شور سے لاگو کیجئے اور ہاؤس اس بلیک مارکیٹنگ

کو پکڑ کر بند کیجئے اور سب سے
زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ
چیزوں کے دام کم کیجئے -

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shri Ghulam Nabi Azad..

SHRI JAMILUR RAHMAN: I am placing the papers...

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please give it to the Home Minister.

श्री गुलाम नबी आजाद (वाशिम) : माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, आज सुबह से यहां पर गृह मंत्रालय की मांगों पर बहुत चर्चा हुई और एट्रोसिटीज के बारे में भी कहा गया ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पहली दफा नहीं हो रहा है । मैं आप का ध्यान पिछले 30 साल ही नहीं बल्कि पिछले 300 साल और 3000 साल से सारे हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में ऐसी वारदातें हुआ करती रही है लेकिन इस के यह माइने नहीं कि मैं यह कहूं कि अगर पहले भी हुआ करती थीं, तो आज भी होनी चाहिए । ऐसा कहने का मेरा बिल्कुल मतलब नहीं है । आप ब्रिटेन में देखिए, आप अमेरिका में देखिये, स्वीटजरलैंड में देखिए, वहां भी रेप होते है, वहां भी डेकायटीज होती है, कत्ल होते है और वहां भी गरीब लोगों की हत्यायें होती हैं लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उन मुल्कों मे जो कानून है, वे बहुत सख्त है और बहुत सख्ती से ऐसे अपराधों से निपटा जाता है। हमारे मुल्क में कोई भी इस प्रकार के सख्त कानून नहीं हैं जिससे कि अपराधियों को ज्यादा से ज्यादा सजा दी जा सके ।

लेकिन आज सवाल इस बात का है कि पिछले दिनों से, पिछले 6 महीने से ये रेप, डेकैटीज और दूसरी तमाम बातें क्यों हो रही हैं और इनकी इतनी चर्चा क्यों हो रही हैं ? इसकी सब से बड़ी वजह है, जैसा कि हमारे दोस्त जगदीश टाइटलर ने कहा कि पिछले दो-ढाई साल तक जो सरकार यहां रही, उसकी जो कमजोरियां थीं, उनसे जो तीन साल तक सारे मुल्क में वातावरण बना, माहौल बना, उसी का आज भी असर दिखायी दे रहा है । डिप्टी स्पीकर साहब, जब कोई भी सरकार बनती है, चाहे वह केन्द्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उसकी जो नीतियां होती हैं चाहे वे अच्छी नीतियां हों या बुरी नीतियां हों, उन नीतियों का, उस सरकार के जाने के बाद भी 6 महीने और 1 साल तक असर रहता है। जिस सरकार ने गलत नीतियां बनायी हों या बुरी नीतियां बनायी हों उनसे जो वातावरण और माहौल बनता है उसका असर तो उस सरकार के जाने के बाद और काफी अर्से तक रहता है । इसलिए पिछली सरकार के जमाने में ढाई साल तक जो सारे मुल्क में डाकेजनी हुई, कत्लोगारद हुई, हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नाम से लड़ाई-झगड़े होते रहे, हरिजनों और गरीब लोगों का कत्लेआम होता रहा, गरीब तबके के साथ बहुत बुरा सलूक होता रहा, आज जबकि जनता पार्टी की सरकार खत्म हो गयी है, उसके बाद भी आज मुल्क में उसका थोड़ा-सा असर और हमारे राज्यों में भी दिखाई देती है ।

मैं समझता हूं कि इस की सब से बड़ी वजह यह है कि जनता पार्टी के शासन में, जनता पार्टी की हुकूमत में, चाहे वह राज्यों में रही हो या केन्द्र में रही हो, जनता पार्टी के लोगों का एक ही प्रोग्राम था कि जनसंघ और आर० एस० एस० के लोग किस तरह से ज्यादा से ज्यादा पुलिस में भर्ती किए जाएं । बदकिस्मती की बात है कि आज मुल्क के अन्दर जो कुछ भी हो रहा है वह उन्हीं की वजह से हो रहा है । आज पुलिस के अन्दर उनके जो कार्यकर्ता है, वर्कर्स हैं, वे ऐसा काम करते हैं, जैसा कि हमारे साथी ने कहा, कि जब भी कोई वाकया होता है, या कोई चोरी होती है तो सब से पहले अपोजिशन के लोगों को मालूम हो जाता है । मैं पूछना चाहता हूं कि उनको ही पहले क्यों मालूम हो जाता है, सरकार को पहले क्यों नहीं मालूम होता है ? इसलिए इससे साफ जाहिर है कि जो ऐसे लोग पुलिस में हैं या और बाकी डिपार्टमेंट्स में है, वे डिपार्टमेंट्स चाहे मरकज से ताल्लुक रखते हों, चाहे स्टेट्स से ताल्लुक रखते हों, वे सब से पहले इनको जानकारी देते हैं । तो मैं डिप्टी स्पीकर साहब आपका ध्यान और होम मिनिस्टर साहब का भी ध्यान इस तरफ दिलाऊंगा कि इस बात की जांच करायी जानी चाहिए कि क्यों इस तरह के वाकयात होते है ?

इस तरह के वाकयात जो प्रैस में आते हैं, इस बात की भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या वे सब के सब सच होते हैं या कुछ पत्रों या कुछ लोगों के कहने की वजह से वे प्रेस में आते हैं । मैं होम मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो भी वकाया होता है, चाहे वह डाकेजनी की बात हो या कुछ और बात हो, वह फ्रन्ट पेज पर आती है । लेकिन जब सरकार उसमें कुछ आगे काम करती है, या लोगों

को पकड़ती है, या उन्हें सजा देती है तो उसके लिए अखबार में कोई भी जगह नहीं पायी जाती । इस तरफ आपका ध्यान दिलाते हुए और इस बारे में ज्यादा डिटेल में न जाते हुए मैं सुझाव देता हूं —

सब से पहले मेरा सुझाव है कि हमारे मुल्क के अन्दर, जैसा कि मैंने पहले कहा कि विदेशी मुल्कों में इस तरह के अपराधों के लिए बहुत सख्त कानून हैं, हमारे मुल्क में उस तरह के कानून या नियम नही हैं, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि यहां भी ऐसे स्पेशल इन्वेस्टीगेटिंग सेल बनाए जाएं कि जो भी शख्स किसी रेप या किसी और केस में अपराधी पाया जाए तो उस केस को 15 दिन के अन्दर अन्दर वह सेल इन्वेस्टीगेट करके स्पेशल कोर्ट के हवाले कर दे और एक महीने के अन्दर-अन्दर उस अपराधी को सख्त से सख्त सजा दे दी जाए ।

यही वजह है कि मुल्क में ऐसी घटनाएं होती हैं, वाकात होते है, तो उनके इन्वेस्टीगेशन में दो-दो और पांच-पाच बरस लग जाते है । अपराधी को पता होता है कि तब तक पुलिस वाले भी भूल जाएंगें और सरकार भी भूल जाएगी और उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा इस वास्ते इस तरह से अपराध बढ़ते जाते हैं । इस वास्ते मेरी प्रार्थना है कि स्पेशल इन्वेस्टीगेशन सैल के साथ साथ स्पेशल कोर्ट्स भी ऐसे केसिस को एक्समीडाइट करने के लिए होनी चाहिये ।

मैं यह भी चाहता हूं कि कुछ इंसैंटिव्ज भी पुलिस को दिए जाने चाहिये ।

कुछ जगहों पर जहां हरिजन और गरीब तबके के लोग हैं वहां पर ऊंची जाति के लोग या गुण्डा गर्दी करने वाले लोग राइफलें ले कर इन गरीब लोगों को मारते है । ऐसे गांवों में और ऐसी जगहों पर उनके बन्दूकों के लाइसेंस जब्त कर लिए जाने चाहिये ।

रेप केसिस जो होते है या दूसरे इस तरह के किस्से होते हैं इस में सी आई डी और आई वी जो है इसकी एक स्पेशल ब्रांच होनी चाहिये । हमारे देश में पुलिस अफसर को थाने से उठाकर आई वी में लगा दिया जाता है और आई वी से उठाकर सी आई डी से उठाकर उसे एस एच ओ बना दिया जाता है । एक एस एच ओ जब सी आई डी में या आई वी में जाता है वह बड़े सरकारी अफसर के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता है क्योंकि उसको मालूम होता है कि कल को उसे थाने में ही जाना है और जब वह जाएगा तो जो बड़े अफसर है वे उसके साथ बुरी तरह से पेश आएंगें । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि पुलिस और आई बी और सी आई डी को अलग अलग रखना चाहिये ताकि बड़े से बड़े आदमी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सके ।

पुलिस थानों की जो सीमा हैं इसके बारे में भी आपको विचार करना चाहिये । साउथ एवेन्यू में अगर कोई सीमा पड़ती है और कनाट प्लेस के किसी पुलिस अफसर को फोन किया जाता है उस अवस्था में जब साउथ एवेन्यू का फोन नहीं मिलता है तो कनाट प्लेस का आदमी यह जवाब देता है कि यह उसकी सीमा में नहीं है । तब तक जो वारदात होनी है वह हो चुकती है, जो कत्ल होना है वह हो चुकता है इसकी मैं एक-दो मिसालें देना चाहता हूं । 1971 में मिस्टर जे० एस० बोधंकर, पी०एस०आई० नागपुर में थे । इनकी ड्यूटी थाने में थी तब उसने सोने गाव में स्मगलर को देखा । वह शराब का स्मगलर था । वह शराब ले जा रहा था वह ले जाई नहीं जा सकती थी, शराब ले जाना उस दिन बन्द था । उसका उसने पीछा किया और सोनेगर, दूसरे थाने के अन्तर्गत पहुंच कर उसने उसको गिरफ्तार किया । बजाय इसके कि सरकार उसकी कुछ सहायता करती, इमदाद करती, प्रोमोशन देती, उसको आज तक उसने डिसमिस कर रखा है और उसको आज तक बहाल नहीं किया गया है गवर्नमेंट ने यह दलील दी कि यह उसकी जुरिसडिक्शन में नहीं था । कोई कत्ल करे, बुरा काम करे और कोई उसका पीछा करे और उसको जाकर पकड़े और आप कहें कि यह उसकी सीमा में नहीं था तो यह उचित बात नहीं है--उसको आपने ऐसे सजा दे दी जैसे उसने कोई कत्ल किया हो, गुनाह किया हो । आज तक उसको डिसमिस किया हुआ है ।

एक पेरिस बेकरी का ओनर था नागपुर में । यह 1978 की बात है । उसने थाने में फोन किया कि उसके यहां गुंडे आ गए हैं और कह रहें है कि जो भी पैसा है हमें दे दो । उसके छोटे भाई ने फोन किया, लेकिन पुलिस स्टेशन के लोगों ने कहा कि यह जो आपका एरिया है यह हमारी सीमा में नहीं आता है । जब तक वह उस थाने में जिस की सीमा में उसका ऐरिया आता था इत्तिला दे पाता, उसकी हत्या कर दी गई। इस तरह से जो कानून में व्यवस्था है उसमें सुधार होना चाहिये । पुलिस थानों की कोई सीमा नहीं होनी चाहिये । जो भी पुलिस का सिपाही या अफसर हो, वह जब यह देखे कि क्राइम किया जा रहा है उसकी यह ड्यूटी होनी चाहिये कि वह उस क्रिमिनल को पकड़े चाहे वह उसकी सीमा में आता हो या न आता हो ।

एक सजैशन मैं यह दूंगा कि जो जेल के अन्दर व्यवहार किया जाता है, उसकी तरफ बहुत सख्ती से देखने की जरूरत है जनता पार्टी की सरकार में मुझे जेल में जाने का इत्तिफाक हुआ, वहां जो जेल में लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है, उसकी तरफ देखने की सख्त जरूरत है । मैं माननीय होम मिनिस्टर का इस तरफ ध्यान दिलाऊंगा कि खास तौर से जो औरतें होती है, वहां उनके साथ बेहूरमती की जाती है । जेल के अन्दर यह नहीं किया जाना चाहिये । जेल में जिस आदमी को बन्द किया जाये, उसके साथ शहजादे

का सलूक करें। यह मैं नहीं कहता, लेकिन कम-से-कम बेहुरमती नहीं की जानी चाहिये। उसको जो जेल में रखा है, उसका नाजायज फायदा उठाकर उसको तंग नहीं किया जाना चाहिये। मैं होम मिनिस्टर से गुजारिश करूंगा कि उसमें पार्लियामेंट की एक कमेटी बनाई जाये और खास तौर से जो औरतें हैं, बच्चे हैं या बाकी लोग हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिये।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जैसे हमारे शर्मा जी ने कहा कि जो गवर्नर्स होते हैं, जब सरकारें तबदील होती हैं, तो उसके साथ-साथ उन को भी इस्तीफा देना चाहिये, ताकि जो नई सरकारें बनें, उन्हें पूरा ओपशन मिलना चाहिये कि वह अपनी मर्जी के गवर्नर बनायें, ताकि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच जो तालमेल हो उससे अच्छी तरह से सरकार चल सके।

इन शब्दों के साथ जो होम मिनिस्ट्री की जो ग्रान्टस हैं, इनका मैं समर्थन करता हूं।

SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT (Manjeri): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am beholden to you for the opportunity afforded to me to speak on the Demands for Grants of the Home Ministry.

It is a matter of deep concern to all of us that the law and order situation in the country particularly in the City of Delhi is very much unsatisfactory. Citizens have no security of their life and property and they live under constant fear today. Just now, Mr. Makwana, the Minister of State for Home Affairs has made a speech. He has narrated the steps taken by the Ministry to arrest the crime wave in the City of Delhi; together with that, he has also asserted that the law and order position has improved in the City of Delhi. I must say that this certificate must come not from the Minister or the Home Ministry but from the citizens of Delhi who are spending sleepless nights. I am sorry, this assertion by the Home Minister will not be and cannot be substantiated by the people of Delhi today. In the circumstances I welcome the reported news in the papers that our Home Minister Shri Zail Singh has taken a very strong view about the deteriorating law and order situation prevailing today, and has consulted the Lt. Governor and senior police officers in this connection. I am told that the Home Minister was very much perturbed over this that he had pulled up police officials for the unsatisfactory law and order position. I am sure this effort of the Home Minister will bear fruit and will have positive results and the people of Delhi will have comfortable nights in future as a result of the efforts of the Home Minister.

Sir, I must say that the conscience of the people of this country is deeply shocked at the atrocities committed on the SC&ST and particularly against offences committed against women. The offences against women which are increasing in number day by day have been discussed in this House and much light has been thrown on these offences against women. Therefore, I don't think it is necessary for me to go into details in this matter. But one thing I must say that the tragedy of the whole episode is that the custodian of law and order, the protector of law and order, that is the policemen are getting more and more involved in these crimes against women. This must be stopped and the Home Ministry must act very effectively and swiftly in this connection. I am happy that the Central Government is seized of the matter and steps have been initiated to enable the State Governments to tackle law and order situation more effectively and especially to prevent and control occurrences of atrocities and offences against harijans and women I wait for the results anxiously. Offences against women, I must emphasise, is a shame, a slur and a disgrace on the entire society. It is high time that all people get fully involved in finding measures to tackle this very grave and shameful evil and put an end to the same.

The recommendations with regard to amendments to IPC and CRPC have been placed on the Table of the House. The Home Minister and the

[Shri Ebrahim Sulaiman Sait]

Law Minister have also consulted the Leaders of the Opposition on the proposed amendments. I hope very soon comprehensive legislation will be brought forward to give deterrent punishment to criminals who perpetrate atrocities against Harijan and Women and that such a legislation will be passed in this session itself.

Sir, it is a matter of great pain and anguish that the situation in Assam is getting serious day by day and is getting from bad to worse. It this explosive situation is allowed to continue it will definitely destroy the unity and integrity of the country which we love and cherish. I am afraid in this whole episode the hands of morbid, militant communal elements is very much visible. I also understand that foreign forces are also involved in this agitation. It has to be considered with all seriousness. With the killing of people and setting fire to their houses, with the completely partisan attitude of the administration and the police, with continuous agitation and the disastrous economic blockade, the government in Assam stands paralysed today; life is completely at a standstill and the people of Assam. particularly the minorities live in constant fear. That is the situation in Assam today. The efforts of the Prime Minister Shrimati Indira Gandhi, and appeals of national leaders to make the leaders of the agitation see reason, have not had any positive response. It is clear that the agitators have become today virtual rulers in Assam. Such a situation cannot be allowed to continue in the interest of the people and in the interest of the country.

It is a matter of great relief today that after having completed the three phased, agitational programmes in Assam—Assam bandh, operational stoppage of air and train services, and picketing of State, Central and semi-government offices, it is reported in today's papers that the All Assam Students Union and the Gana Sangram Parishad have now decided to suspend the agitation for two weeks from 22nd July to 3rd August. I welcome this. I am sure that this will not be for the breathing time for the agitator nor is it intended to be an eye-wash. Of course the economic blockade continues. This also should have been withdrawn. This has done more damage. I hope the agitators in Assam are really serious in withdrawing the agitation and that they will rise to the occasion and demonstrate that they are really patriots. I hope that they will now agree to come and sit round the table for negotiation in a calm atmosphere and settle this very vexed problem of foreigners in Assam in the best interest of the people of the country. That has to be done; if that is not done, the country is going to suffer very seriously. I am sure the Prime Minister will take advantage of this situation and see that a settlement is reached through negotiations and proper judicial process will be evolved. The decisions will have to be acceptable to all parties and that all parties should be taken into confidence before coming to a final solution of this problem.

I must say and reiterate at this juncture that there should not be any compromise on the question of unity and integrity of the country and the future of the minorities should be protected. This is the commitment of the Central Government. For this purpose I must insist that the CRP, BSF and the military should remain in Assam until the situation becomes completely normal. If it is not done, there is danger for the security of minorities in Assam because the minorities have no confidence in the partisan police in Assam. I must emphasise here: there cannot be any going back on 1971 as the cut-off date. In case you go back from 1971, it is going

to be brutal, impracticable and disastrous and it will go against all international commitments. It is therefore not possible to accept even the recommendation of Gandhi Foundation because they want to go beyond 1971. Starting from 1951 as cut off year is completely impractical and disastrous and therefore unacceptable. Even if you are able to detect foreigners, where will they be sent? Who is going to accept them? Therefore I have also to emphasise that it is a problem which has to be considered on humanilarian considerations also. The anti-minority character of the agitation has to be given up. None can deny that the agitation has an anti-religious minority and anti-linguistic minority character; that has to be given up. Any talk of session should be put an end to once and for all. I must insist that any settlement can be only on the basis of constitutional provisions and international commitments. In case these factors are ignored there cannot be any settlement. The settlement which is a forced one will become infructuous.

Sir, it is really tragic that the communal riots have been cutting at the very roots of our secular character and tarnishing our image abroad for the last thirty years. Thank God, for the last. So many months we did not have holocausts like the one we witnessed at Varanasi, Jamshedpur and aligarh, in 1978 and 1979. But I am sorry to say that the country has not been completely free from the communal riots. We have had communal riots recently at Allahabad. Hyderabad, and Chamrajpet and to-day's papers talk of tension at Badaun in U.P. I urge that question of communal riots should be tackled at national level. All the political parties should join and put their heads together to see that communal riots are put an end to for all time to come.

I remember a Conference was held in December, 1978 and a National level Committee on Communal harmony was set up in January 1979 by the then Prime Minister Shri Morarji under the Chairmanship of Shri Jagjivan Ram, the then Deputy Prime Minister. The Committee was asked to examine the recommendations of National Integration Council and various other enquiry commissions. Nothing has come out of this Committee so far. There has not been any progress. Now, Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi had convened a Conference of Chief Ministers and other officers and Governors in April 1980, to discuss the issue. A number of suggestions were made. These important recommendations have been given on page 9 of the Home Ministry's Report. I quote:

"(a) frequent recourse to punitive fines or recovery of the cost of quartering additional police;

(b) prompt investigation and prosecution of cases;

(c) revival of Integration Committees or Ekta Committees in various States;

(d) taking of strict action against rumour-mongering and publication of alarming news;

(e) adequate representation of minority communities in services under Government, Public Sector Undertakings and other bodies and institutions.

(f) promotion of religious and communal amity at the grass-root level, etc."

I want to know what has been done about these recommendations. Have minorities got adequate representation in military, in judiciary and in executive and in Government establishments and various public sector undertakings? After having made these recommendations what has the Government done, I want to know? This is very important.

To put down communal riots, we have to take strong measures—suspension of police officers, especially District Magistrates and District Superintendents wherever communal riots take place has to be made a must as a law.

(Shri Ebrahim Sulaiman Sait)

We must put it down that full compensation will be paid to the riot victims. A ridiculous position prevails to-day, if a person dies on account of air crash he is given Rs. 2 lakhs as compensation, but if a person dies of communal incident he gets nothing as compensation. If a person dies in a train accident, he gets Rs. 5.000, again if he dies in a communal riot he gets nothing. This difference in the value of persons lives should be stopped. It is nothing but discrimination. The riot victims should necessarily, therefore, get full compensation.

Sir, Janata Government established Minorities Commission with great fanfare in January, 1978. But this had no stautory or Constitutional status. It had come into existence by an Executive Order. The Constitution (46th) Amendment Bill 1978 was introduced for according Constitutional status to the Minorities Commission. But this could not get through as requisite majority could not be secured in the House. I would, therefore, urge upon the Home Minister, Sardar Zail Singh, to see that this Minorities Commission is given constitutional and statutory status as early as possible. A Constitution Amendment Bill should be introduced during this session itself for that purpose so that this Minorities Commission can be clothed with statutory powers and also given a Constitutional status. Also, today the Minorities Commission is not a full-fledged commission. Some members had resigned and there are some vacancies on the Commission. Therefore, I would urge upon the Home Minister to see that suitable persons enjoying the confidence of the minorities are nominated on the Minorities Commission. As I said, this Commission should be given statutory powers and Constitutional status so that it can function effectively and serve the cause of the minorities.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Before I call upon Shri Yellaiah, I remind hon. members that they should take not more than 10 minues. Otherwise, other members will not have opportunities to speak. (*Interruptions*). If the Chair rings the bell, the hon. member who is speaking must stop. Of course, it is an unpleasant task to ring the bell. We have to do it in a pleasant manner. Therefore, we may not ring the bell every now and then, but request the hon. members to conclude.

श्री नन्दी येल्लैया (सिद्दीपेट) : उपाध्यक्ष महोदय, आज गृह मन्त्रालय के सम्बन्ध में इस सदन में जो चर्चा हो रही है मैं इसका समर्थन करता हूं। गृह मन्त्रालय एक ऐसा मन्त्रालय है कि समाज के अन्दर जो कुछ भी हो रहा हो उन तमाम चीजों पर निगरानी रखने के लिए और जनता की तमाम समस्याओं को दूर करने में इसका बड़ा महत्व है। एक बात मेरी समझ मे नही आती कि जनता सरकार के समय में इतनी घटनायें और हरिजनो पर अत्याचार हो रहे थे उनका इतना प्रचार नही होता था, जितना कि अब हो रहा है। मेरी राय में इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य हो सकता है। हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा दोबारा सत्ता सम्भालने के बाद ऐसा मालूम होता है कि विरोधी दलों द्वारा न केवल दिल्ली बल्कि सारे देश में श्रीमती गांधी की सरकार को बदनाम करने के लिये एक माहौल पैदा किया जा रहा है। इससे पहले यहा पर जब चौधरी चरण सिंह की काम चलाऊ सरकार थी तब भी हम सुनते थे कि वे अपने आपको समाजवादी कहते हैं। मै लोग यहां पर आज भी हरिजनो के उत्थान के भाषाण देते हैं, लेकिन इस डेमोक्रेटिक कन्ट्री में आज भी हरिजन भाइयो को अपनी राय देने से रोका जाता है। हरिजनो और आदिवासियों पर यह दबाव सदियों से है, यह कोई नई बात नही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हू कि एक जमाना आयेगा, जब हरिजम जातियो पर जो गावो में और शहरों में रिजर्वेशन में नाइन्साफी होती है, वह पूरी होगी। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जिस वक्त देश में इमरजेंसी का एलान किया था, उस वक्त देश की हालत बहुत ही खराब थी, देश में विभिन्न प्रकार के खतरे थे। मैं आज दावे के साथ कहता हुं कि 30 साल आजादी के बाद अगर हरिजनो में जागरूकता आई है अगर हरिजनों में परिवर्तन हुआ है, तो वह केवल इमरजेंसी के शासन काल में ही हुआ है। पहले गांव में रहने वाला हरिजन तहसीलदार के पास नही जा सकता था, पटवारी के पास नहीं जा सकता था, और उनको वोट डालने के अधिकार से वंचित रखा जाता था, उनको वोट डालने नही दिया जाता था, वहां का पटवारी यदि बैल पर कहता था, तो वे बैल पर निशान लगाते थे और यदि गाय पर कहता था तो गाय पर निशान लगाते थे। यह स्थिति किसी जमाने में थी। इमरजेंसी लगाने के बाद जमीनों के बटवारे के काम में भी काफी परिवर्तन हुआ था। लेकिन जनता पार्टी के राज में मैं समझता हूं कि हरिजनों के उत्थान के लिए, हरिजनों के विकास के काम में रुकावटें आई हैं। मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हम हरिजनों की तरक्की करना चाहते है, समाज

के अन्दर उनके ऊपर जितने अन्याय हो रहे हैं, ना-इन्साफी हो रही है, उसका कारण यही है कि उनके अन्दर शिक्षा अभाव है, इसके बिना समाज में हम उन की तरक्की नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हरिजन आदिवासियों को मैट्रीकयूलेशन तक कम्पलसरी शिक्षा दी जाए, तभी वे समाज के अन्दर जो नाइन्साफियां हो रही है, उनका मुकाबला कर सकते है, ठोस मुकाबला कर सकते हैं।

आज हम क्या देख रहे हैं, देश में लां एंड आर्डर के सिलसिले में बहुत सी बातें कहीं जाती हैं और श्री धनिक लाल मण्डल, हमारे भूतपूर्व गृह राज्य मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि इस देश में छोटे आदमी का कोई स्थान नही है। लेकिन मैं उन को बताना चाहता हूं कि उन्ही छोटे आदमियों की वजह से उन्ही बीकर सेक्शन माइनोरिटीज की वजह से हमारी सरकार सत्ता में आई है। मैं आपसे पूछना चाहता हू कि जब देश में जनता पार्टी की सरकार बनी, तो आपने क्या किया ? आपने केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ और स्व० संजय गांधी के खिलाफ शाह कमीशन बनाए, जिनमें देश का लाखों रुपया बर्बाद किया गया। अपने शासन के दौरान आप लोग आपस में लड़े आपके पास शासन की कोई नीति नही थी। जैसा कि हमारे गृह मंत्री श्री जैल सिंह जी ने कहा— एक दल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। इस तरह की बातें चली। यह मैं नही कह रहा हूं, यह माननीय गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से अनुरोध करना चाहता हूं कि जनता शासन काल में भारत के अन्दर हमारे समाज की जो परिस्थिति थी उस से लोग बहुत निराश हो चुके थे। लेकिन श्रीमती इन्दिरा गांधी के आने के बाद उस में काफी सुधार हुआ है, परिवर्तन हुआ है और लोगों में यह विश्वास पैदा हुआ है कि ये गरीबो के लिये कुछ कर सकती हैं और कर रही हैं। मैं गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जहां पर ऐसी चीज होती है, ना-इन्साफी होती है, औरतों पर अत्याचार होते हैं, उन के मुजरिमों को खासतौर पर दण्ड दिया जाना चाहिये। हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्य यहां पर बहुत सी बात कहते हैं लेकिन बाहर जा कर देखें कि क्या हो रहा है, इस के लिय जिम्मेदार कौन है कौन करा रहा है, इस का कलर क्या है ? वे अखबारों को ले कर आते है और यहां पर पेश कर देते है ; ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन को ठीक करने में मदद करना सभी राजनीतिक दलों के माननीय सदस्यों की जिम्मेदारी है। हर एक आदमी का फर्ज है कि वह इस काम में सरकार की मदद करे। आज हर एक आदमी की रक्षा करना सरकार का फर्ज है और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जरूर इस में कामयाब होगी।

मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The golden example of Mr. Yellaiah should be followed by all.

Now, Mr. Janardhan Poojary.

SHRI JANARDHANA POOJARY (Mangalore): Sir, I rise to support the Demands for Grants of the Home Ministry.

I heard with rapt attention the speech of the former Minister of State for Home Affairs, Shri Dhanik Lal Mandal. At the outset, he has stated that he was against granting a single naya paisa to the Ministry of Home Affairs. I just ask him whether it is because of the crimes or the sins committed against the people of this country during their regime. I can say that the Janata Party people did not understand the implication and also the importance of the Home Ministry. They did not understand that the Home Ministry is the backbone of the governmental structure. They did not understand that the performance of the Home Ministry depends on the security, peace, prosperity and also the progress of the nation.

Sir, it is the responsibility of the Home Ministry not only to frame the rules, but also to redress people's grievances and also to bring justice to the common man. They thought it is the responsibility of the Home Ministry only to maintain law and order. There they have utterly failed. You know the era of despondency, the era of frustration, and the era of demoralisation. Further, I would submit that, you know the people reiterated their faith in the democratic values, they asserted their right to reject the people's representatives when they came to know that these leaders were misusing the powers given to them by the people of this country themselves. Now, we have found that there is a conspiracy prevailing in this country to overthrow the present Government. How they are doing it? There is a conspiracy, there is a trap laid by the Opposition people—not only the Opposition people, but some other elements also in this country. Why are they doing it? We have to dissect the conspiracy we have to analyse as to why they are doing. First of all, I would bring to your notice the Assam situation. I am just

[Shri Janardhana Poojary]

referring to the report that has appeared in the Hindustan Times, which says:

"Assam stir costs Rs. 10 crores a day. The country is losing Rs. 300 crores per month on account of a prolonged Assam agitation, Rs. 100 crores by way of petroleum products and Rs. 200 crores indirectly through the loss of essential products like fertilizer, cement, steel, according to the official estimate"

Now, I am just bringing to your notice that we have lost so far Rs. 3,000 crores because of this agitation in Assam. I am asking the opposition people whether this factor is not going to affect the economy of the country, whether with this amount we could not have wiped out the deficit in our rational budget, whether we could not have prevented inflation in this country with this amount?

18.00 hrs.

You know what is going on in Assam. These misguided students and also anti-social elements are ruining the life and property of the people. Thousands of shops and houses have been burnt. People have been put to great difficulty. But that has been done with deliberate intention. If at all the opposition parties are interested in the economy of the country, in the integrity of the nation, in the security of the nation, why can't they go to Assam and tell the students there...

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): We are fighting there.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is 6 O'Clock now. There are 25 to 30 hon. Members to speak from the ruling party and 10 Members from the opposition have also got to speak. What is the sense of the House?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): May I make a submission through you to the House? Since this is a very important Ministry and many Members want to participate from both sides, I only request that the time be extended up to 8 O'Clock.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Minister is going to reply only tomorrow. First we will extend up to 8 O'Clock. Even if we extend up to 9 O'Clock, I am afraid nobody sticks to time.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Nine O' Clock will be too much.

MR. DEPUTY-SPEAKER: If you are not in a position to sit, others will sit.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Only those who want to speak.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You agree till 8 O'Clock now.

SHRI JANARDHANA POOJARY: As I stated earlier, if at all the opposition people are interested in the integrity and the security of the nation, if at all they have the courage, let them go to Assam and tell the students and the anti-social elements that they are doing something which is not only injurious to the security and integrity of the country but also to the country's future.

As so many Members have stated earlier, a large number of houses and shops have been set on fire, and a large number of people have been murdered, causing disorder and chaos in that part of the country. So, it is the duty of the Home Ministry to ask the misguided students and anti-social elements to behave properly. It is also the duty of the Home Ministry to tell them that they must abide by the Constitution, that all citizens have the right to live in any part of the country. Otherwise, linguistic minorities will be put to hardship and the integrity and the security of the nation will be jeopardised. If this agitation is continued for another two months, the country is going to lose Rs. 3,600 crores. If this aspect is neglected, our country will be brought into an economic precipice and nobody will be able to save us. I

am therefore requesting the Home Minister to deal with the agitationists sternly. He must tell the students that this is not the proper way.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri): One clarification. The hon. member in his speech has said that the members in the Opposition had a hand in Assam agitation. There are so many opposition parties. I would like to know—otherwise, it would go on record and it would appear as though we have consented and we have not opposed—as to which party the hon member is referring.

SHRI JANARDHANA POOJARY: I am not yielding.

That is one conspiracy. What was the statement of Mr. George Fernandes before the Consultative Committee attached to the Ministry of Home Affairs. He has gone to the extent of saying that there is a nation of 2.3 crores of people and you cannot overlook the fact that here is a man.....

SHRI DHANIK LAL MANDAL (Jhanjharpur): I may clarify that Mr. Fernandes does not know Hindi well. He has picked up Hindi from the roadside. He used the word 'Kaum' which has different meanings. It means, 'Janata', 'people', it also means 'country'. That was explained in the meeting itself and the Home Minister has accepted it. The hon. member should not doubt the integrity and patriotism of Mr. Fernandes. How can he say this?

MR. DEPUTY-SPEAKER: He can express his views.

SHRI JANARDHANA POOJARY: If that is the case, Mr. Fernandes should have contradicted the press report, which he has not done so far. We cannot forget the Baroda dynamite case. Mr. Fernandes himself had confessed that he was responsible for those 53 explosions. There is a conspiracy to overthrow the present Government. We must be careful about it. There is another aspect of the conspiracy—demoralisation of the police force. The police are always being criticised both inside and outside Parliament. That naturally leads to demoralisation in the police force. Uncertainly and fear has gripped the police. They are agitating to let them adopt the conventional methods of interrogation in dealing with the hardened criminals. Now they do not know as to what methods of interrogation they should adopt. Sitting in a very pleasant and safe environment, we can criticise them. But we should not forget that the police have to deal with the hardened criminals of every kind and they have also to deal with the, violent, indisciplined mob. They have to control the unruly mob. By demoralising the police, they are encouraging the lawlessness, bringing chaos in the country.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Poojary, you please sit down.

Shri Harikesh Bahadur.

SHRI JANARDHANA POOJARY: Just 2-3 sentences.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That will not be recorded. Whatever Mr. Poojary speaks will not go on record. I am not permitting him. When I ring the bell, the hon. Member will sit down. Otherwise, I will call the next member. You must excuse me.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: (Badagara): First bell or second bell?

MR. DEPUTY-SPEAKER: When I ring the first bell, you will immediately sit down or else I will call the next member. I have to accommodate all the members.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: Normally, it is always after the second bell.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your suggestion is accepted.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: It is not a suggestion it is a practice of the House.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मुझे आपने जो समय दिया है उस में से एक मिनट निकल चुका है । इसलिए जब आप घन्टी बजाएं तो एक मिनट उस में और जोड़ लेने की कृपा करें । •

सब से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि आज देश में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है । न यहां गृह मंत्री उपस्थित हैं और न राज्य मंत्री । कोई इस बात की परवाह ही नहीं करता है कि सुना जाए कि क्या बोला जा रहा है । कोई कैबिनेट रैंक का मंत्री इस समय यहां नहीं है । इसके लिए इस सरकार की जितनी बड़ी निन्दा की जाए कम है । इस सरकार को मैं इस बात के लिए निन्दा और भर्त्सना करता हूं ।

जिस शासन में प्रधान मंत्री तक सुरक्षित न हों, धर्म गुरु तक सुरक्षित न हों वह शासन भी क्या शासन है ? क्या सचमुच में आज देश में कोई कानून और व्यवस्था की स्थिति है ? प्रधान मंत्री के ऊपर इसी पार्लियामेंट हाउस के बाहर छुरा फेंका था । धर्म गुरु, निरंकारी लोगों के प्रमुख धर्म गुरु की हत्या कर दी गई । आज लोग कानून और व्यवस्था की बात करते हैं । लेकिन वास्तव में इस देश में कोई कानून और व्यवस्था नाम की चीज इस समय नहीं है ।

जिस शासन में संसद सदस्यों के घरों में चोरियां हो रही हों प्रो० मधु दंडवते, प्रो० सोम नाथ चटर्जी, श्री ज्योतिर्मय बसु और आज जो कांग्रेस पार्टी के संसद सदस्य जो 22 मीना बाग में रहते हैं उन के घर में भी चोरी हो गई है, वह शासन भी कोई शासन है ? आप लोग सदस्यों को भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं तो जनता को कैसे करेंगे ? मैं जानता हूं कि मेरी बात आप को कड़वी मिर्च की तरह लगती है किन्तु उसे सुनिये । जिस शासन में मंत्री के साथ पुलिस का दरोगा सही ढंग से व्यवहार न करता हो वह भी शासन कोई शासन है ? मंत्री जी बैठे हुए हैं मकवाना साहब । वह चाणक्य पूरी के थाने में गए और उन्होंने कहा कि वहां के दारोगा ने उनके साथ कर्टियसली बिहेव नहीं किया .....

SHRI YOGENDRA MAKWANA: For your information and benefit, I may point out that there was no misbehaviour on the part of the police officer. But it was only because he took action late that he was transferred.

श्री हरिकेश बहादुर : जिस शासन में विधायक ताला तोड़ कर लोगों के मकानों पर कब्जा कर रहे हों वह भी शासन कोई शासन है ? उस शासन में क्या कोई कानून और व्यवस्था नाम की चीज है ? लखनऊ के अन्दर एक विधायक ताला तोड़ कर मकानों पर कब्जा कर रहे हैं । जिस शासन में पुलिस महिलाओं पर अत्याचार कर रही हो, महिलाओं के साथ बर्बरता के साथ पेश आ रही हो वह शासन भी कोई शासन है ? उस शासन के लिए यह एक महान शर्म की बात होनी चाहिये । मैं घटनाओं में जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि समय का अभाव है । बागपत कांड हुआ है । बाराबंकी में हुआ है । झांसी में हुआ है एक पी ए सी के अफसर ने एक महिला के ऊपर अत्याचार किया है । पूर्णिया के अन्दर एक हरिजन महिला के साथ बलात्कार हुआ है । उन्नाव के अन्दर हुआ है । बांदा में हुआ है । दरभंगा सी आर पी और बिहार मिलिटरी पुलिस के लोगों ने एक हरिजन पर अत्याचार किया । दिल्ली में जय प्रकाश नारायण अस्पताल में एक महिला के ऊपर अत्याचार हुआ है । मुरादाबाद के पुलिस स्टेशन में महिला के ऊपर अत्याचार हुआ है । इस तरह के कांड चारों तरफ हो रहे हैं और बहुत ज्यादा हो रहे हैं लेकिन पुलिस के खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं । आज तक बागपत कांड के लिए दोषी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड नहीं किया गया है । मैं समझता हूं कि वास्तव में पुलिस के अत्याचारों को रोकथाम करने के लिए जैसा हमारे भूतपूर्व गृह मंत्री श्री धनिक लाल मंडल जी ने कहा है एक स्थायी आयोग की स्थापना आपको करनी चाहिये । मैं कहना चाहता हूं कि जिस शासन में हरिजनों पर पुलिस अत्याचार कर रही हो, इसमें जितने बताये हैं उनमें बहुत से हरिजनों के मामले हैं, उसके अलावा हरिजनों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं--कफलटा कांड, हाथरस कांड, कानपुर में अनेक हरिजनों के घर जलाये गये, बलिया में एक हरिजन महिला की हत्या हुई, आंध्र प्रदेश में 4 हरिजन मारे गये, बंगलौर में हरिजनों पर लाठी चार्ज हुआ, मध्य प्रदेश में बहुत से हरिजन मारे गये, बिहार में हरिजनों पर घोड़ा दौड़ाकर हत्या की गई और फिर गोली मार दी गई ।

आज जब कुछ संसद सदस्यों ने इस सवाल को यहां उठाना चाहा, तो माननीय स्पीकर साहब ने इसकी अनुमति नहीं दी और कहा इसी समय बोलने के लिये, इसलिये बोल रहा हूं । इस प्रकार करसुनभा में यह घटना हुई है, जो कि बहुत ही दर्दनाक है । हरिजनों पर पुलिस ने घोड़े दौड़ाये और बाद में जब वह चोट से कराह रहे थे तो उन्हें गोली से उड़ा दिया गया । आज इस शासन में यह काम हो रहा है, यह मैं कहना चाहता हूं ।

जो शासन चुनाव में धांधली कराता है, इलेक्शन में भयंकर रेगिंग हुई है । उत्तर प्रदेश का मैं एक कांड बताना चाहता हूं । वहां के देवरिया जिले के अधिकारी ने चुनाव में बहुत भ्रष्टाचार किया । जब वोटों की गिनती के समय

कुछ बैलट-बाक्स की सील टूटी पाई गई, तब कई लोगों ने, जिनमें उम्मीदवार भी सम्मिलित थे, आपत्ति उठाई तो उस जिलाधिकारी ने उम्मीदवार सहित बहुत से लोगों को पिटवाया और अवैध तरीके से वोटों की गिनती करवाई। क्या सरकार उस मामले की जांच करेगी और दोषी जिलाधिकारी को दंड देगी ?

इसी प्रकार से चारों तरफ चुनाव में धांधली हो रही है, लेकिन यह रोकना नहीं चाहते । मैं चुनाव में धांधली का एक और किस्सा बताना हूं । उत्तर प्रदेश के ही गोंडा जिले में एक विदेशी पादरियों का मिशन है, उस मिशन के फादर पीटर व फादर बची नार्वेट कई चुनावों में मतदाता बने रहे और कांग्रेस को वोट देते रहे । जब इन लोगों के बारे में जानकारी हुई कि ये वास्तव में भारत के नागरिक नहीं हैं, जब गोंडा के जिले के लोगों ने इस सवाल को उठाया और उन्होंने देखा कि अब कि बार वोट नहीं दे पाएंगे, तो किसी तरह से मतदाता सूची में नाम कटवा लिया। क्या सरकार सुनिश्चित करेगी कि ऐसे लोगों का नाम जो कि भारत के नागरिक नहीं हैं, मतदाता सूचियों से हटें ? यह नहीं हटाना चाहेंगे क्योंकि ऐसे ही लोगों से इनको वोट मिलता है, तभी इनकी सरकार बनी हुई है ।

जो सरकार अन्धों पर लाठी चार्ज करवाये, क्या वह शासन देश में कानूनी व्यवस्था दे सकता है । अन्धे प्रधान मंत्री से मिलने जा रहे थे उस दिन जब कि अन्तर्राष्ट्रीय दिवस विकलांगों का मनाया जा रहा था । उसी दिन इस शासन के लोगों ने पुलिस द्वारा अन्धों पर लाठी चार्ज करवाया ।

जब इस तरह के तमाम समाचार अखबारों में निकलते है तो हमारे सूचना प्रसारण मंत्री कहते हैं कि प्रेस के लोग आजकल रेप के केसेज को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं । इतना दर्दनाक और भयंकर अत्याचार महिलाओं पर हो रहा है और जिसके लिये शासन का सिर शर्म से झुकना चाहिये, वहां के मंत्री ऐसा कहते हैं । प्रेस के लोगों को हम सभी को धन्यवाद देना चाहिये कि वह ऐसी बातें प्रकाश में लाते हैं । आज कहा जाता है कि प्रेस के लोग क्यों इस तरह की बातें सामने लाते हैं।

इस शासन में ट्रेन में डकैतियां पड़ रही हैं, जगह-जगह लोगों के घर लुट रहे हैं, हत्याएं की जा रही हैं, चारों तरफ साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं, चाहे इलाहाबाद हो, मुरादाबाद हो, अहमदाबाद हो या हैदराबाद हो। हर जगह कांग्रेस (आई) की सरकारें हैं और हर जगह दंगे चल रहे हैं । यह सारी चीजें आज हो रही हैं उनको रोकने के लिये ये क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

देश पूरी तरह से अराजकता की तरफ जा रहा है । उत्तर-पूर्वी भारत को ले लीजिये । कोई भी राज्य शायद ही ऐसा इस समय बचा हो जहां कि स्थिति खराब न हो गई हो । त्रिपुरा में भयंकर नर-संहार हुआ है, वहां की सरकार ने पुलिस मांगी, लेकिन आपने पुलिस नहीं दी । आपकी इंटेलिजेंस एजेन्सी बिल्कुल फेल रही । अगर उन्होंने सूचना आपको दी तो आपने कोई सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की । 5,000 आदमी लगभग मार दिये गये हैं, इस बात की क्या गारन्टी है कि दूसरे प्रदेशों में आप इस चीज़ को रोक सकेंगे । असम की क्या स्थिति है, सारे लोग जानते हैं । मणिपुर की विधान सभा के अहाते में डकैती पड़ी । उसमें कितने ही लोग मारे गये और डाकू तथा विद्रोही कितने ही बंदूकें छीन कर ले गये। सरकार ऐसी घटनाओं की रोक-थाम नहीं कर पाई है । नागालैंड के एक संगठन ने कहा है कि नागालैंड की लिबरेशन के लिए एक प्रोट्रेक्टिड वार शुरू करनी चाहिए । सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है ।

SHRI P. A. SANGMA (Tura): I rise to support the Demands for Grants in respect of the Ministry of Home Affairs. I was thinking whether I should make a speech at all before I put myself and you, Sir, to embarrassment. I think I will take less time than you have allowed me and leave whatever is left of my time to my friend here, Shri Manoranjan Bhakta as coming from a Union Territory he wants more time.

Shri Ram Jethmalani spoke very eloquantly of insecurity and the uneasy feeling of fear in the minds of people of this country after our government came into being. But I think he left the House without telling the most important thing which he wanted to tell and that was that during the 2½ years of the Janata rule the people of this country felt very secure and very safe! That part he forget to tell.

Now he also speaks about the act of irresponsibility by the present government. I want to give only one example of how responsibly the Janata government acted during their regime. Many members of the opposite side have brought out many points about the atrocities on Harijans and all that. Now, the Belchi incident took place on 27-5-77 and the hearing of the case started on

[Shri P. D. Saugma]

5-2-1980, that is, after 2½ years whereas in the case of an incident which has recently happened in Pipra, the incident took place on 25-2-80 and the hearing started on 8-4-80, that is, only after 1½ months. Therefore, I do not know how they are going to justify this. that they are acting very responsibly and our government has been acting very irresponsibly.

Mr. Jethmalani also spoke that the turmoil in the north-east started only after Mrs. Gandhi came into power. I do not know how much he knows about the north-east. For his information, the turmoil in the north-eastern region started much before this government came into being. He forgets that except two Members, we do not have any representatives from Assam in this House. This turmoil started before the last Lok Sabha election. I do not know how he has said that this turmoil started after this government came into being.

We must tell this House that we the people from the North-east region really feel that we have been neglected for many years. But one thing I want to put on record. Whatever status we enjoy to-day in the political, social or economic field, I must say, is because of Prime Minister Shrimati Indira Gandhi. You remember that we the people in the north-east was a component part of Assam. My community never had any representation in this House. So also Mizoram. And it was Assamese people who were representing the entire north-eastern region in this House. But it was Prime Minister Indira Gandhi who gave separate statehood for Meghalaya. It was she who created Mizoram. It was she who created Arunachal Pradesh. It was she who created Manipur and it was also Shrimati Indira Gandhi who gave statehood to Tripura. So, if we have any political status or social status to-day in this country, it is because of Prime Minister Indira Gandhi.

I want to give a few suggestions. As I said, I do not want to take much time of the House. As far as North-Eastern region is concerned, I have some serious suggestions to make for the consideration of the Home Minister. My hon. friend, Shri Chingwang Konya had suggested a few hours back that in order to solve the problem of the North-Eastern region, a separte ministry should be created for this part. I suppport this suggestion. In fact this had been voiced by the people of the north-eastern region for quite some time. Therefore, I would urge upon the Prime Minister to create a separate ministry for the North-Eastern region. For some reason or the other, if it becomes difficult for the Government of India not to do so, I would give an alternative suggestion that there should be a separate ministry under the charge of the Prime Minister, for the welfare of scheduled castes and scheduled tribes and other minorities. In that ministry, there should be a separte cell to look after the North-Eastern region because a major portion of that region is inhabited by the people belonging to the scheduled tribes.

Another important point that I want to make is this. There are five States in the north-eastern region and for these five States, we have a Common Governor. Under the present conditions that are prevailing in that region to-day, I would earnestly urge upon the Government of India to appoint a separate Governor for these five States because it is very difficult for one person to look after such hig areas. The population in that part of the country may be less but because of transport bottlenecks it is realy difficult for a single person to look after the whole of the north-eastern region.

Then, there is a difficulty from the constitutional point of view. Mr. Chingwang referred to the boundary dispute between Assam and Nagaland, between Assam and Meghalaya and between Assam and Arunachal Pradesh and between Assam and Mizoram. With all these States, we have got

boundary disputes. It so happens that the Governor will address the Assam Assembly talking against Meghalaya and in Manipur he may speak against Nagaland and when he adresses the Nagaland Assembly he may speak against the Assam Government and *vice-versa*. While so doing, he may contradict himself in the other Assembly. So, from the constitutional point of view, it is somewhat impractical for all the five States to have a common Governor in the North-Eastern Region. Therefore, I would again urge upon the Government to appoint separate Governors for different states in the North-Eastern region. Government of India was very kind to constitute the North-Eastern Council for looking after the development of the entire region. Somehow I have doubts about the smooth functioning of the North-Eastern Council. Now in many of the regional councils and other bodies, Members of Parliament are associated. But, in this particular North-Eastern Council, no member of Parliament is associated so far.

I would urge upon the Government—Home Ministry—to see if it would be possible to have a representative or two from among the Members of Parliament, belonging to the North-Eastern Region in that Council.

Many Members have spoken about the Mizoram prablem. Well, I am happy that Government of India, the Prime Minister and the Home Minister are taking keen interests in the development of Mizoram. There have been talks in that regard. According to newspaper report, talks are on between Mr. Laldanga and Government of India for finding a peaceful solution to the Mizoram problem. I welcome this move. But, I want to warn the Government of India that there are people who are trying to see that these negotiations do not materialise.

I think that this group is represented by no less a person than Brigadier Sailo himself who is the Chief Minister. Therefore, I would caution the Government of India that there should be no person standing in the way of peaceful negotiations.

One more point I want to make. That is regarding the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders of 1951 and 1976. There are many communities who had been recognised as Scheduled Castes and Tribes in one State but they have not been recognised as such in other States. I urge upon the Government to remove this area restriction. For example, my community, Garo community, is recognised as a scheduled tribes community in Meghalaya, in Nagaland and even in West Bengal but we are not considered as scheduled tribes in Assam. We have got one lakh population of Garos in Assam but we are not recognised as scheduled tribes in Assam. In Assam Hajang are not recognised as scheduled tribes but they are recognised scheduled tribes in my State. There are communities in my place like Ravas and Koch which have been recognised as scheduled tribes in some other places but in my place they are not recognised as scheduled tribes. So, I would like the Government to consider this point and bring legislation towards the amendment of this order and remove the restrictions so that everybody is treated on an equal status through out the country.

With these words I support the demands of the Ministry of Home Affairs.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad): Mr. Deputy Speaker, Sir, now unfortunately in this House when we are talking we are not speaking to each other, we are talking to the entire world. Everyday in some form or the other rape and other things are brought in the House and discussed. I am disgusted, the whole world thinks that this nation consists of all repists. Therefore, I want that Members should have some restraint

[Shri M. Gopal Reddy]

and whenever there is a genuine complant they should write to the concerned Minister. I wrote once to Shri Zail Singh when he was Chief Minister. The house of one Mr. Jagga was demolished during Emergency time and he approached me and in that connection I wrote to him. I quote here the reply sent by him:

"I am in receipt of your letter dated 6th September, 1976. On your letter handed over to me, in January a regular inquiry was conducted by the local self-government departement and it was decided that full compensation be paid to Shri Chanan Ramji Jagga of Muktsar for the damages caused to his house by the Municipal authorities of Muktsar. I have asked the Inspector General of Police to give protection to Shri Jagga."

Now, this is the way how Members of Parliament should function. So, I request the Members whenever such things come to their notice a simple letter to Shri Zail Singh is enough and all these speeches are unnecessary. We should have full faith in him. Unfortunately, he has become Home Minister of this country in very adverse circumstances and I appeal that the House should appreciate the good work that he is doing.

श्री शिव प्रसाद साहू (रांची) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, माननीय गृह मंत्री द्वारा इस सदन में प्रस्तुत अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे देश का एक प्रान्त बिहार है और छोटा नागपुर उस प्रान्त का एक भाग है। छोटा नागपुर में क्या चीज नहीं है, वहां पर तांबा, कोयला, यूरेनियम, लोहा—यह सारी चीजें हैं। लेकिन मैं वहां की जो दर्दनाक कहानी सुनाने जा रहा हूं वह आपको इस देश के किसी भी कोने में सुनने को नहीं मिलेगी। छोटा नागपुर में दो जिले है—रांची और पलामू। वहां पर बहुत ही गरीबी और अशिक्षा है, मैं खासकर पहाड़ी क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, शहर की बात नहीं करता, रांची तथा पलामू जिले में खासकर उरांव जाति के लोग हैं, मुण्डा जाति के लोग हैं, उन में शिक्षा का बिल्कुल ही अभाव है। मैं समझता हूं 25 प्रतिशत भी उनमें शिक्षा नहीं है तथा वहां पर इतनी गरीबी है कि लोग दाने दाने को मोहताज रहते हैं। इसी वजह से बाहर के लोग नजायज फायदे उठा रहे हैं। हमारे जिले में पंजाब से, कानपुर से, असम से, बंगाल से, बड़े-बड़े ठेकेदार आते हैं और वहां की महिलाओं को, वहां के लोगों को झूठा आश्वासन देते हैं कि तुम हमारे साथ काम करने के लिये चलो, हम तुम्हें काफी मजदूरी देंगे। नासमझ लोग उनके साथ जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन ठेकेदार लोग उनको रुपए का लालच देते हैं और जवान लड़कियों को बहकाया जाता है। इस तरह से प्रति वर्ष दो लाख से अधिक आदमी नवम्बर से जनवरी महीने तक, रांची और पलामू के कुछ हिस्सों से उन ठेकेदारों के साथ चले जाते हैं। नतीजा यह होता है कि उनके पिता नहीं होते, उनके गारजीयन नहीं होते और वे बनारस, इलाहाबाद, पंजाब, त्रिपुरा आदि राज्यों में चले जाते हैं। वहां हमारी जवान बहनों के साथ इतना भयंकर दुर्व्यवहार होता है इतना ज्यादा उनके साथ अनाचार होता है, जिसको बयान यहां नहीं किया जा सकता है।

मैं "हिन्दुस्तान" पेपर का एक उदाहरण आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं—"अधिकृत सूत्रों के अनुसार त्रिपुरा की पुलिस ने एक विशेष-अभियान चला कर उन 212 आदिवासी महिला श्रमिकों को अनैतिक व्यापार के दलालों के पंजे से बचाया है, जिन्हें बिहार से यहां उक्त व्यापार के लिए लाया गया था। इनमें से 120 महिलायें हैं और अधिकांश अविवाहित हैं।

सूत्रों ने बताया है कि मुख्य रूप से मुण्डा और उरांव कबीलों के इन महिला श्रमिकों को बिहार के सूखाग्रस्त जिले छोटा नागपुर के विभिन्न भागों से दक्षिण त्रिपुरा में ईंटों के भट्टों पर लाया गया था। इनमें से कुछ लड़कियों को तो रांची के इलाके से अपहृत करके लाया गया था और कुछ को असम के चाय बागानों में रोजगार दिलाने के बहाने से फुसला कर लाया गया।"

ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अभी हरिजन महिलाओं के साथ जो काण्ड हुआ, उस पर सदन में इतना बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन उधर त्रिपुरा के एक गांव में 120 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, क्यों हुआ? इस पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। वे लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं, उन के अन्दर शिक्षा का अभाव है—इस तरह की सारी बातों को देखना चाहिए। आप नवम्बर महीने से बनारस से शुरू करें और पंजाब तक चले जांय, उधर बंगाल के हिस्सों में चले जाय, जितने भी ईंट के भट्टे हैं उन सब में उरांव और मुंडा जाति के लोग काम करते हैं और उन के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, यह कितनी शर्मनाक बात है। अगर यही स्थिति रही तो उरांव और मुंडा जाति का जैनरेशन ही चेन्ज हो जायगा। नवम्बर के महीने में होटलों में

आप देखिएगा तो हजारों-हजार जवान बहनें खड़ी रहती हैं और ठेकेदार आते हैं, पुलिस के कर्मचारी खड़े रहते हैं, उन बहनों के साथ बलात्कार होता है। ट्रक के ट्रक उन को भट्टों में ले जाते हैं। मुझे पुराना जमाना याद आता है जब अरब में गुलामों की बिक्री होती थी। ये बातें नहीं रोकी गईं तो बड़ी मुश्किल हो जायगी. मैं क्या कह सकता हूं। इस का कारण—बेरोजगारी, भुखमरी और शिक्षा का अभाव है। उन के लिए रोजगार मुहिया कराना होगा, शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी।

ये दोनों जिले रत्नगर्भा का इलाका हैं, लोहारडगा और पलामू के कुछ हिस्से हैं जहां एशिया का बाक्साइट का सब से बड़ा भण्डार है, देश का 75 प्रतिशत बाक्साइट वहां से निकलती है। लोग वहां पर फैक्टरी खोलना चाहते हैं, लेकिन बड़ी रेलवे लाइन के अभाव में खोल नहीं पाते हैं। इस प्रश्न को मैंने कई बार यहां उठाया है। यदि आप रेल की सुविधा देंगे तो लोग वहां पर अपने कारखाने खोलेंगे। जिस से उन इलाकों के लोगों को काम मिलेगा। यदि यह नहीं हुआ तो लोग भुखमरी के शिकार होंगे। मैं आप से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में दूसरा कोई इलाका नहीं है जहां के 2 लाख लोग दूसरी जगहों पर भाग कर काम पाने के लिए जाते हैं। संसार में कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। अगर यह शोषण और अन्याय नहीं रोका गया, तो वहां पर स्थिति बहुत भयंकर हो जायगी।

अब मैं कुछ सुझाव आप को देना चाहता हूं। छोटा नागपुर की आबादी तकरीबन 1 करोड़ है और छोटा नागपुर से बिहार को रेवेन्यू तकरीबन 70 प्रतिशत मिलता है, लेकिन आदिवासियों पर केवल एक-चौथाई खर्च होता है। सभी कल-कारखाने यहां पर हैं, जैसे टाटा, एच० ई० सी० का कारखाना या दूसरे कारखाने। इन सभी में नौकरियों में उन के लिए 25 प्रतिशत रिजर्वेशन रखा गया था। जहां तक मुझे जानकारी है, उन कारखानों में एवं सरकारी नौकरी में अभी तक 5 परसेन्ट लोगों को भी रोजगार नहीं दिया गया है। पुलिस में, रेंजर में और दूसरे महकमों में इन को नहीं लिया जाता है। ऐसा क्यों होता है यह देखने की बात है। कुछ हमारे मिशनरी भाई हैं, उन में काफी लोग शिक्षित हैं, लेकिन जो उरांव और मुंडा कबीलों के लोग हैं, उन में शिक्षा का बहुत अभाव है और बहुत गरीबी है। इसी लिए वहां बराबर डकैतियां होती हैं, क्योंकि युवक बेकार हो रहे हैं। हमें इन सारी बातों को देखना होगा, अन्यथा बहुत सी कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी—यह सर्वविदित बात है। आज बेकारी की वजह से छोटा नागपुर में अलगाव की भावना पनप रही है। जिस तरह से असम और दूसरे हिस्सों में अलगाव ... पैदा हुई है, उसी तरह से छोटानागपुर में भी यह भावना पैदा हो गई है कि उस का भी अलग प्रान्त बने। समय रहते इस को नहीं देखा गया और शोषण नहीं रोका गया तो एक बड़ा भयंकर तूफान उठने वाला है—जिस की ओर मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

कल के पेपर में निकला है—श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने भी स्वयं इस बात को माना है कि हरिजन और आदिवासियों के लिए जो रुपया मुहैया किया जाता है, अधिकारीगण उस को ठीक तरह से खर्च नहीं करते हैं, दूसरे मदों में खर्च कर देते हैं। ये अधिकारी पहाड़ों पर जाना नहीं चाहते। उन के साथ ठीक तरह से सुलूक नहीं करते। इन लोगों के साथ इतना खराब सुलूक किया जाता है कि उन को "अरे उरांव, अरे मुंडा"— इस तरह से पुकारते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने अधिकारियों को हिदायत दें कि वे भी मनुष्य हैं, उन के साथ मनुष्यता का व्यवहार होना चाहिए और वहां ऐसे अधिकारियों को भेजिए जो उन की भावनाओं को समझें। वे पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं, वहां ऐसे अधिकारियों की जरूरत है जो उन के जजबात को समझें, उन के हृदय की आवाज को समझें। मैंने आपके सामने एक बहुत ही गम्भीर बात रखी है. मैं आशा करता हूं कि आप इस पर जरूर विचार करेंगे तथा जो आदिवासी भाई-बहन दूसरे प्रदेशों में काम करने जाते हैं उन के सुरक्षा के उपाय होने चाहिएं। मेरा सुझाव है कि इस काम के लिये रांची में एक स्पेशल आफिसर बहाल किया जाय। जो भी ठेकेदार वहां आते हैं, उन से पूछा जाय कि तुम कहां से आये हो, उन के स्टेशन का नाम, उन के भट्टे का नाम और पूरा पता, कितने भाई-बहनों को ले जा रहा है, सब कुछ उन के पास लिखा जाय। यह भी पूछा जाय कि क्या मजदूरी दोगे। अकसर ऐसा होता है कि उन को यह लालच देते हैं कि तुम को प्रति हजार ईंटों की कीमत 25-30 रुपए हजार के हिसाब से देंगे। लेकिन जब वहां जाते हैं तो 10-12 रुपए हजार से ज्यादा नहीं देते, यदि वह बोलता है तो उसे बांध कर पीटा जाता है। हमारे राज्य मंत्री श्री कार्तिक उरांव के रिश्तेदारों के साथ भी जो घटना घटी है, उस को मैं कह नहीं सकता हूं। श्रीमन् बड़ी भयंकर स्थिति है। इस लिए स्पेशल आफिसर रांची में और पलामू में जरूर बहाल किए जायें। जितने श्रमिक लोग सप्लाई हों, बिना उस अधिकारी या एस० डी० ओ० की अनुमति के तथा बिना रजिस्ट्रेशन के न भेजे जायें। यदि श्रमिक जायें तो जितना पैसा तय किया है, उतना पैसा उन को मिला या नहीं मिला, इस की भी पक्की जानकारी मिलनी चाहिए।

[श्री शिव प्रसाद साहु]

मेरा सुझाव है कि हरिजन आदिवासियों के लिए मंत्रालय में एक विशेष सेल खोला जाय, जिस के अन्दर ऐसे अधिकारी रखे जायं जो यह देखें कि कितना रुपया इन पर खर्च होता है, किस तरह से खर्च होता है, उन को ठीक से नौकरियां मिलती हैं या नहीं, उन के हर काम की समुचित ढंग से देख-रेख करें । इन शब्दों के साथ में गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं ।

DR. R. ROTHUAMA (Mizoram): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Demands for Grants for the Ministry of Home Affairs. I come from Mizoram ad I represent Mizoram which is the most trouble-ridden area in the North-Eastern region. The crisis in the North-Eastern area has in fact its origin in Mizoram following the arrest of Mr. Lal Denga by the then Janata Government on the advice of the Brigadier T. Sailo, the present Chief Minister. If you look into the history of Mizoram, you will find that there had been perfect peace and tranquility from August 1977 till May 1979, that is, when the present Ministry came to power. But suddenly there arose a sudden and abrupt outburst of law and order problem and violent incidents only after 1979. Brig. Sailo had advocated strong measures against these violent incidents. He has circulated a Memorandum on how to tackle the Mizo problem by 'Strong Armed measures' to the Prime Minister Central Ministers, the Home Minister and M.Ps. This is precisely the main cause for the abrupt outburst of violent incidents that have been happening from May 1977. The initiative on a peace move by the present Government is most welcomed by all Mizo people except the ruling party. The present Government has been utilising Mizoram Police to create artificial law and order problem in Mizoram Brig. Sailo, the Chief Minister of Mizoram gave thousands of copies of the memorandum to the Prime Minister, Central leaders and Members of Parliament in the first week of July advocating strong measures against the MNF. He has been pursuing very vigorously these strong measures soon after he came to power. Consequently, there has been serious law and order problem and killing of local and non-local people in all walks of life. This is the root cause of the whole crisis in the North-Eastern Region. I know this very well. If the Central Government want to solve this problem in Mizoram particularly, you cannot do this with the present Government there. Brig. Sailo has been proceeding with the idea of sabotaging the present peace talks. You cannot go ahead with the peace initiative successfully keeping the present Ministry in power. I can say that very definitely. The Mizoram Chief Minister, Brig. Sailo has been using Misoram Police Special Forces in creating artificial law and order problem there and I will give you the examples. I am sure, the Minister of Home Affairs who is in direct charge of the Union Territories will give serious consideration to this situation.

I will give you examples where Mizoram special police force is being involved to create law and order problem. On the 24th August, 1979, Mr. Lalnunthara, a driver attached to the Agricultural Department was shot dead at 7.30 in the evening at Chandmary by somebody. The Mizoram Government gave out the information that he had been killed by the MNF. The general public, however, did not believe it. The opposition parties took up the case in the State Assembly after some time and on investigation it was found out that the real culprit for this was one Mr. Rohmingthana, a CID constable under the Chief Minister's own portfolio. But he was kept in the police custody only for about two months and now he is being employed again in the special force to create law and order problem in the name of undergrounds. This I know very well. It does not mean that I support the Mizo undergrounds. But I must tell this House that we have suffered enough and we are fed up

with this suffering and killings every day.

Now, I would tell you the second incident. On 29th March, 1980, Mr. Parliano Sailo was sent by the authorities of Mizoram Government to Lungdai with the idea of killing one Mr. Shanker, a Bengali gentleman, who has married a local girl. Mr. Parliano Sailo, who is an ex-underground and has a certificate of surrender and also carrying a pistol, knocked at the door of Mr. Shanker's house. Mr. Shanker was away to Silchar. His wife was very much apprehensive. She told him that her husband was in the other house and that she would call him. Mrs. Shanker, however, secretly reported the matter to the security force and told them that he had come to kill her husband. The security forces come under the command of Maj. Gupta. They surrounded the house and arrested Mr. Parliana Sailo with a pistol. He told Maj. Gupta that he had no right to arrest him because he had been sent by the authorities of Mizoram Government, and that Mizoram police were coming to take him out. As he had said, the special force of Mizoram under Sub-Inspector C. Lalruata came to take him out in the very same evening. That Sub-Inspector of Sailo who came to take out Mr. Parliana had bitter encounter with Maj. Gupta. Major Gupta said, "Who are you" The Sub-Inspector said, "I am Mizoram Police. Then Major Gupta said, "Why are you carrying two arms? One is a foreign arm. No Indian police can carry foreign arm. Therefore, you must be underground." So, he arrested them and took away their guns and his police batch. Then he took them to the security post. On contact with Mizoram Government or IGP, they were all released. His main mission was to finish Mr. Shankar, a Bengali and two-non-local high school teachers. An incident took place on 20th March, 1980, when 4 BRTF personnel were killed by the Mizoram Police. This was also confessed by Mr. Van Lalzuia, one of the Special Forces of Mizoram Police. You had to take note of what Mr. Mandal said yesterday regarding the present Ministry in Mizoram. He said, "He welcomes the peace move but warned you not to distrust Sailos' Ministry." Now, as long as Sailo Ministry is there in power, your honest effort to bring peace to Mizoram will again misfire. Secondly, Brig. Sailo's Party lost the people's mandate. They have no right to continue in power. You have rightly dissolved the previous Punjab Ministry of Prakash Singh Badal on the ground that he lost in the election for M.P. In the same way as in Punjab, some action should be taken with respect to this present Ministry of Mizoram.

Secondly, since Sailo Government is pursuing a strong arm policy, it would not be possible on your part to solve the Mizoram problem by peaceful means. Therefore, in the interest of bringing peace through the present dialogue, the Sailo Ministry should be dissolved straightway. The Mizoram people, except the present ruling party, are having very high hopes in the initiative of Mrs. Indira Gandhi for starting peace talk with Mr. Laldenga. Therefore, if the Mizoram problem is solved, it will have far-reaching beneficial effects on the problems of the North Eastern Region as a whole. All the problems and crisis in the northern area are directly as a result of the mishandling of Mizoram problems by the previous Janata Party. Mr. Charan Singh and Mr. Laldenga had reached some understanding in November 1977 and they called top four underground leaders to Delhi to approve that understanding before 1977 Christmas but they could not come down to Delhi due to the destructive role played by Brig. Sailo; and for his interference in the underground, the underground became split in 1978. Otherwise, our problems would have been solved.

There had been complete peace in Mizoram from August 1977 to May, 1979. There was not a single violent incident, but suddenly, soon after the present Ministry of Sailo came to power in May 1979, there was an upsurge of violent incidents involving killing of a girl, CRP personnel, teachers both local and non-local. The reason is the strong arms policy of Brig. Sailo which they have been pursuing vigorously with the help of Mizoram Police. When the peace talk was started on 20th March, 1978, even then the underground had not reacted in violent activities. Why? Why should there be a sudden upsurge of violent activities from May 1979? All the opposition leaders in Mizoram including Congress-I have been appraising the Home Minister, the Prime Minister of the violent incidents in Mizoram, but no action has been taken. Mr. Sailo has lost the confidence of the people.

Now Mizo people everywhere in Mizoram are most apprehensive, afraid of Mizoram Police in the villages, in the town also; they are not afraid of army personnel, CRP. I have verified this in the course of my recent visit to many interior places in Mizoram. I am asking the hon. Home Minister and hon. Minister of State whether they are going to do something about the present Ministry which does not have the people's mandate. Are they going to keep that ministry in power at the sacrifice of the peace effort? If they keep him in power. I want to warn that it will misfire again. Brig. Sailo had submitted a memorandum in July this year advocating strong arm policy against MNF. We all believe in Mizoram including many organisations there that if the present Ministry is dissolved, the current law and order problem in Mizoram will end because it is the creation of the Mizoram police. I want that the hon. Minister should come with a definite answer regarding what the Government are going to do with the present P.C. Ministry. In Mizoram they are using the state police forces to create law and order problem and Non-Mizos feel very insecure. With these words I thank you for this opportunity.

SHRI KUSUMA KRISHNA MURTHY (Amalapuram): Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to support the demands of the Home Ministry. One of the most gratifying things that the present government have done soon after resumption of power is to give number one priority for law and order. Soon after the first and brief session of Parliament, they held a conference with all the concerned officials from different states and also another conference with the Chief Ministers and clearly impressed upon all the states the urgent need to restore public confidence in the ability of the administration in maintaining law and order in the country. As a result, it can be clearly seen that the implementation of intensive patrolling had already been started. The speed in investigation to tackle crimes and the promptness in disposal of cases has resulted as has also been pointed out by my hon'ble friend from Meghalaya, Mr. Sangma.

Another important changed aspect which we can clearly see from the government point of view is this; they have clearly realised the twin objectives; tackling the problem of Indian Police Force, that is creating a modern police force: and improving the living conditions of the police. In this respect they have already taken some important steps. They have realised the significance of providing them housing facilities. For that they have earmarked sufficient funds as suggested by the 7th Finance Commission. Even then it is not sufficient that even till today, there are 3,86,193 police personnel who have not been provided with

any accommodation. Unless we provided the need-based requirement of the police it is meaningless to expect honestly in discharging their duties. Probably that is the reason why Indian Police frequently figure in the columns of crime. It is quite disheartening to know about their active involvement in indiscriminate, unlawful activities. Some of the inhuman crimes reported against them may not be correct but all cannot be wrong. In a way the Indian police are losing their credibility and morale. We are proud of our military personnel; they are held in high esteem and dignity in our country and they win the applause and the highest respect of the nation, always in the hour of need whereas the police personnel have started shaking even our basic faith in them. The police who are supposed to be the custodians of law and order are losing public confidence as their morale is very badly affected because of their involvement in inhuman and unexpected crimes.

19 hrs.

The Prime Minister, on visiting Narainpur, made a pertinent observation urging upon the Government to find out the gap between the training and performance of the police personnel and to rectify them. I would, therefore, humbly request the hon. Home Minister to find out the same and rectify these gaps at the earliest. Above all, the police personnel should be clearly made to realise that it is not the mechanical discharge of their duties. What the nation expects from them is a clear sense of their involvement in the dignity of our nation-building.

Here in this House I have been listening to the Members sitting on the other side. They were discussing about atrocities on Harijans. Members from the Opposition argue that atrocities committed on Harijans are more in Congress(I) rule whereas our Party Members prove with facts and figures that the atrocities on Harijans were more during Janata Rule. One say, they are more while the other say, they are less. This conception of more or less in a way implies to me as if certain amount of atrocities on Harijans is allowed in this country. Otherwise how can they translate inhuman acts into percentages? No less a person than Shri Charan Singh, when he was the Minister of Home Affairs specifically said in this House, when I was sitting on the other side, during his rule the atrocities on Harijans stood at 1 per cent. Probably, he was thinking, an other 14 per cent of atrocities were allowed on the Scheduled Castes in this country. Unfortunately, while the founding fathers were incorporating a clause 15 per cent reservation for the Scheduled Castes in the Constitution, had they also permitted 15 per cent atrocities on Harijans in this country, there would not have been any kind of this regular ritual here for shedding a lot of crocodile tears and expressing their vain wrath and anger. The crux of the problem is, why should they be committed on Harijans alone. Are the Harijans not human being? Why should they be discriminated like this?

While intervening in this discussion, the Hon'ble Minister of State Mr. Makwana, made it clear that the atrocities are not sporadic and I agree with him. Therefore, they cannot be dubbed as a party issue. The real case lies in the social set up of society. So, as the Prime Minister has correctly emphasised more than once that even a single case of atrocity against scheduled Castes is shameful for the Nation. So, the whole issue should be looked at from this angle but not as more or less.

Besides this, atrocities—due to social or economic causes should not be trated as ordinary violation of law and order assigned to the States list. The

plea that atrocities being a law and order problem could be tackled by the State Government only and the Central Government would only provide the guidelines may not be tenable under the proper appreciation of Article 46 of our Constitution which enjoins upon the State (means the Nation) the protection of weaker sections and in particular the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Article 46 finds a significant place among the fundamental principles governing our nation. Therefore, the problem of atrocities on Harijans can be, in a way, tackled in the following manner. The hon. Minister while writing to States specifically emphasised the need for immediate special recruitment in the police force "at cutting edge levels" by the Scheduled Castes and the Scheduled tribes and thereby, the discrimination of any type against the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes could be tackled first at the grass-root level. This suggestion should be implemented forthwith for the benefit of the nation.

Apart from this, another important aspect of this issue is that so many forces have been created by the Union Government so far for security purposes. For instance, there are Border Security Force, Industrial Security Force and so on. Therefore, a kind of para-miltary force wth the special objective of preventing atrocities should be created. It can be named as "Social Security Force" and it should be specifically assigned the task of preventing atrocities on Harijans in this country.

The performance of the Home Ministry regarding implementing reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is quite discouraging and unsatisfactory even till today. First of all, I would like to impress upon the Government the urgent need to revise the lists of scheduled castes and sheduled tribes so that their real strength can be found. Twice attempts have been made in this matter and they were, however, not successful so far. This time such an urgent problem should be tackled on a priority basis. Apart from that, from 1951 onwards, various rules and regulations have been issued regarding reservation in their service matters but as on 1-1-1978, the representation of scheduled castes in various services stood as follows; Class I, 4.49 per cent, Class II, 6.93 per cent and Class III, 11.46 per cent. For scheduled tribes, the corresponding figures are 0.84 per cent, 0.87 per cent and 2.01 per cent respectively whereas their percentages were constitutionally fixed at 15 per cent and 7½ per cent for scheduled castes and scheduled tribes, respectively. This is quite disgraceful. The representation in public sector undertakings was not made available by the Bureau of Public Enterprises in spite of the repeated reminders by the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Bureau of Public Enterprises is not responding to these reminders.

The University Grants Commission Act may also be suitably amended to provide for reservation in teachers' posts upto the level of lecturers in all the Universities. In order to clear the heavy backlog in the total strength of each cadre, there should be a definite programme of special recruitment confined to scheduled castes and scheduled tribes. Secondly, there should be a clear provision for punitive measures against erring officials for violating the rules of reservation in article 335.

The Home Minister made it very clear that 'Manusmriti' was the root cause of all the social evils like casteism and untouchability. There are laws like 1955 Acts and 1976 Act. But laws are not enough to conscientise the nation when the problem to be attacked concerns a perpetuating national shame, that is, practice of untouchability. Besides strict enforcement of laws, the development of the social conscience should be earnestly done. Their basic attitude can be changed by a mass movement at the national level.

श्री वीर भद्र सिंह (मंडी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे गृह मंत्रालय की मांगों पर बोलने का मौका दिया । चूंकि समय बहुत कम है, इस लिए मैं संक्षेप में अपने विचार आपके सामने रखूंगा ।

सामान्य स्थिति में भी गृह मंत्रालय एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है, क्योंकि देश की सुरक्षा और शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी उस पर है । परन्तु आज जब देश विकट परिस्थितियों में से गुजर रहा है, देश के कुछ भागों में चिन्ताजनक घटनायें घट रही हैं और देश की सुरक्षा तथा एकता के लिए खतरा पैदा हो रहा है, तो इस मंत्रालय की अहमियत और भी बढ़ जाती है, उसका रोल और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ।

आज देश में जो हालत है, वह हमें जनता पार्टी और लोक दल की सरकारों से विरासत में मिली है । जिन्होंने 27 महीनों तक देश पर शासन किया । उस अवधि में यह मुल्क कमजोर बना, आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटा, शासन-तंत्र कमजोर हुआ, प्रभावहीन हुआ और सारे देश में हर एक क्षेत्र में भ्रष्टाचार बढ़ा । इस दौरान कानून और व्यवस्था खत्म हो गई—कानून और व्यवस्था जैसी कोई चीज रही ही नहो । स्वयं जनता पार्टी के नेताओं ने कई दफा कहा कि हरिजनों, आदिवासियों और कमजोर वर्गों पर जितने अत्याचार जनता पार्टी के शासन में हुए, उतने पहले कभी नही हुए । यह बात कई दफा इस सदन में और बाहर कही गई । गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में भी लिखा है कि 1979 में जितने साम्प्रदायिक दंगे हुए, उतने पहले कभी नही हुए । इस रिपोर्ट में लिखा है कि 1979 में 304 साम्प्रदायिक दंगे हुए, जिनमें 261 व्यक्ति मरे और 2379 जख्मी हुए ? इससे साफ जाहिर होता है कि जब जनता पार्टी की सरकार हटी, तो इस मुल्क में क्या परिस्थिति थी और मौजूदा सरकार को क्या चीज विरासत में मिली । इस सरकार को बने कुछ महीने हुए हैं । मैं जानता हूं कि आज भी कुछ परिस्थिति खराब है । कानून और व्यवस्था की परिस्थिति जहां पहले के मुकाबले में बेहतर है वहां उस में और सुधार करने की आवश्यकता अभी है । मगर जो इन लोगों ने तीन सालों में मुतातर देश की हालत को खराब किया है उस के लिए हम से यह उम्मीद करें कि हम एकदम जादू की छड़ी घुमा कर उस को ठीक कर दें, यह मुमकिन नही है । उन्होंने इतना काम बिगाड़ा है कि उस बिगडे हुए काम को ठीक करने में अभी कुछ समय लगेगा । मुझे इस बात की खुशी है कि चाहे वह कानून और व्यवस्था का प्रश्न है, चाहे लोगों की आर्थिक दशा को सुधारने का प्रश्न है, इस तरफ हम आगे बढ़े हैं । इस में कुछ सुधार हुआ है । मगर अभी इस में और काम करने की आवश्यकता है ।

अभी कई माननीय सदस्यों ने आसाम के बारे में यहां पर जिक्र किया । आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विशेषकर मणिपुर, त्रिपुरा और आसाम में जो स्थिति उत्पन्न हो गई है उस से सारा देश चिन्तित है । आसाम में पिछले कई महीनों से विदेशी नागरिकों के प्रश्न को ले कर आन्दोलन चल रहा है । इस में कोई शक नही कि चाहे वह आसाम के लोग हैं, मणिपुर के लोग हैं, त्रिपुरा के लोग हैं या सारे उत्तर पूर्वी अंचल के लोग हैं उन की कुछ जायज मांगे हैं, उन मांगों की तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए । उन की एक शिकायत यह है कि वहां पर विकास के काम कम हुए, वहा यातायात के साधन कम है, रोजगार के साधन कम है । इन चीजो को मुहैया करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए । इस के साथ साथ वहां पर जो एक प्रश्न है कि बंगला देश से बहुत से लोग आसाम के क्षेत्र मे आए और आ कर वहां पर बस गए, इस के बारे में सरकार को यह देखना चाहिए कि जो बगला देश और आसाम की सीमा है उस पर सुरक्षा का इंतजाम कड़ा करें ताकि बंगला देश से लोग आसाम में न घुसने पायें ।

जहा तक आसाम का प्रश्न है इस में कोई दो राय नहीं हैं कि यह एक राजनैतिक प्रश्न है और इस का हल भी सर्वसम्मत राजनैतिक हल के आधार पर हो सकता है । इस हल को ढूंढने मे न केवल सरकार को काम करना है बल्कि हमारे जो विरोधी पक्ष के सस्दय और नेता हैं वह भी इस में महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते है । मगर आज हम देखते क्या हैं कि जो हमारे विपक्ष के सदस्य या नेता है वे बजाय इस के कि उस समस्या के समाधान के लिए सरकार का हाथ बटाएं, बजाय इस के कि जो सारे उत्तर पूर्वी अंचल में आग फैली है उसको बुझाने के लिए कुछ काम करें, वे उलटे, वहां उस आग में घी डालने का कार्य कर रहे हैं । वे उस आन्दोलन को और उकसाने और बढ़ाने का काम कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि यह ठीक नही है । वहां का जो प्रश्न है, सिर्फ एक ही ढंग से उस का समाधान हो सकता है । बातचीत के जरिए वहां की समस्या का समाधान ढूंढा जाय । वह बातचीत कैसे हो ? बातचीत के लिए अनुकूल वातावरण पैदा होना चाहिए । इसलिए इस से पहले कि वहां पर कोई बातचीत हो वहां के जो आन्दोलनकारी हैं चाहे वे वहां के छात्र हैं या गण-संग्राम परिषद् के लोग है, उनको चाहिए कि आन्दोलन को वापिस लें और फिर बिना

शर्तें वहां पर सरकार के साथ बातचीत करने के लिए सामने आएं । ऐसा शांत और अनुकूल वातावरण वहां पैदा करें जिस से कि इस समस्या के समाधान के लिए बातचीत हो सके । अभी उन्होंने 15 दिन के लिए आन्दोलन को आंशिक रूप से स्थगित करने की घोषणा की है । यह एक सही कदम है । मैं इस का स्वागत करता हूं । मगर मैं यह चाहूंगा कि बजाय इस के कि आंशिक रूप से वे इस आन्दोलन को स्थगित करें, पूर्ण रूप से इस को स्थगित कर के शांत और अनुकूल वातावरण इस के लिए पैदा करें मैं सरकार से भी प्रार्थना करूंगा कि जहां हम यह देखते हैं कि आसाम में आन्दोलन हो रहा है वहां कुछ विदेशी ताकतें भी हैं, अन्दर के लोग भी हैं जो हिन्दुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, हिन्दुस्तान के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं और आसाम के अंदर लोगों का आन्दोलन हो रहा है उस का नाजायज फायदा उठा कर सारे के सारे पूर्वांचल को मिलाकर एक स्वतंत्र देश की रचना करने की साजिश कर रहे हैं । इस का भी हमें मुकाबिला करना पड़ेगा ।

जहां तक पथकतावाद का सवाल है जो हमें मणिपुर या आसाम में नजर आता है वह महज उस इलाके तक ही महदूद नहीं है, उस का असर कई दूसरे क्षेत्रों तक भी पहुंच रहा है । अभी आप ने देखा होगा हाल ही में पंजाब के कुछ लोगों ने तथाकथित खालिस्तान सरकार के बनाने की घोषणा की । मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि इस बारे में क्या किया गया ? यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हम हंसी में टाल दें कि किसी मनचले आदमी ने कोई घोषणा कर दी जिसको नजरन्दाज कर दिया जाए । हिन्दुस्तान की सवायल पर कोई तथाकथित स्वतन्त्र सरकार की घोषणा करता है--यह कोई हंसी मजाक का सवाल नही है, यह देश-द्रोही है और इसके खिलाफ वही कार्यवाही करनी चाहिए जोकि एक देश-द्रोही के साथ की जाती है । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाया है ?

अभी हाल ही में काश्मीर के मुख्य मंत्री, शेख अब्दुल्ला ने एक बयान दिया जिसको पढ़कर बड़ा अफसोस हुआ । मैं उनको बड़ा देशभक्त मानता था । सेक्यूलेरिज्म के प्रति उनका कमिटमेन्ट भी रहा है, वे एक नेशनलिस्ट रहे हैं लेकिन जब मैंने उनका बयान पढ़ा--जिसका अभी तक कोई खण्डन नहीं आया है--तो कम से कम मुझे उससे बड़ा दुःख हुआ । उनका यह सारा बयान अखबारों में छपा था । उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है, वह मैं 15 तारीख के "पैट्रियाट" से उद्धृत कर रहा हूं जिसमें उन्होंने कहा है :

"In a highly emotional outburst against his "traitor" detractors, Jammu and Kashmir Chief Minister, Sheikh Abdullah, asserted here yesterday that "we will never let other dictate terms to us."

Shaheed Bazar on the occasion of Martyrs' Day composed mostly of youth, the Sheikh said: "We will not allow anybody to become arbiters of our destiny, be it Gen. Zia-ul-Haq or Mrs. Gandhi. The people of Kashmir will not let others play with their destiny whether it is India, Pakistan or the U.N."

इस तरह का बयान शेख साहब ने दिया और उनकी तरफ से कोई खण्डन नहीं आया है । मैं समझता हूं यह बड़ा सीरियस मामला है । इस बयान को पढकर ऐसा लगता जैसे कोई हिन्दुस्तान के किसी राज्य का मुख्य मंत्री नहीं, बल्कि किसी स्वतन्त्र देश का प्रधान मंत्री बोल रहा हो । इस बयान से ऐसा लगता है जैसे कश्मीर हिन्दुस्तान का कोई राज्य नहीं है बल्कि कोई स्वतन्त्र देश है । सबसे बुरी बात यह है कि उन्होंने अपने बयान में इंडिया और पाकिस्तान को इक्वेट किया, श्रीमती इन्दिरा गांधी और जियाउल हक को इक्वेट किया । मैं कहता हूं यह ट्रीज्न नही है तो क्या है ? मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या आपने इस बारे में शेख साहब से स्पष्टीकरण मांगा है या नहीं ? अगर नहीं मांगा है तो आपको स्पष्टीकरण मांगना चाहिए कि उन्होंने किस प्रसंग में इस किस्म का बयान दिया जोकि भारत की एकता के खिलाफ है, भारत की अखण्डता के खिलाफ है और भारत की सुरक्षा के खिलाफ है । मैं चाहूंगा कि आप उनसे स्पष्टीकरण मांगे ताकि आइंदा किसी भी मुख्य मंत्री को इस किस्म का बयान देने की हिम्मत न हो जिस से भारत की सुरक्षा एवं एकता को धक्का न लगे ।

आखिर में मैं दो बातें और कहना चाहता हूं जहां तक हरिजन तथा आदिवासियों का सम्बन्ध है, उनके प्रति गृह मंत्रालय की सीधी सांविधानिक जिम्मेदारी है । अभी कई माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में जिक्र किया कि आज जगह जगह गांवों में झगड़े हो रहे हैं । यदि आप इसका विश्लेषण करें तो आप पायेंगे अधिकांश झगड़े जमीन से शुरू होते हैं । इस बात को मानना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान के हर राज्य में पिछले कई वर्षों में बड़ी भारी तादाद में हरिजन आदिवासियों को उनकी भूमि से वंचित किया गया है । कई जगह ऐसे कानून बने हैं कि हरिजन आदिवासियों की जमीनें ट्रांसफर नहीं हो सकती हैं लेकिन वह कानून काफी नहीं है । कानून बनाने से पहले ही बहुत सी जमीनें ट्रांसफर हो चुकी थीं और आज कानून बनने के बाद भी ट्रांसफर हो रही हैं । इस बात को हमें रोकना होगा । जिन

लोगों की जमीनें छिन गई हैं उनके लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा कि उनको वह जमीनें वापिस मिलें ताकि सही रूप में हमारे गांवों में शांति स्थापित हो सके और इन लोगों को सामाजिक तथा आर्थिक न्याय मिले ।

इन शब्दों के साथ मैं गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं । मैं जानता हूं आज की कठिन परिस्थिति में काम चलाना आसान नहीं है लेकिन मुझे खुशी है कि आज ज्ञानी जैल सिंह जैसे तजुर्बेकार व्यक्ति हमारे गृह मंत्री हैं जो कि मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं, वे अपने तजुर्बे के आधार पर समस्याओं को हल कर सकते हैं । उनके राज्य मंत्री श्री मकवाना साहब और श्री वेंकटसुबैया भी सुलझे हुए व्यक्ति हैं और मुझे उम्मीद है उनके परस्पर सहयोग से इन समस्याओं को सुलझाने में सफलता मिलेगी ।

*SHRI BAJU BAN RIYAN (Tripura East): Hon. Deputy Speaker, Sir, I am speaking in Bengali. Here we are discussing Demand Nos. 47 to 57 under the Ministry of Home Affairs on the subject of Police, census, other expenditure of the Ministry of Howe Affairs, etc. I will speak something only on the allocations made for the Scheduled Castes and Tribes, the tribals and other backward communities, since my time is very short.

Sir, I feel that the allocations made for the tribals and the Scheduled Castes/tribes is very meagre. As a result of such meagre allocations over the years, there has not been very marked improvement in the standard of living of the tribals, the Scheduled Tribes and other backward communities for the last 33 years. I will draw the attention of the House to Demand No. 48 wherein Rs. 9 lakhs have been allocated for entertainment and hospital expenes in Prime Minister's office. But in Demand No. 57, major head 288, the amount allocated for post-matric scholarships to inter State Scheduled Castes; Scheduled Tribes and economically backward class students is only Rs. 2,39,000. Therefore we see that the amount allocated for the entertainment of people in the Prime Minister's office is several times more than the allocation for such scholarships to the tribal, Scheduled Castes/Tribes and other backward community/students all over the country. If we work out the per capita allocation for scholarships to these students we will find that the amount is even less than the price of a slipper which many hon. Members are wearing on their feet. In some States the rate of scholarship is Rs. 40 and in some States is Rs. 50 or 60. This is the stipend that the poor students in India are getting from the Government. As a result of this attitude, the students from poor classes who have received some education in the last 33 years, belong to such families only where their parent, could provide them with some education after undergoing immense hardships and making great sacrifices. Otherwise the poor students cannot get any education. Government help is pitifully meagre. Their level of education remains as before. I don't believe that the present Government is sincere about raising the economic standards of these backward classes and communities and the tribals. That is why I do not support them.

Sir, about the law and order problem in Tripura, many hon. Members of this House have expressed their views. Members of the opposition parties have tried to place a factual and true picture of the occurrences there. For example hon. Member Shri Kishore Singh Deo visited Tripura a few days back as a member of a delegation, and he has placed a true picture here about what has happened in Tripura. But I regret to say that many members of the ruling party have placed a distorted and twisted version before this House in the many discussions that has taken place in the form of calling attention motion or discussion on the North-Eastern Staies etc. They have done that only to encourage the miscreants and mischief mongers in Tripura. Their versions have no relation to the truth and the factual position. Many members have said that the CPI (M) has instigated these incidents,

*The original speech was delivered in Bengali.

[Shri Baju Ban Riyan]

some have said that the Bengalis have instigated these incidents and some others have said that the Tribals have instigated these incidents. I don't accept any of these contentions. Today we are running the Government there. But our party the CPI(M) have existed in that State for the last 30 years or more. Our party is functioning there since the days Tripura was a princely State and monarchy was prevailing there. Now we have formed a left front Government along with the R.S.P., the Forward Bloc etc. In the last assembly elections, out of 60 seats we have won 56 seats the remaining 4 seats have gone to the Yuva Samiti. The Congress party that have ruled the State for long 30 years have failed to win a single seat. Not only that, their condition is such that they cannot even hold a meeting in Tripura democratically. The people there say that these thieves have come to hold a meeting we will not attend them. They have burgled for long 30 years we will not permit them any more. In this situation they took to other methods. What was that? The Bengalis who supported, who the Congress agitated "We are Bengalis" and the tribal supporters formed the 'Yuva Samiti'. In this way two extremist organisations were formed. The tribal Yuva Samiti raised the slogan "All hill tribes of the world unit". The 'We are Bengalis' organisation raised the slogan "All Bengalis of the world unite." In the midst of this slogan-mongering and tense atmosphere our left front Government is trying to proceed with various developmental programmes. Already we have provided employment to many tribals. We have granted pension to many poor Bengalis. We have increased the emoluments of the employees and workers which was payable to them under the Constitution. Corruption was curtailed to a great extent and there was improvement in the law and order situation.

Sir, under the Tripura Land Reforms and Land Revenue Acts, written permission of appropriate authority was necessary for the transfer of land by tribals to non-tribals. Ignoring this provision of Law much land was transferred to non-tribals illegally during the Congress rule in Tripura. From 1969 onwards it was decided to restore all illegally transferred land to the tribals. The left front Government made provision for payment of compensation to non-tribals for restoration of such land to the tribals. In our regime no such illegal transfer of land has taken place.

One of the main causes for the misunderstanding between the tribals and non-tribals. Only a handful of trouble-. One gratifying thing is that in the recent massacre in Tripura there was no mass involvement of Tribals and non-tribals. Only a handful of trouble-makers from both sides are behind all this. The democratic unity between the two sections still exists. As I was saying, Sir, there was all-round improvement in Tripura and the left front Government was functioning very smoothly and effectively. In this situation some miscreants and trouble-makers started conspiring and aggravated the situation. If you go to Tripura, any person will tell you who is behind all these disturbances. We have heard the speech of the hon. Minister and the answers given to many questions. The hon. Minister of State who is sitting here has said that about 500 people have lost their lives in the disturbances in Tripura and a few hundreds have been wounded, and many houses have been burnt. But some members of the ruling party have stated that thousands of people have been killed, some said it was 3000, some said it was 5000 and so on. I will expect that such irresponsible statements would not be made in the House, and the people of India should not be misled in this way.

Sir, our left front Government is trying to raise the standard of living of the tribals through a series of new legislations. Our Government has given the tribal language of Tripura the status of a State language. I would like to know whether any other

State Government has done that! Will the Congress Governments in any State be able to do that? In the last 30 years has any of the 500 and odd colloquial languages been given recognition? It has not been done anywhere also. I fail to understand how the economic standards of the tribals and other backward communities can be improved with this attitude of the Government.

I will hope that the Central Government will provide the relief that is nessessary for the people in Tripura after the disturbances, and for reconstruction of the State. The relief provided so far by the Centre is indeed praiseworthy and I am thankful for that. I hope the Centre will help us in tracing and punishing the miscreants who are responsible for these disturbances. I will request you to enquire into the activities indulged in by those people in Tripura who call themselves Congressmen. Are they trying to defuse the situation and bring about peace or are they trying to fan the fire! So far as I know the members of the Congress party in that area are only trying to aggravate the situation. I can name a few persons in this connection. Have you heard of *** This gentleman has given statements at various places.

SHRI MANORANJAN BHAKTA (Andaman and Nicobar Islands): He has mentioned the name of a person. He is not present in the House; he cannot defend himself.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will go through the proceedings and see if anything has been mentioned.

SHRI BAJU BAN RIYAN: Mr. Deputy-Speaker, Sir, since you object I withdraw the name that I have mentioned. Even then I will request them to make enquiries what their party members are doing there.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Very kind of you.

SHRI BAJU BAN RIYAN: I will request you only to enquire what your party members are doing there. It they are aggravating the law and order situation, I will hope the Central Government will help the State Government in punishing them. Here I conclude Sir, thank you.

श्री अरविन्द नेताम (काकेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

राज्य मंत्री श्री वेंकेटसुब्बया ने अपने विभाग की जो रिपोर्ट पेश की है, उस में उन्होंने शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्स की नौकरियों के सम्बन्ध में रिपोर्ट में कुछ फीगर्स दिये है। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहूंगा कि जो पेज 16 में शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स की प्रथम वर्ग की, क्लास 1 की पोस्टों की केटेगिरी है, उस में शेडयूल्ट कास्ट की 2.03 और शेडयूल्ट ट्राइब्स 0.47 प्रतिशत नौकरियां ही है इस के अलावा क्लास 2 में कम है और नीचे की केटेगिरिज में भी कम है हालांकि मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस में वृद्धि हो परन्तु मैं एक बात आपको माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री श्री मकवाना साहब की जानकारी में शायद यह चीज हो कि यह बात सही है कि सरकार की तरफ से प्रोमोशन और एपाइटमेट में रिजर्वेशन है और उसमें वह काफी मदद कर रही है पर मैं मिनिस्टर साहब को और खासतौर पर मकवाना साहब को यह बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्स के रिजर्वेशन के खिलाफ करीब 23 केसेज पेन्डिंग है और इस देश की हाई कोर्टो में करीब 150 केसेज पेन्डिंग है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आदिवासी और हरिजन शासकीय कर्मचारी है, वे अपने विभाग में लड़ें या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्टो मे लड़ें इस सम्बन्ध में गृह मंत्रालय या गृह मंत्री जी क्या कदम उठाने के लिए सोच रहे है. यह मैं जानना चाहूंगा जब गृह मंत्री जी बहस का जवाब दें।

इस के अलावा इस सदन में काफी चर्चा हुई है कि खासकर हरिजन और आदिवासयों के अत्याचारों के सम्बन्ध में एट्रोसिटीज के सम्बन्ध में मै ज्यादा कुछ न कह कर गृह मंत्री जी का ध्यान जो रिपोर्ट है, कमिश्नर की 25 वी रिपोर्ट है और उस में जो 9वां चेप्टर है कमिश्नर की रिपोर्ट का, उस में कुछ सुझाव दिये गये है और करीब करीब 11 सुझाव दिये है. जो समय

***Expunged as ordered by the Chair.

के अभाव के कारण मैं पढ़ना नही चाहता। बड़े अच्छे सुझाव उसमें दिये गये है और मैं यह चाहूंगा कि मंत्री जी जो सुझाव दिये गये है उन पर यदि अमल करें तो यह जो समस्या अत्याचारों की है, वह बहुत कुछ हल हो सकती है। यह जो होम मिनिस्ट्री की मैन रिपोर्ट है, उस में पेज 3 पर यह बात कही गई है :

"The Constitution has provided various safeguards for the protection and promotion of the interests of the Scheduled Tribes. Till the end of the 4th Plan, the pace of development in the tribal areas was rather slow."

यह गृह मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना तक प्रगति बहुत स्लो रही है। इस के बाद पांचवी प्लान की योजना सारे आदिवासी क्षेत्र के लिए लागू की गयी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा है —

"Working Group for Monitoring and Evaluation of Tribal Development of Backward Classes was constituted by the Ministry. The Working Group submitted its report in July, 1979, and the State Governments have been requested to adopt the form as suggested by the Group for implementation."

तो मैं अमर में जानना चाहता हूं कि इस वर्किंग ग्रुप ने क्या निष्कर्ष निकाले, उन पर क्या निर्णय लिया गया? यह कम से कम सदन में बताना चाहिए, ताकि सदन को भी मालूम हो कि सब प्लान के बारे में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में कितनी प्रगति हुई? इस सम्बन्ध में मंत्री जी बताएं।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इसी सदन में मैंने खास तौर से इसके बारे में कहा था कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में आपने पैसे की व्यवस्था की, सब कुछ किया लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अभाव में वह प्रगति नही हो पा रही है जो कि होनी चाहिए थी। वर्किंग ग्रुप ने जो रिपोर्ट सबमिट की है। This Working Group submitted its report in October, 1979.

इस रिपोर्ट के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि यह जो सब प्लान के बारे में प्रगति हुई है उस के बारे में वर्किंग ग्रुप ने क्या निष्कर्ष निकाले है। माननीय मंत्री जी जब जवाब दे तो इसके बारे में बताएं। क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, पूरी पांचवी पंचवर्षीय योजना खत्म हो गयी परन्तु एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अभाव में जितनी योजनाएं सफल होनी चाहिए थी वे नहीं हो पा रही है।

मै एक बात कहना चाहूंगा कि राज्य सरकारों का यह एटीच्युड रहा है कि छोटे छोटे कारपोरेशन या बड़े बड़े कारपोरेशन हो सभी के लिए आई० ए० एस० अफसर नियुक्त किये जाते है। चाहे 10 करोड का कारपोरेशन हो या 10 लाख का कारपोरेशन हो। लेकिन ट्राइबल डवलपमेंट कारपोरेशन के काम के लिए राज्य सरकारों के पास आई०ए०एस० अफसर नही है। दस लाख के कारपोरेशन के लिए भी जब राज्य सरकार आई० ए० एस० अफसर की व्यवस्था कर रही है तो जो नये नये आई०ए०एस० अफसर हों उन्हे ट्राइबल एरियाज में भी लगाया जाना चाहिए ताकि सब प्लान का काम ठीक प्रकार से चल सके और ट्राइबल एरियाज का ठीक ढंग से विकास हो सके।

आपने रिपोर्ट में एक बात कही है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना मे कुल 590 करोड़ रुपये का प्रावधान था। छठी योजना मे ? हजार करोड रुपया खर्च करने की योजना थी। इसी ढंग से आपने शेडयूल्ड कास्टस के बारे मे सौ करोड का प्रावधान रखा है। मुझे अभी भी शका है कि आपने क्या गाइड लाइस दी है, क्या आपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर दिया है, इस सम्बन्ध में मै जानना चाहूंगा कृपया गृह मत्री महोदय बताने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, 23 जून, को एक क्वेश्चन के जवाब में कृषि मंत्री जी ने यह कहा है कि प्रपोजल फोर नेशनल फोरेस्ट पालिसी रिव्यू कर रहे है। यह कृषि मंत्री ने स्वीकार किया है। इसके बारे मे गृह मत्री जी का पालिसी मेकिंग में क्या रोल है, यह बताएं। 1894 में जो पालिसी बनी थी, जिसका की 1952 मे रिव्यू किया गया और उसमें फर्क हो गया है। यह जो रिपोर्ट आफ दा शिड्युल्ड रियाज एण्ड शेडयल्ड ट्राइबस कमीशन की है, जो कि ढेबर कमीशन की रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है, इसमें है—

"Thus the tribal who formerly regarded himself as the lord of the forests, was through a deliberate process turned into a subject and placed under the Forest Department. Tribal villages were no longer an essential part of the forests but were there merely on sufferance. The traditional rights of the tribals were no longer recognised as rights. In 1894 they became 'rights and privileges' and in 1952

they became 'rights and concessions'. Now they are being regarded as 'concessions'".

यह इम्पैक्ट है। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आप नेशनल पालिसी जो बना रहे है उस में इनका रोल क्या है यह मैं जानना चाहता हूं। मकवाना साहब ने बड़े ही सुन्दर ढंग से कहा है कि हम ने राज्यों को गाइड लाइंज दी है। तीस साल की आजादी के बाद भी केन्द्रीय सरकार राज्यों को गाइड लाइंज दे रही है लेकिन उन पर अमल नहीं हो रहा है। क्या आप कोई कदम उठाएगें क्योंकि काम ठीक इसके विपरीत हो रहा है राज्यों में ? मैं चाहता हूं कि इस पालिसी के सम्बन्ध में आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लें और इस में थोड़ा सा सुधार लाने की कृपा करें।

मेरे साथी श्री राम प्यारे पनिका का एक सुझाव है बहुत सी जातियां आज भी छूट गई है जो शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्ज में नहीं जुड़ी है। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक जाति है जो महाराष्ट्र में महार के नाम से पुकारी जाती है एम०पी० में उसको माहरा कहा जाता है। प्रोनंसिएशन का ही फर्क है। महाराष्ट्र में वह शैडयूल्ड कास्ट में आती है और उत्तर प्रदेश में भी शेडयूल्ड कास्ट में उसकी गणना होती है लेकिन मध्य प्रदेश के बोर्डर पर वह शैडयूल्ड ट्राइब बन जाती है। महाराष्ट्र में शैडयूल्ड कास्ट और पूर्वी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में उसको शैडयूल्ड कास्ट में सम्मिलित नहीं किया गया है उनकी जो वर्या-उपजातियां है वह भी उस में शामिल नहीं की गई है। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर इस पर रीथिंकिंग कर के संविधान में संशोधन करने पर विचार होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, सारा सदन मानेगा और सारा देश तो मानता ही है कि आज देश में कानून और व्यवस्था की जो हालत है और जितनी वह खराब है, उतनी खराब इससे पहले कभी नहीं थी। ऐसी हालत जनता सरकार में भी नहीं थी। मैं उन आदमियों में से हूं जो यह मानते हैं कि जनता सरकार के जमाने में कुछ चीजों की मान्यता घटी थी लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से आज क्राइम्ज बढ़ रहे है उस तरह की हालत जनता सरकार के वक्त भी नहीं थी।

यह ठीक है कि क्राइम्ज जहां तहां हुआ करते थे और अखबारों में भी आया करते थे। लेकिन आज एक नया फिनोमिनन देखने में आ रहा और वह यह है कि बहुत ज्यादा रक्षक ही भक्षक हो रहा है पुलिस हमारी सुरक्षा के लिये बनी है लेकिन आज हालत यह है कि वही भक्षक हो रही है, सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

कानून व्यवस्था की हालत क्यों गिरती जा रही है इसकी तह में जाने की जरूरत है। मैं इसके दो तीन मुख्य कारण बताना चाहता हूं और भी इसके कारण हो सकते है लेकिन दो तीन जो मुख्य कारण मेरी समझ में आए है उनको मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं।

पहला कारण तो यह है कि देश की जनता और शासन के बीच में विश्वसनीयता में कमी आई है। जिस दिन वर्तमान शासक दल सत्ता में आया उसी दिन से इसने खुद-ब-खुद कहना शुरु कर दिया कि हम बदले की भावना से काम करना नहीं चाहते है। लेकिन आप देखें कि सत्ता में आते ही इन्होंने लैफ्टिनेंट गवर्नर को बदला, पुलिस कमिश्नर को बदला, एटर्नी जनरल को बदला, सालिसिटर जनरल को बदला। ये सब बातें यह कहने के बावजूद हुई कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, सी० बी० आई० के एक डी० आई० जी० ** जो हमारे क्षेत्र से आते हैं। उन्होंने गुनाह इतना ही किया था कि इन्दिरा जी को जेल ले गये थे और मारुति के मामले को इन्वेस्टीगेट कर रहे थे। जो इन्स्पेक्टर या डी० एस० पी० पुलिस अनुशासन के तहत डी० आई० जी० के सामने आ नही सकते, वह दो-दो गाड़ियों में आर्म्ड फोर्स लेकर सुबह उनके पास पहुंचे। अगर विरोधी दल के सदस्य नहीं होते तो शायद** इस देश में न रहे होते, दुनिया में न रहे होते। यह स्थिति इनकी है कि किस तरह से बदले की भावना से काम कर रहे हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Yadav, you mentioned the name of a person who is not a Member of this House. You should not mention the name of the person who cannot defend himself.

SHRI R. P. YADAV: I can say D.I.G. That is all. I am not alledging anything. So, there is no question of his defending himself.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is better you avoid this.

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : आप देखें, अभी चन्द दिन हुए इस देश के माने हुये हृदय रोग के विशेषज्ञ **, उनको बिना कहे-सुने इस लिए

**Expunged as ordered by the chair.

तबादला कर दिया गया क्योंकि सन् 1977 में इन्होंने कहा था कि श्री जगजीवन राम को तुम बीमार करार दे दो । इन्होंने कहा कि यह मैडिकल एथिक्स के खिलाफ है, मैं नहीं करता । उनका ऐसी जगह पर इन्होंने तबादला कर दिया है कि वह वहां जा नहीं सकते, उनको नौकरी से बाहर जाना पड़ेगा । यह इनकी मंशा है और बदले की भावना से काम करने का तरीका । आप अन्दाजा कर सकते हैं कि किस तरह से काम करने की इनकी भावना है ।

आप जानते हैं, जैसा हमने कहा कि यहां पुलिस कमिश्नर भिंडर साहब को बहाली हुई है । ये 208 पुलिस अफसरों को सुपरसीड करके ऊपर गये हुए हैं आप उन पुलिस अफसरों की भावना का ख्याल कीजिए, वे कहते हैं कि ये कल तक हमसे आर्डर लेते रहे, हमारे निर्देश पर चलते रहे, आज हम इनके निर्देश पर कैसे चलें । यही कारण है कि दिल्ली में कानून और व्यवस्था जो इतनी अच्छी थी देश में उदाहरण था, आज रोज-ब-रोज इसलिए गिर रही है कि पुलिस आफिसर्स, पुलिस फोर्स डिमोरलाइज्ड हो गई है । इनके पुलिस कमिश्नर आर्डर पर काम नहीं हो पा रहा है । इसीलिए रात दिन चोरियां और डकैतियां बढ़ रही हैं ।

गृह मंत्री तो यहां पर हैं नहीं, लेकिन मैं एलेज करता हूं, कि क्या यह बात सही है कि दिल्ली में ऐसे एस० एच० ओज०, को पुलिस फोर्स में लगाया गया है जो बांगडू हैं जिनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी नहीं है, उन लोगों को यहां बहाल किया गया है। गृह मंत्री के क्षेत्र से यहां पर पुलिस वालों की भर्ती को जा रही है, और भिंडर साहब की पत्नी जो यहां सदस्य हैं, उनके क्षेत्र से लोगों को लाया जा रहा है जिनकी कोई एडिमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं हैं । एस० एच० ओज० में ऐसे लोग हैं जो बहाल नहीं हो सकते, पुलिस में आम तौर पर ऐसे लोगों को बहाल किया गया गया है । आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि उनसे कानून व्यवस्था की हालत क्या ठीक होगी ?

देश में 9 प्रान्तों में चुनाव हुए । मैं ऐसे प्रान्त से आता हूं जहां इलैक्शन कमिश्नर के निर्देशों के बावजूद मास स्केल पर डी० एम० से एस० डी० ओ० तक और एस० पी० से लेकर दारोगा तक ट्रांसफर किये गये यही कारण है कि उन लोगों ने इनके मन के मुताबिक छापे मारे और इनको जिताया । आज ये चाहते हैं कि उन पर शासन करें। वे कहते हैं कि हम तो तुमको शासन में लाये हैं, तुम कौन होते हो, हम पर शासन करने वाले — यही कारण है कि देश में आज यह हालत हो रही है । न कानून है, न कायदा है । यह बहुत खतरनाक बात है, इस ओर सरकार को ध्यान विशेष तौर पर देना चाहिये । यहां के पुलिस आफिसर्स और सरकारी अधिकारी अगर यह चाहेंगे कि जब हम शासन में आपको लाये हैं, तो जो हम चाहेंगे, वही होगा । यह एक चेतावनी है कि सरकार देखे कि कोई इस तरह का काम न हो जिससे जनतंत्र पर खतरा आ जाये ।

बिहार में उन्होंने कई प्रकार की अनियमितायें की, अन्याय किये । आपको जान कर हैरत होगी कि सात दिन तक 81 जगहों के रिजल्ट्स रोक रखे गए । अगर ऐसा न किया गया होता, तो बिहार में इनकी मैजोरिटी नहीं हो सकती थी ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): Sir, the matter had been raised and the Law Minister has already replied on this matter.

SHRI R. P. YADAV: Even then I have got every right to raise it here again.

PROF. N. G. RANGA: Law Minister has replied to all these charges.

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अगर ईमानदारी से सब काम होता, तो बिहार में इनकी सरकार नहीं बनती । जितनी जगहों को जीतने से इनकी सरकार बन सकती थी, वहां रीपोल करवाया गया और जबर्दस्ती बैलट-पेपर्स पर स्टैंपिंग की गई । इस प्रकार मैजोरिटी प्राप्त करके इनकी सरकार बनी है ।

इस देश में कानून और व्यवस्था की हालत बिगड़ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण हम माननीय गृह मंत्री जी को मानते है । इस मुल्क का शासन गृह मंत्री करते हैं । यदि गृह मंत्री चाहें, तो देश में कानून और व्यवस्था की हालत सुधर सकती है । लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जिस दिन मंत्री महोदय बड़े अफसरों की मीटिंग करते है, उसी रात कहीं न कहीं डाका पड़ता है । इससे आप उनकी चुस्ती का अन्दाजा लगा सकते है । इतने बड़े मुल्क के लिए बड़ी चुस्ती और काबलियत की जरूरत है, लेकिन माननीय गृह मंत्री उसके लायक नहीं हो पा रहे हैं । इसलिए उनको स्वेच्छा से त्यागपत्र देना चाहिये । उन्हें इस पद को सुशोभित करने का कोई अधिकार नहीं है ।

आज उत्तर-पूर्वी भारत में जो हालत हो रही है, उसको देखकर कोई भी कह सकता है कि देश का वह हिस्सा जल रहा है । जब तक सब लोग मिल कर इस समस्या के बारे में विचार नहीं करेंगे, तब तक उसका समाधान नहीं होगा । यह सरकार वहां पर रिप्रेशन बन्द करे और सब लोगों को टेबल पर बिठा कर इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करे ।

मुझे तो ऐसा लगता है कि यह सरकार जान-बूझ कर इस देश में इस तरह के हालात पैदा करना चाहती है, ताकि लोग कहें कि बिना इमर्जेन्सी के इस मुल्क में कोई दूसरा रास्ता नहीं है । यह सरकार जानबूझ कर 1974 जैसी स्थिति की तरफ जा रही है । इन्दिरा कांग्रेस के कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि वर्तमान स्थिति में इमर्जेंसी के सिवाय और कोई इलाज नहीं है । मेरा चार्ज है कि ये लोग जान-बूझ कर देश में इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं । ये चाहते हैं कि इस तरह के हालात बने रहें, वे दिन-प्रति-दिन बिगड़ते जायें और 1974 की हालत फिर से हो, ताकि ये मुल्क में फिर से इमर्जेन्सी लाग् कर सकें और लोगों के मुंह पर ताला लगा सकें ।

श्री कुंवर राम (नवादा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे यादव जी ने कई ऐसी बातें इस सदन में रखी हैं जिन के ऊपर जनता को भी विश्वास नहीं होगा । जनता को गुमराह करने के लिए ऐसी बातें रखी जाती हैं । देश की जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें इन्होंने कही है । इस का जीता जागता सबूत 74 का आन्दोलन है । हमारे कई साथियों ने 1971 के आन्दोलन का जिक्र किया । टोटल रेवोल्यूशन के नाम पर जब कि सारा देश टोटल प्रगति पर जा रहा था और हर स्तर पर चाहे ग्रीन रेवोल्यूशन की बात रही हो इंडस्ट्री की बात रही हो । सीकर सेक्शन को फाइनैंनशियली डेवलप करने की बात रही हो पोलिटिकल स्टेबिलिटी की बात रही हो या दुनिया के सभी मुल्कों में हिन्दुस्तान की चर्चा एक मजबूती के साथ चलने की बात रही हो, सभी दिशाओं में देश प्रगति पर जा रहा था जब कि यह 74 का आन्दोलन शुरू हुआ और यह 74 का आन्दोलन किस नाम पर हुआ था ? आज यादव जी क्या बता सकते हैं इस बात को और साबित कर सकते हैं कि 74 का आन्दोलन जो हुआ और जो सरकार बदली, उस से कितना फायदा हिन्दुस्तान को हुआ ? क्या इस का आंकड़ा वह दे सकते हैं ? क्या पिछली हुकूमत वाले इस का आंकड़ा दे सकते है ? वे आंकड़ा नहीं दे सकते हैं। इतनी बड़ी क्षति उस से इस मुल्क को हुई कि आज उस को मरम्मत करने में अपने को अक्षम महसूस करना पड़ता है । जब हम भी ईमानदारी से बैठते है और यह सोचते है पार्टी से ऊपर उठ कर तो ऐसा मालूम होता है कि 74 के आन्दोलन को ले कर इस मुल्क को गुमराह कर दिया गया, इस मुल्क को बर्बाद कर दिया गया । नहीं तो हम इस अवधि में कितने सीकर सेक्शन के लोगों की तकदीर को बदल सकते थे और उस रास्ते पर हम चल रहे थे । हम यह कहेंगे कि श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश एक ठोस तरीके से चल रहा था तो कुछ विरोधी पक्ष के लोग मजाक उड़ायेंगे । लेकिन अभी तो आप ने देखा है कि हिन्दुस्तान के अवाम ने श्रीमती इंदिरा गांधी को वोट दिया । मैं जब जाता था क्षेत्र में और लोगों से यह कहता था कि मैं कांग्रेस (आइ) का उम्मीदवार हूं.... (**व्यवधान**) . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now it is nearing 8 P.M. There are some more hon. Members desiring to speak. We have already extended the time up to 8 o' clock. Now, what shall we do? Are we to extend the time further? Tomorrow the Minister will reply. It has been announced. Today this discussion must be over.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: Sir, if it is necessary time can be extended. The House can always revise it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Anything can be done with the approval of the House. Now, what was decided in the morning was that this discussion would be over today. The two State Ministers have already intervened. Tomorrow the hon. Minister will reply. We have already extended time by two hours. Now, may I know the sense of the House?

SHRI N. G. RANGA: Mr. Deputy-Speaker, Sir, are we to understand that it will go on till mid-night? For how many hours are we to sit like this? (*Interruptions*)

SHRI MANORANJAN BHAKTA: Sir, we want to continue our discussion. (*Interruptions*)

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: Sir, may I make a suggestion? Of course, it has been extended upto 8 O' clock and there are some Members also who are very keen to participate in the discussion. So, we can meet the wish of the Members halfway, that is, we can further extend the House by half-an-hour so that some more Members are accommodated.

MR. DEPUTY-SPEAKER: In half-an-hour we may not be able to complete the list of Members who are yet to speak.

SHRI RAJESH PILOT (Bharatpur): Sir, subject to the condition that nobody should speak for more than 5 minutes.... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, there is a suggestion to extend it by half an hour and no Member will take more than 5 minutes. (*Interruptions*) All right, we will extend it by one hour. That is the sense of the House and nobody shall speak for more than 5 minutes.

(*Interruptions*)

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: How can you say that it is the sense of the House? Did you put it to the vote of the House?

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: He has come out with that proposal and I am putting it before the House. If you want, I will take the sense of the House.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: You put it to the vote of the House. You cannot bully us. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will put it to the vote of the House. What is your proposal, Mr. Unnikrishnan?

(*Interruptions*)

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN:**

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, no. You are casting some aspersions. You must withdraw this. It is improper. You must not cast aspersions on the Chair. I am very sorry, Mr. Unnikrishnan you are a very senior Member. You should have brought it to the notice of the House at that time. Please sit down.

(*Interruptions*)

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri): Sir, how many Members are still there to speak?

MR. DEPUTY-SPEAKER: All the Members who have been allotted time have exhausted their time except the ruling party. This is the position. All the Members on the Oppositon side have spoken. But I want to give chance to all again.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Now, with the extended time, everybody should be given the opportunity.

MR. DEPUTY-SPEAKER: If you go through the records, you will find that I have given chance to speak to all. You can verify from the records.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, is it the sense of the House that the House may sit up to 9 O' clock?

SOME HON. MEMBERS: Yes, agreed.

AN HON. MEMBER: Sir, first you expunge the remarks made by Mr. Unnikrishnan from the proceedings.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes, it is left to me.

Now, Mr. Kunwar Ram to continue.

श्री कुंवर राम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि हम जब विरोधियों से कहते हैं कि अगर यह देश सही दिशा में चल सकता है तो वह श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में ही चल सकता है और इसको इस देश के अवाम ने साबित भी कर दिया है । विरोध पक्ष के माननीय सदस्य श्री रतनसिंह राजदा ने आरोप लगाया कि सात महीने की हुकूमत में इस सरकार ने क्या किया ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सात महीने में तो बच्चा पैदा हो जाता है ।

श्री कुंवर राम : सात महीने में जो बच्चा पैदा होता है, वह जिन्दा नहीं रहता है । .... (**व्यवधान**) .... मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि लॉ एंड आर्डर राज्यों का सवाल है । राज्यों में जनता पार्टी की हुकूमत अप्रैल तक रही और फकत दो-तीन महीने का लॉ एंड आर्डर का सवाल हमारे सामने आता है । तो यह जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर कैसे आ सकती है । अगर लॉ एंड

**Expunged as ordered by the Chair.

आर्डर की जवाबदेही केन्द्रीय सरकार पर थोपी भी जा सकती है तो उस पीरीयड में, उस अवधि में राज्यों में जनता पार्टी की हुकूमत थी । उसने यह जान लिया था कि श्रीमती इंदिरा गांधी का लोकसभा के चुनाव में बहुत बड़ा बहुमत मिल चुका है, बहुत बड़ा मेंडेट मिल चुका है, और अब राज्यों में भी उसकी हुकूमत बनेगी । इस स्थिति को देखकर उन्होंने केन्द्र में हुकूमत को कमजोर करने के लिए षड़यन्त्र रचना शुरू कर दिया । इधर केन्द्र से राज्यों की हुकूमत को स्पष्ट रूप से लॉ एंड आर्डर को मेंटेन करने के लिए आदेश जाते रहे, सर्कुलर्स जाते रहे, चिट्ठियां जाती रहीं, लेकिन राज्यों ने उनको कोई वैल्यू नहीं दी, तो क्या श्री रत्नसिंह राजदा साहब का आरोप इन बातों को देखते हुए सही सिद्ध होता है । मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार के एक-दो महीने की हुकूमत में कोई खास परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है । लेकिन जनता पार्टी के लोगों ने केन्द्र की हुकूमत को बदनाम करने के लिए, केन्द्र की फाउन्डेशन को कमजोर करने के लिए षड्यन्त्र रचना आरम्भ कर दिया था ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी को काग्रेस (आई) पार्टी ने नहीं तोडा । हिन्दुस्तान की जनता ने हमें भारी बहुमत देकर, हम लोगों के कंधे पर केन्द्र की सरकार को चलाने की जिम्मेदारी सौंपी है । जब इनकी पार्टी टूट गई और ये जनता के पास वोट मागने के लिए गए, तो जनता ने पूछा कि हमने आपको पाच वर्ष की अवधि के लिए बैठाया था और आप दो-ढाई वर्ष में हमसे वोट मागने के लिए क्यों चले आए ? यह आपका दोष था कि आप हुकूमत को सभाल नहीं पाए । मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप फिर हमारी नींव को कमजोर करना चाहेंगे, तो मैं यह ऐलान करता हूं कि जनता पार्टी, जो पहले ही कई पार्टियों में विभक्त हो गई है, के सामने यह प्रश्न फिर उठेगा । मैंने एक हुकूमत का मौका तुम को दिया, लेकिन तुम ने नहीं सम्भाला, अब हम को सिर्फ इन्दिरा गांधी में आस्था है, हम उन के एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे । हिन्दुस्तान की जनता ने श्रीमती गाधी में विश्वास रखते हुए उन को प्रबल बहुमत दे कर इस सदन में हिन्दुस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन सम्भालने के लिए भेजा और यह कह कर भेजा कि जनता पार्टी ने हिन्दुस्तान में अशान्ति फैला दी है, लॉ एण्ड आर्डर सिचुएशन को तबाह कर दिया, मंहगाई को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है । आप कहेंगे कि मंहगाई इधर भी बढ़ी है । मैं पूछता हूं--क्या इस में पिछली हुकूमत की देन नहीं है ? यह पिछली हुकूमत की देन है, जिस के कारण आज महगाई इस तरह से बढती चली जा रही है ।

जब तक यह हुकूमत नहीं बदली थी, उस से पहले की हालत आप को बतलाता हूं । हम बाजार में जाते थे--यह ट्रेण्ड बन गया था कि जनता पार्टी की हुकूमत व्यापारियों की हुकूमत है, जनता पार्टी की हुकूमत भ्रष्टाचारियों की हुकूमत है, स्मग्लर्स की हुकूमत है । खुले आम जो आलू सुबह 1 रुपये किलो बिकता था, शाम को उसी आलू के दाम दो रुपये हो जाते थे और उस को कोई रोक नहीं सकता था । इस तरह की विरासत हम को मिली है । इस बिगड़ी हुई परिस्थिति को सुधारने में आज हमारी प्रधान मंत्री जी लगी हुई है, लेकिन इस काम में भी हमें इन लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है । आप जिस तरह की आवाजें उठा रहे है, उन से देश का भला होने वाला नहीं है । जनता में जिस तरह की आवाजें आप उठा रहे है, वे आवाजें श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतत्व से दबेंगी । श्रीमती इन्दिरा गाधी को बदनाम करने से कुछ नहीं होगा, जनता आप के हथकण्डों को समझ चुकी है । आप ने उन को जेल में डालने की कोशिश की, लेकिन आप असफल रहे । आज मैं दावा करता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गाधी महगाई को कन्ट्रोल करेंगी, लॉ एण्ड आर्डर सिचुएशन को अपने कब्जे में करेंगी--अब वह समय दूर नहीं है ।

मैं इस मंत्रालय की मागों का समर्थन क्यों कर रहा हूं ? वजह यह है कि हमारे धनिक लाल जी मंडल एक दम पीछे से दौड़ते हुए आगे आये और फिर आगे से दौडते हुए पीछे गये और कहा कि इस विभाग को एक पैसा न दो । मैं उन से कहना चाहता हूं कि हम उन की करनी के फल को ही भोग रहे है, आज उन की करनी के कारण ही इस तरह की कठिनाइयां हमारे सामने आ रही है । हम ने उन को दुरुस्त करने का वायदा किया है । हम हिन्दुस्तान के लॉ एण्ड आर्डर को सुधारेंगे, मंहगाई को ठीक करेंगे ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am going to call the next speaker.

श्री कुंवर राम : अभी कन्क्लूड नहीं कर सकता हूं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Already you have concluded. Nothing will go on record.

श्री कुंवर राम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरिजन हूं और ऐसे क्षेत्र से आया हूं, जहां हरिजन ज्यादा संख्या में हैं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can speak tomorrow on some other subject. Whatever he speaks shall not go on record.

(Interruptions) **

**Not recorded.

श्री चन्द्रपाल सिंह : (अमरोहा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रालय की मांगों पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं और उस के लिये जैसा वातावरण यहां पर बनाया जा रहा है, वह बड़ा दुखद है । सिर्फ इन्दिरा जी की तारीफें हो रही हैं, यह नहीं देखा जा रहा है कि कमी कहां पर है । वह किस तरह से दूर हो सकती हैं । जब कांग्रेस पार्टी शासन में आई तो वह जनता पार्टी को दोष देती है और जब जनता पार्टी आई थी, तो वह कांग्रेस पार्टी को दोष देती थी । यही होता चला आ रहा है.... (**व्यवधान**).... लोक दल भी कह लीजिए । मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि यह बात देखने की है कि यह व्यवस्था, दुर्व्यवस्था जो बनी है, वह किस तरह से बनी है । अगर देश में शान्ति नहीं है, तो देश विकास नहीं कर सकता । ऐसा क्यों होता है उस के इतिहास में आप को जाना होगा और सब से बड़ी बात यह देखने की है कि इस सब का कारण क्या है । आज पुलिस पर से जो आस्था लोगों में कम हो गई है, उस के लिए हम क्या करें । अगर पुलिस में आस्था नहीं रहेगी, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है । उस के लिए आज का जो पुलिस का ढंग बना हुआ है, उस को देखने की जरूरत है । आज पुलिस का जो सब से छोटा कर्मचारी है, सिपाही है, उसको ऊपर उठाने के लिए विशेष उपाय करने पड़ेंगे । आज हम देखते हैं कि एक पुलिस सिपाही में और एक बड़े अफ़सर में जमीन आसमान का अन्तर है । उस को कम करने के लिए हमें उन की तन्खवाहें बढ़ानी चाहिएं, उन के लिए होस्पीटल्स, मेडीकल फैसिलिटीज की व्यवस्था करनी चाहिए, उन के बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए । इस गरीब देश में हम जितना उन के लिए कर सकते हैं, उतना करना चाहिए और सरकार को उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि आज सिपाहियों की संख्या पुलिस फोर्स में 80 फ़ीसदी है । अगर उन को प्रोमोशन नहीं देंगे, तो पुलिस में रिजेन्टमेंट रहेगा जैसा कि आज वह बना हुआ है ।

इस के अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे आज साइंस आगे बढ़ रही है, उसी तरह से पुलिस को भी आधुनिक यंत्रों से लैस करना चाहिए । पुलिस के लिए अच्छे हथियारों का इन्तजाम होना चाहिए और पुलिस के इन्तजाम की सारी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए । इस के अलावा आज जितनी आबादी बढ़ गई है, उस के हिसाब से पुलिसमैनों की संख्या नहीं बढ़ी है इस तरफ़ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कहने को तो कहा जा सकता है कि यह स्टेट सबजक्ट है लेकिन मैं यह कहूंगा कि आपको भी रचनात्मक कार्य उन के लिए करने चाहिएं ताकि वे सुख से रह सकें । चारों तरफ़ एक वावेला मचा हुआ है कि यह जो सरकार बनी और विधान सभाओं में जो यह सरकार आई, तो उस में पुलिस का पूरा इस्तेमाल किया गया है और आज सब जगह इस की चर्चा रहती है । जब भी शासकीय दल अपने लाभ के लिए पुलिस से काम लेगा, तो जैसा कि हमारे एक भाई कह रहे थे कि वे लोग यह कहते हैं कि गद्दी पर बैठने के लिए जब हमारा इस्तेमाल किया है, तो क्या हमें दबाने के लिए ऐसा किया है । अभी बागपत का केस हुआ । वहां पर पुलिस के अत्याचार की भावना प्रकट होती है और उस के बारे में बहुत से लोगों ने कहा है लेकिन जिस तरह की बात वहां पर हुई है और जैसा वातावरण वहां पर बना हुआ है, उसे सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और बैठ कर उस समस्या का समाधान करना चाहिए न कि उस बात को दबाना चाहिए । इस तरह से जो समय का दुरुपयोग हो रहा है उस को बचाना चाहिए और मैं तो यह कहूंगा कि आप को बागपत की घटना के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए और ज्ञानी जैल सिंह जी और माननीय गृह मंत्री जी, जो यहां बैठे हुए हैं, उन को इस को प्रेस्टिज का प्वाइन्ट नहीं बनाना चाहिए और यह नहीं कहना चाहिए कि वहां उस समय दारोगा नहीं था और डी०एम० ने यह कह दिया और वह कह दिया । इस तरफ़ आप को विशेष ध्यान देना चाहिए और जो आप का पैसा है और जो आप की शक्ति है, वह देश के दूसरे लाभकारी कामों में लगनी चाहिए ।

एक दूसरी बात मैं यह और कहना चाहता हूं कि यह जो लाइसेन्स प्रणाली है, जो हथियार देने का एक तरीका देश में बना हुआ है कि खराब आदमी को लाइसेन्स मिल जाता है और अच्छा आदमी उस से महरूम रह जाता है, इस को फ्री कर देना चाहिए । जो लेना चाहे, वह हथियार ले ले । आज दूसरे मुल्कों में सब में यह प्रणाली है कि सब को लाइसेन्स मिल जाता है ।

आप ने जो मुझे समय दिया था, उसी में मैंने अपनी बात कह दी है और मैं आप को धन्यवाद देता हूं और आप से प्रार्थना करता हूं कि जो मैंने सुझाव दिये हैं, उन पर ध्यान दिया जाए ।

SHRI MANORANJAN BHAKHTA (Andaman and Nicobar Islands): Mr. Deputy-Speaker, I rise to speak on the Home Ministry's Demands for grants. There is a long list of objects for this ministry but I would like to deal with only three points: law and order situation in the country, the

department of personnel, and the Union Territories. So far as law and order situation is concerned, you will appreciate that it is part of a conspiracy which is going on in this country. I cauton the Union Home Minister to be vigilant and take action because it is not simply a matter of lawlessness in this country. In this country a situation came up in 1977, when there was a new Government under the leadership of Shri Morarji Desai; it was a weak Government. At that time, finding the weakness of the Government, they tried to create instability, chaos and lawlessness and thereby tried to lead the country towards a situation of civil war. What is going on in West Bengal? West Bengal comes on my way from my Constituency to Delhi. Moreover, every day I am receiving a number of letters. A large number of political workers are murdered. Their houses are burnt. Many things are happening. The police is not registering their cases. The analysis or figures shows that the number of crime cases is on the decline day by day but in Tripura, in West Bengal and in some such patches, the number is increasing. Therefore, I say, you must make it a point that it is not a simple process of lawlessness in the country. It is a part of conspiracy. Even, it may have link with international conspiracy, to have chaos in this country and to lead the country towards civil war.

Many people talk about rape and atrocities on the Harijans. This is a heinous crime and in civilized society, this sort of activity should be condemned. I would like to say if any lady, any women, and mother or sister of ours is stripped in any place, by an individual or by some political group, the culprit should be severely punished. At the same time I would also like to appeal through this House to our sisters in the country that they must try to avoid mini and Provocative dresses so that they can help law and order enforcing authorities to check the crimes.

Whatever decision is taken by the Government or the Department of Personnel and Administrative Reforms, that decision must be implemented. Whatever decisions you take, those decisions must be implemented. But what is your implementing machinery? Implementing officers are police and other forces. If these forces are not efficient and sufficient in number and if they are not in tune with the needs of the day and they are not ready to implement, it is very difficult to ease the situation. A deep thought has to be given by the Government how to increase the efficiency.

I am proud, as I have seen the employees of this Parliament House, of their efficiency. They are one of the most efficient sets of persons working in India and I must say that if half of this efficiency is given to any of the Government Departments and other workers, I am sure there will be definite improvement in the law and order situation. Not only that, whatever decisions we take, those can be implemented.

Unless you remove the anomalies, you give wages and other things properly and unless you look into the grievances of employees—workers and policemen and senior Officers-Class I and II and the clerks and the people working in the lower level, we will not be able to do anything in this country.

Ministry of Home Affairs is responsible to provide good Government in the Union Territories. They are responsible for the development of the Union Territories. I come from the Union Territory of Andaman and Nicobar which is directly administered by the Union Home Ministry. I am sorry that Shri Dhanik Lal Mandal is not here now. He was in charge of the Union Territories and looked after the Andaman and Nicobar Islands during the Lok Dal and Janata rule. I just wanted to quote some of the examples of how that Government worked. What was the situation that

prevailed there in the Union Territories then. We do not have any Assembly or elected forum except this House. There was one advisory committee associated with the Union Home Minister as well as the Chief Commissioner. They used to discuss some matters of public grievances. The village panchayat pradhans used to be members and they could ventilate the peoples' grievances there. But as as soon as the Janata Government came to power, only one meeting was held under the chairmanship of Chaudhari Charan Singh and later on this committee was discontinued. They talk about democracy. But whatever democratic right we had, they snathched it away from us. Now Mr. Makwana has promised that something would be done so that the people of that territory may be properly looked after. I am grateful for that.

Coming to development activities, water scarcity is very much there. We are always representing to the Government of India for more money for water supply schemes. Regarding this, the reply I got to an unstarred question on 15-7-78 was this:

	No. of water taps	Expenditure
		Rs. in lakhs
Mayabunder . .	278	6.00
Diglipur . . .	183	4.60
Rangat . . .	207	3.81

Out of these, Government quarters got 234, 154 and 189 water connections but private quarters got only 23, 3 and nil respectively. This was the reply given on 15-7-78 by Shri Dhanik Lal Mandal.

In reply to another parliamentary question, it was stated that Rs. 7½ crores were surrendered to the Government of India back, because they could not implement anything. I am not biased, but during the three years of Janata-Lok Dal rule, they have completely stopped the development activities in that far flung territory. This is the situation that prevails and they feel insecure. I went on a fast for 14 days in the territory with a 90 point charter of demands addressed to the then Prime Minister, Shri Morarji Desai. This amount of money was returned back because they could not implement the development schemes.

Coming to employment, young people are every day running about for employment. But it was said in a reply on 2-7-80 that since the ast 1½ years, 635 posts were lying vacant in the different departments there. This is what the Janata regime did in that far flung Union Territory.

I am now asking the Government, what are you going to do in that territory? On the one side there is Indonesia, only 92 miles away. On the other side, there is Burma, only 150 miles away. In between we have 319 big and small islands having tribal population and people from different parts of the country. Perhaps we can claim that this is the part of the country where there is true national integration. Anybody from this House can go there and see how people of all kinds, irrespective of caste, creed, religion and language, are living together. It is a mini-India. In that territory, we are getting natural resources like gas and petroleum products and there is a bright future. What is the Government of India going to do in that territory? That is my question. At the same time, if you only have district development plans, that will not help. The Home Ministry must take the initiative. You must have some special plan for the accelerated development of these areas. The grievances of the people of Andaman and Nicobar Islands should be properly looked after. What is happening in the North-Eastern region and other places should not be

repeated in that peaceful territory. My earnest request is that whatever has been mismanaged and undone by the Janata Government, our Government should set things right. Indiraji has got a very soft corner for the small territories. She has her good wishes for us. She wants to do something.

I would like to appeal to the Home Ministry and the Home Minister Incarge to kindly look into the grievances of this far flung Union Territory for the sake of this country.

SHRI NGANGOM MOHENDRA (Inner Manipur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I have been waiting with the greatest patience and have been listening to what—have been said about the North-Eastern region. I am not going to refer to any other part because they have all been well represented. But I would like to mention what is happening and transpiring in that region, particularly in my State.

My friend from Meghalaya stated, in his enthusiasm that Manipur was also represented in Parliament by the representatives of Assam. That is not correct. Manipur has always been having her own representatives' right from the First Lok Sabha. This may be taken note of.

There has been a lot of reference to our region. Some are condemnatory, some are with certain idea, with certain wish to do something good to solve the problem that has been aging there. Some of my friends have tried to say in milder terms that they were going to solve the problem. But at the very outset, I would like to mention before the House that the problem is not such which can be solved by any sort of tinkering. There is a common belief there in Manipur that whatever feelings are there they are because of the neglect of that area by the successive Governments at the Centre. During the last 32 years—I do not want to enter into any debate—my small State, Manipur, has seen not only successive changes of abortive Governments but also long, medium and short spells of President's rule with nothing achieved. It may also be mentioned for the information of the hon. Home Minister and the hon. Minister of State for Home Affairs that Manipur was under the rule of their Ministry till 1972 when we got our full statehood. Therefore, the Home Ministry had and have every reason to take responsibility for what had been and is happening there. Uptil 1972, we were directly under the rule of the Home Ministry.. Even a mere Joint Secretary was our God, was our President, was our Prime Minister, was our everything and God knows what those Secretaries have been doing! Of course, some of my friends have said that the Home Ministry was adorned by eminent personalities which India had over produced. Even then I would submit that perhaps none of those Ministers had any acquaintance with the problems obtaining there throughout these 32 years. Even now I challenge, they do not know. They do not know what is happening there. There are bureaucrats assisting the Minister in the Home Ministry. It is the Home Minister or for that matter the Home Ministry which tries to be spoon-fed by those bureaucrats. Of course, I am not going to dig into the affairs of the Home Ministry, but there are some bureaucrats in the Home Ministry who must have been advising on the affairs of Manipur and the North-Eastern region. What have they been doing? I met the Governor, Mr. L. P. Singh, a civil servant of eminence, as is said the moment insurgency began in that State. Of course, I was not an M.P. then. He said: 'Oh, this is nothing. Some 30 or 40 boys are doing all this.' What then is happening there now? Perhaps the Home Ministry must have heard some such utterances not very responsible ones from Mr. L. P. Singh or some central Secretaries here. There is a common

bellief in Manipur that some bureaucrats in the Home Ministry are concerned more with the promotions, appointments and transfers of certain personalities like IAS and IPS officers who think themselves to be God-sent. They are in power.

MR. DEPUTY-SPEAKER: God's avtar.

SHRI NGANGOM MOHENDRA: Yes, The moment I became M.P. I am seeing that at least 90 per cent of these Secretaries/Commissioners visit Delhi at least three times in a fortnight! What type of consultation they are having either with the Home Minister or with the Prime Minister, God knows. They are here perhaps in connection with their children's education or something like that.

MR. DEPUTY-SPEAKER. Please conclude.

SHRI NGANGOM MOHENDRA: If you want me to step ..

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, no. You can continue for another two or three minutes.

SHRI NGANGOM MOHENDRA: Now, I want to give an account of the five-month old Congress (I) Government. It is not an insinuation. Nor am I demanding dissolution. I have been hearing in this august House in the first Session that very many important personalities who are now Ministers, and who were not Ministers but M.Ps. then, demanding the dissolution of certain Legislative Assemblies. The reason being worsening of the law and order situation in those States. If this criterion is to be adopted, Manipur Ministry deserved dissolution long long ago. But I am not demanding it. I am only stating it as a matter of fact.

Now, during the last 5 months, there have been over 90 broad daylight murders, all by shooting in the board light. murder of security personnel, policemen, Manipur rifles, BSF civilians and what not and of these at least 20 during the last 5 months of the Congress (I) rule. Again, broad day-light robberies of banks have been the alternate-day incidents throughout these 5 months of the Congress (I) rule. I do not say that they are encouraging. But it is happening during their rule.

एक माननीय सदस्य : आप एक-एक माननीय सदस्य को बीस-बीस मिनट दे रहे हैं तो औरो का क्या होगा ? . . . . (**व्यवधान**) . . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: He will conclude by 8.42. He has got two more minutes.

SHRI NGANGOM MOHENDRA: I have been attending this House, and I have never interrupted anybody. My learned friend seems to be a little elderly also. I hope he will reciprocate.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He has agreed.

SHRI NGANGOM MOHENDRA: Not a single miscreant involved has been arrested. Of course, there may be some sort of hanky panky publication saying that five suspects have been arrested etc. but in reality not a single miscreant directly or indirectly concerned with the incidents has been arrested.

Many of our friends have been complaining about political assassinations elsewhere. For us the year 1980 opened with the murder by shooting of a veteran communist leader Comrade Bira Singh, who was himself a candidate in one of the Assembly constituencies. But not a single murderer nas been traced till now. Therefore I submit for the consideration of the two Ministers in the Home Ministry to find out whether any of the officers, and for that matter, any of the Ministers are hobnobbing with any of the factions of the so-called hostile leaders. Nowadays so many

sonorous alphabetical combinations are there to indicate these clandestine organisations adequate mention of which had been made by other members and I need not repeat them

It will be surprising to you to know that there are nine intelligence agencies functioning in Manipur with all sorts of names, RAW, PAW and so on, all perhaps giving conflicting information. The Home Minister or somebody in the Home Ministry may know it. Let them deny it if untrue.

There is also the feeling that whoever goes from here, right from the Prime Minister, whether in office or out of office, makes so many promises. So, I was amused to listen to the prescription of a lot of panaceas by our hon. Minister of State to cure the ills of the northeastern region. But I fail to persuade myself to believe in all these things because we have all along been promised many things, only to be forgotten and only to be broken with impunity.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude. You have spoken very well.

AN HON. MEMBER: He should have been given an opportunity earlier.

SHRI NGANGOM MOHENDRA: This is the lot of the small States.

So, something must be done to tone up these God-sents from here. With the exception of one or two, they are all unwanted. With all respects to them, they may be generally very good in Delhi, but they are very bad there. That is not only my opinion, but it is the general comment in Manipur.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can meet the Home Minister and give your points to him.

SHRI NGANGOM MOHENDRA: Another surprising feature is that Manipur has been made the rendezvous for the meeting of these big officials. Something happens and the Director General of the CRP will fly from Delhi to Manipur, then the Commander of the Eastern Army, some Lt. General, will fly from Calcutta, then L. P. Singh will fly from Shillong, and some other person from somewhere else. They will discuss the matters without any of our representatives including their own Chief Minister. That is what happened the other day. I was going with the Deputy Chief Minister, and I told him that something was going on and asked him if he knew anything about it. He said "no". So, when things are being done or decided without us, the result is quite abvious. (*Interruptions*) If it is unpalatable. I cannot help, I am stating stark realities.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI NGANGOM MOHENDRA: Manipur became a part of India or was merged with India by the Merger Act of 1949. Before that, we had our own Assembly, we had our own Constitution making body, we had our own elected Assembly there; whether it was good or bad, that is different. But after the merger, we are bogged down and we are trailing far behind other Indian States.

I will read out Article 8 of the Merger Act.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is not relevant to the subject proper. You need not read that. Please conclude.

SHRI NGANGOM MOHENDRA: My nature is very docile. I will conclude. We must try to get at the root of the problem and for that, I draw the attention of the Home Minister to the unemployment and industrial backwardness.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Some more Members are to speak. Please conclude.

SHRI NGANGOM MOHENDRA: Unemployment and industrial backwardness in a State, where the literacy is more than 40 per cent in a population of 15 lakhs must be taken note of. The time bomb of educated unemployed is only beginning to burst in a State, which had been comparatively quite for three decades. Any strong arm methods will not do.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can meet the Home Minister and mention to him the rest of the points. I am now calling the next Speaker.

Shri Hiralal Parmar.

श्री हीरा लाल आर० परमार (पाटन) : मानवीय उपाध्यक्ष जी, मैं गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए इस देश में सामाजिक असमानताओं की आलोचना करना चाहता हूं। मैं इतना भाग्याशाली हूं कि मुझे रात के 9 बजे बोलने का अवसर मिला है और 540 सदस्यों की लोकसभा में तीन प्रतिशत से कम सदस्यों की हाजिरी में बोलने का मौका मिला है।

मैं एक गम्भीर बात की ओर आपका ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं। मैं जब संसत्सदस्य नहीं था और जनता पक्ष का शासन चलता था उस समय अखबारों में हरिजनों की हत्याओं की खबरें पढ़कर मुझे बहुत दुःख होता था। हमें सोचते थे कि इस देश में हमारे लिए क्या होने वाला है, क्या हम इनसान नहीं हैं और क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं इस देश में हमारी क्या दशा होगी? संसद् में आने के बाद सात महीने में मैंने कुछ देखा, कुछ सुना तो मुझे लगा कि संसद् में बैठने वाले हमारे सारे माननीय सदस्य, सभी जाति के बनिया, पटेल, क्षत्री, ठाकुर, ब्राह्मण सभी दलों के लोग हम हरिजनों के लिए रो रहे हैं। यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई कि अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे हिन्दुस्तान के सब दल के लोग हमारी रक्षा करने के लिए पूर्ण रूप से जागृत हैं, लेकिन फिर भी मैंने विचार किया जब सब लोग हमारी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर क्या पाकिस्तान, चाईना, अमरीका, जर्मनी या जापान के लोग हम लोगों को मार रहे हैं? हमारी हत्या करने वाले आखिर कौन लोग हैं? इन सब चीजों को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस संसद् में हमारे लिए जो लोग रो रहे हैं, हमारे लिए आंसू बहा रहे हैं वही लोग हमको खतरे में डाल रहे हैं। हमारे गुजराती में एक कहावत है–

बगल में छुरी, मुह में राम ।
है हरिजनों की हत्या करने का काम ।।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि सब दल के सदस्य क्यों रो रहे हैं। मैं जानता हूं हमारा देश स्वतन्त्र है, हमारा देश आजाद है, यहां लोक शाही से शासन चलता है। देश में हमारी 25 प्रतिशत आबादी है और ये लोग हमारी तरफदारी लेकर शासन पर बैठना चाहते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये गलत आंसू बहा रहे हैं। अब 33 साल की आजादी के बाद हमारा दिमाग भी कुछ काम करने लगा है, ऐसे लोगों का अब हम समर्थन देने वाले नहीं हैं। इस संबंध में भी अब सोचना जरूरी है।

अब मैं हरिजनों और पिछड़ी जातियों के लोगों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए और उन लोगों की रक्षा करने के लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। अगर मैं सारी बात कहूं तो रामायण जैसे सैकड़ों ग्रन्थ हो जायें, महाभारत के सैकड़ों ग्रन्थ बन जायें। सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए कुछ कानून बनाए हैं और रिजर्व बैंक द्वारा सर्कुलर भी भेजे गए हैं कि देहातों में पिछड़ी जातियों के लोगों को ग्रामोद्योग के लिए 5 हजार रु० बिना जामिन के दिए जायेंगे, लेकिन उस कानून पर राष्ट्रीकृत बैंक अमल नहीं करते हैं और हरिजनों को इस उद्देश्य से जो रुपया दिया गया है वह जीरो प्रतिशत है। ढाई साल के जनता पार्टी के शासन में हरिजनों को लोन नहीं दिया जाता था, क्यों कि जनता पार्टी के शासन में बैंकों में ऐसे मैनेजर घुस गए थे, जो हरिजनों और आदिमजाति के लोगों के साथ अन्याय करते थे। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में जिस स्टेट का जो मैनेजर काम कर रहा है, उसको दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर दिया जाए।

दूसरा सुझाव यह है कि अब छूआछूत के बारे में भी हम ध्यान देना होगा। आवास के लिए जो जमीनें हरिजनों को दी जा रही हैं, वह सबके साथ दी जायें। हरिजनों के लिए अलग जमीन देने के ऊपर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए।

इन्डस्ट्रीज के लिए भी कोई सुविधा नहीं दी जाती है। इन्डस्ट्रीज में हरिजनों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हरिजनों को इन्डस्ट्रीज में लाने की जरूरत है। मेरा यह भी सुझाव है कि छोटी इन्डस्ट्रीज की ग्रान्ट के लिए हरिजनों को 80 प्रतिशत रुपया 4 प्रतिशत ब्याज पर दिया जाए और 20 प्रतिशत रुपया सब्सिडी के रूप में दिया जाए।

एक बात मैं पुलिस के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे गुजरात में डी० एस० पी० और एस० पी० रैंक के आठ दस आदमी हरिजन जातियों के है लेकिन उनको समाज में जाने का मौका नहीं दिया जाता है, वे लोग दफतर में ही बैठकर काम करते है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इन लोगों को भी दूसरे लोगों की तरह से समाज में जाने का और काम करने का मौका दिया जाना चाहिए ।

ग्रामोद्योग, छोटे उद्योग और चमड़ा उद्योगों को जो सुविधा सरकार दे रही है, वह बहुत कम है। इस पर ध्यान दिया जाय और इन सुविधाओं को बढ़ाया जाय ।

आप की आवास के बारे में न० 219 की स्कीम थी, जिस को जनता पार्टी के शासनवालों ने ढाई साल पहले बन्द कर दिया था। यह स्कीम हरिजनों के आवास के लिये है, मैं चाहता हूं कि इस को फिर से चालू किया जाय।

मैं ज्यादा वक्त न लेते हुये, आप ने मुझे रोने का मौका दिया है, उपाध्यक्ष महोदय, इस के लिये आभार प्रकट करता हूं ।

श्री एन० ई० होरो (खुन्टी) : उपाध्यक्ष जी, मैं सरकार से इस समय केवल एक बात कहना चाहता हूं जो निति के सम्बन्ध में हैं। नार्थ–ईस्ट रिजन एवं आदिवासी क्षेत्रों के लिये जो नीति सरकार चला रही है, उस को सुधारने की जरूरत है। आप पुराने अंग्रेजों के समय की कोलोनियल-इम्पीरियलिस्ट टाइप की नीति को अभी भी चला रहे हैं और जैसा कि एक माननीय सदस्य ने अभी कहा, उस से साबित होता है कि आदिवासी क्षेत्रों में जहां अशान्ति है, वहां की समस्याओं का समाधान करने के लिये सरकार के पास कोई ठोस नई नीति नहीं है। आप स्ट्रांग आर्म्ड मेजर्स के आधार पर काम करना चाहते हैं और आप के विभाग के अफसर भी उसी पुरानी लकीर के फकीर बन कर चलना चाहते है .... उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी मेरी बात को सुन नहीं रहे है...

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your speech is being recorded.

AN HON. MEMBER: They are giving thought to your speech.

श्री एन० ई० होरो : जो नीति आप नार्थ–ईस्ट इण्डिया के लिये चला रहे है, उस को सुधारने की जरूरत है। यह कालोनियल इम्पीरियलिस्ट नीति है, इस को सैकेन्ड लुक दीजिए और इस पर नये ढंग से नीति बनाइये ।

सरकार के जितने बयान आते रहे हैं और आज भी दोनों राज्य मंत्रियों ने जो बयान दिये हैं तथा--परसों प्रधान मंत्री जी ने भी जो कहा है उसमें यही कहा गया है कि जो आन्दोलन पूर्वी क्षेत्र में चल रहा है, वह एन्टी नेशनल है, एन्टीसोशल है, मिसक्रिएन्टस उस को चला रहे हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि आप ने यह नहीं देखने की कोशिश की है कि वे मांग क्या कर रहे हैं। उन की मांग जायज है या वे क्या राजनीतिक बात कर रहे हैं—इस पर आप को नये ढंग से विचार करना चाहिये। बिना सोचे समझे उस पर अपने विचार प्रकट नहीं करने चाहिये। आप उनकी मौलिक समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करते और लाठी और गोली लेकर उन का मुकाबला करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये।

स्टेट मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा है कि छोटा नागपुर और संथाल परगना के लोग अलग प्रान्त बनाने की बात कर रहे हैं, इस से फिस्सी फेरस टेण्डेंसीज को बढ़ावा मिलेगा। मैं पूछता हूं, जब गुजरात बन रहा था, तब आप ने अलगाववाली शक्तियों को बल मिलेगा ऐसा नहीं कहा था। जब महाराष्ट्र बना, आन्ध्र बना, पंजाब बना, उस वक्त कोई भी इस बात को कहने वाला नहीं था, लेकिन जब आज आदिवासी क्षेत्र में नये प्रांत बनाने की बात निकली है तो आप कहते है यह सिसेशनिस्ट टेण्डेन्सी है, इससे फिस्सी फेरस टेण्डेन्सीज को बढ़ावा मिलेगा । इस लिये आप को अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा । आप को अपनी नीति को सुधारना चाहिये । आप इस बात को मान्यता दीजिये कि आदिवासी क्षेत्र में जहां भी संघर्ष चल रहा है जहां ऐसी बातें हो रही हैं, उस के पीछे एक इतिहास है वे अपने अधिकार के लिये अपनी जुबान और संस्कृति एवं मौलिक मान्यताओं के लिये लड़ रहे हैं—इस बात से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता ।

बहुत सारे कमीशन बने, ढेबर कमीशन बना, दूसरे कमीशन्स बने, लेकिन आप ने उन की सिफारिशों पर अमल नहीं किया । आपके पास कमीशनों की रिपोर्टें हैं, लेकिन जो आप के विभाग के अफसर हैं, ब्यूरोक्रेसी है उन का मन एक ढंग का बना हुआ है और आप उसी ढंग से सोचते हैं। आप इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें। हम लोग जो अलग झारखण्ड प्रान्त की मांग कर रहे हैं वह जायज मांग है और इस क्षेत्र को वह दिया जाना चाहिये, इसमें वे सारी बातें मौजूद हैं जो एक अलग प्रान्त के लिये आवश्यक हैं आप को मालूम होना चाहिए कि अंग्रेजों ने 1911 से 1936 के बीच में झारखण्ड को चार टुकड़ों में बांट दिया । यह आदिवासियों का एक अखण्ड क्षेत्र था। जिसमें नेशनल इनटेग्रेशन का प्रोसेस चलता रहा है मगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के आधार पर उस को चार टुकड़ों में 1911 और 1936 के बीच में बांट दिया गया था। इस का

कन्सोलीडेशन होना चाहिए इस पर यदि आप विचार नहीं करेंगे और सिर्फ यह कहेंगे कि वहां जो बेकवर्डनेस या असन्तता है उसके लिए आर्थिक पिछड़ापन जिम्मेदार है। तो समस्या का समाधान नहीं होगा कुछ बुनियादी मुद्दे हैं, जिनको मैंने कहा है उसे आपको देखना पड़ेगा आप इनको नजरान्दाज नहीं करें।

21.00 hrs.

मैं कुछ आसाम की बात कहना चाहता हूं जहां पर फारेनर्स की बात कही जाती है। आज वहां पर 50 लाख आदिवासी और हरिजन ऐसे हैं जिनको आदिवासी और हरिजनों की लिस्ट में नहीं रखा गया है। 1950 से आज तक उन की समस्या को हल नहीं किया गया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार, जो 30 साल तक पहले थी, उस ने इन्हें आदिवासी हरिजन माने जाने का बराबर विरोध किया है, उस ने यही बार-बार कहा है कि आसाम के चाय बगान के जो मजदूर थे और जो आज भी काम कर रहे हैं, उनको आदिवासी और हरिजन नहीं माना जा सकता है। ये आदिवासी और हरिजन 45 लाख हैं इनके अलावा 5 लाख दूसरी जातियां है, जिन को आप की पार्टी के मेघालय के मेम्बर ने कहा है कि उनको आदिवासी नहीं माना गया है। इस मामले को आप को देखना होगा क्योंकि यह एक भयंकर रूप लेती जा रही है। उस मसले को आप हल नहीं कर रहे है। आप इसी कोशिश में हैं कि कांग्रेस (आई) की सरकार आसाम में फिर से बन जाए। आसाम में जो मूवमेंट चल रहा है, उसका सामना करने के लिये एक काऊन्टर मूवमेंट आप करना चाहते है। आप को चाय बगान के एवं अन्य आदिवासियों के अस्तित्व की रक्षा करने के लिए शेड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में परिवर्तन करना चाहिये। असामा के इन आदिवासियो का प्रतिनिधि मंडल आपसे मिला था उनकी बात स्वीकार कर उन्हे आदिवासी हरिजन लिस्ट में शामिल कीजिये। मैं ऐसे मुद्दे उठा रहा हूं, जो आदिवासी क्षेत्रों से सम्बन्धित है उनको आप नजरान्दाज मत करिये। इन पर गहराई से विचार न होगा तो देश को तोड़ने का काम होगा। आप देश को तोड़ने का काम मत कीजिए। जो कुछ हो रहा है वह 30 साल से हिन्दुस्तान में कांग्रेस सरकार की गलत नीति के कारण हो रहा है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभायी है। इसी कारण इतना विकराल रूप इस समस्या ने ले लिया है। आज अगर आसाम और लोग देश से निकलना चाहते हैं तो इस के लिए कांग्रेस की नीति जिम्मेवार है। आप ने ऐसी स्थिति पैदा की है कि अमेरिकन शक्ति, चाइना शक्ति और दूसरी शक्तियां वहां आ रही हैं। उन को क्या किसी ने बुलाया है, किसी ने न्यौता दिया है। आपने ही ऐसी स्थिति पैदा की है। जिससे बाहरी शक्ति घुसपैठ कर रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप को अपनी इस नीति को बदलना होगा और नये ढंग से काम करना होगा। जो लोग लोकतंत्र की अवाज उठा रहे हैं उन को आप एन्टीनेशनल कहते हैं। ऐसी बात मत कहिये। उन्हीं से आप को बातचीत करनी है और मामले को सुलझाना है, या यदि उन को आप सुबह शाम एन्टी नेशनल और सेशेसेनिस्ट कहेंगे, तो उन का दिल जल जाएगा और बात बिगड़ जाएगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लूज टाक मत कहियें और समझबूझ कर समस्या को हल कीजिये। होता क्या है कि जो आप के विभाग से बात बन कर आती है वही आप कह डालते हैं। आदिवासी क्षेत्र से नये प्रांत बनाने की बातें उठ रही हैं उन पर विचार करने के लिए आप एक नेशनल कमीशन बनाइये। नेशनल कमीशन बनाकर गहराई से वहां की प्राब्लम्स को स्टेडी करना चाहिए। उत्तराखण्ड, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ की बात देश के सामने आई है। आप ऐसा मत कहिये कि यह अलगाव की बात है। द्वारा मजबूत बनाने तथा आदिवासी क्षेत्रों को साटेड उन्हे प्रगति पथ पर लाने में सहूलियत होगी।

If you go on sweeping the problems under the carpet. It is not going to solve the problems.

आप को दि नशनल इन्ट्रेस्ट में उन की प्राबलम्स को देखना चाहिए। हम चाहते हैं कि देश के टुकड़े न हों। नये प्रान्त बनाने से देश के टुकड़े नहीं हो रहे है। अगर गुजरात अलग बन सकता है पंजाब बन सकता है तो झारखन्ड, उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ, क्यों नहीं बन सकता, इस से देश के टुकड़े नहीं हुए पर जब वे अलग प्रान्त मांगते है तो आप कहते हैं कि ये फिसीपेरेस टेन्डेन्सी है। इन गरीब आदमियों को हजारों साल से दबाया गया है और जब ये कुछ कहते है तो इनको आप इन्हें अलगाववादी या राष्ट्रद्रोही कहते हैं। आप ने अंग्रेजों से हिन्दुस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन संभाला है। मैं आपकी पार्टी का नहीं हूं फिर भी मैं आपसे चाहूंगा कि जरा इसको आप गंभीरता-पूर्वक विचार कीजिये। अपनी पुरानी नीति को बदल कर नये दृष्टिकोण अपना कर आदिवासी क्षेत्रों में उठते हुए नेशनललिस्ट के प्रश्नों को सुलझाने के लिये झारखण्ड आदि नये प्रान्तों का गठन कीजिये। डरा कर या धमका कर के आप आदिवासियों की प्राबलम सोल्व नहीं कर सकते है। मैं चाहूंगा कि आप आदिवासियों की प्राबलम को सिम्पेथेटिकल्लो विचार कर सोल्व करें।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. S. B. Sidnal will be the last speaker. You will be given only three or four minutes. And then the discussion will be over.

SHRI S. B. SIDNAL (Belgaum): Even one minute will be enough.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are so many demands that are coming up. The others may speak on

them. Since your party members have already spoken, I cannot accommodate the rest.

Now, Mr. Sidnal.

SHRI S. B. SIDNAL (Belgaum): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the Demands for Grants for the Ministry of Home Affairs.

I would first like to discuss the point on the political sufferers, that is, about the freedom fighters. The State Minister has already stated that he has already granted pension to 1.80 lakhs of persons and the rest are refused. (*Interruptions*)

I want to draw your attention to a document. It says that the M.L.A., M.L.C or M.P. who lived as a co-prisoner for the moment has to give a certificate which is of necessity. But all of them are dead. If we ask for the documents, they cannot be produced. There are hardly a few who live and that they too are old and they may die in five, six or two years. That is why I suggest to Government that they should be asked only to produce a co-prisoner's certificate and not the co-prisoner who was an M.L.A., M.L.C. or M.P.

In our district, Belgaum, they are not available. For want of documents their pension has been subpended. Our Minister stated that there are bogus freedom fighters whose pensions had been stopped. They may be 5 or 6 per cent. Sir, you know that under the Indian Evidence Act, ten may be accused, but even one innocent should not be punished. In the same way, even one innocent freedom fighter should not be punished by not granting him the pension. I request the Home Minister to grant them the pension with a local enquiry with a certificate from a co-prisoner who lived with him. Suppose a man has not got a birth certificate. He may file an affidavit in the court. That is taken for granted in a court of law. Similarly, when a co-prisoner files an affidavit that 'X' was living with him as a prisoner at that moment why not that be taken? Otherwise also among the political sufferers, may be 5 to 10 per cent may be bogus. Even that can be scanned properly with the vigilance of our government machinery.

Lastly much has been said. I do not want to repeat anything. But only in regard to atrocities and repeated rapes and repeated dacoities committed in this country it is not out of any political reason or motivation but it is because of economic disparity that we have had so far. If we study the situation all over the world, in China even before Mao came the same thing was prevailing in China—there was economic disparity there; there was educational disparity there and there was social disparity prevailing in China. Such blunders in the society are still there. They cannot be rooted out. But, we can reduce them to the maximum level by the efficiency of our officers. By way of a suggestion, I would like to state that there should be increase of police force; there should be more of them especially in harijans and adivasi areas. There the officers of the same community must be posted to reduce such atrocities. In my district there was one district judge from the scheduled caste community and, during his regime, for three years, there were no atrocities committed. Only they feared that they might go and report. Even they did not know who is the person belonging to scheduled caste or scheduled tribe. I think it will help the morale of the people if this is done.

They will not commit atrocities because there is some man to ask them. So, my suggestion would be that District Judge, Deputy Commissioner and Superintendant of Police must be of the same community where more atrocities are committed on the poor harijans. It is high time that we take recourse to it and redress it

Lastly, Sir, the IPS and CrPC should be amended. A cheat who is a standing danger to society is awarded very little punishment whereas a murderer who has committed a murder and has only one personal enemy is given capital punishment. Sir, murderer has only one enemy whereas a cheat is enemy to the whole society. He should be given more punishment. For instance, five persons died due to consumption of spurious liquor. The man behind this illicit liquor should be awarded capital punishment.

Sir, I thank you for having given me the opportunity to speak

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri): Mr. Deputy Speaker, Sir, I may be allowed to say only one sentence.

Now that there is no time to speak I would request the hon'ble Minister in his reply to make a mention about the solution of the Maharashtra-Karnataka problem which is a burning issue for the last so many years.

MR. DEPUTY SPEAKER: Now, the discussion on the Demands for Grants under the control of the Minintry of Home Affairs is over. Tor ow the hon'ble Minister will reply. The House stands adjourned till 11 a.m. tomorrow.

21.12 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, July 22, 1980/Asadha 31, 1902 (Saka).